चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

भाजपा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ढोंग

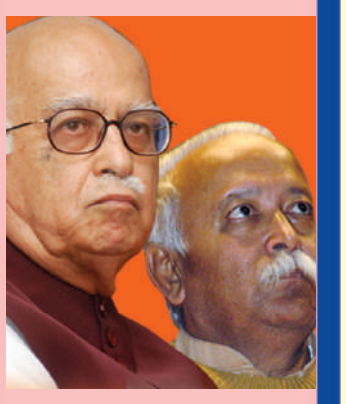

पेज 2

चिदंबरम को सिविल सोसाइटी का जवाब

पेज 3

राहुल के सामने चुनौतियों का पहाड़

पेज 5

साई की महिमा

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 31 मई-6 जून 2010

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सोनिया गांधी इस घोटाले में शामिल नहीं हैं !

नीरा राडिया

फोटो–*इंडिया टुडे इमेज के सौजन्य से*

2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के घोटाले के पर्दाफाश ने देश के नामचीन पत्रकारों, नौकरशाहों, राजनेताओं और बड़े पूंजीपतियों के दोयम चरित्र को बेनकाब कर दिया है. साफ हो चुका है कि भारत के मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि सत्ता के दलाल करते हैं. फिर भी राष्ट्रीय मीडिया और विपक्षी पार्टियों ने खामोशी अख्तियार कर रखी है, क्योंकि संचार मंत्री ए राजा और उनकी सखी नीरा राडिया के घोटालों में सबके हाथ काले हैं.

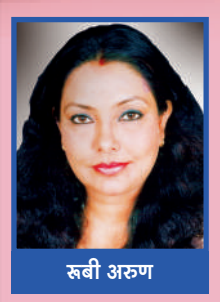

रूबी अरुण

चौसठ हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला करने के बाद भी संचार मंत्री ए राजा बड़े ठाठ से अपने पद पर क्या इसलिए रहे, क्योंकि उनके रिश्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मधुर हैं? जनता दल अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि 2 जी स्पेक्ट्रम सौदे में सोनिया गांधी के केमैन आइलैंड स्थित बैंक ऑफ अमेरिका के खाते में करोड़ों डॉलर की एंट्री हुई है और इसके तमाम काग़ज़ात उनके पास मौजूद हैं. बहरहाल, क्या भाजपा इस मसले पर इसलिए ख़ामोश है, क्योंकि नैनो कार के प्लांट को गुजरात में स्थापित करने में ए राजा की ख़ासमख़ास दोस्त नीरा राडिया ने अहम भूमिका निभाई थी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राज्य के औद्योगिक विकास और राज्य में पूंजी निवेश का यह बेहतरीन मौक़ा था. या फिर वजह यह है कि ए राजा ने भाजपा के ख़ासमख़ास, मुंबई में डीबी रियलिटी एवं अवश्या नाम की कंपनी के ज़रिए रियल स्टेट का धंधा करने वाले और यूनीटेक वायरलेस के मालिक शाहीद बलवा को नियमों के ख़िलाफ़ जा कर 2 जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे दिया गया, जिससे उसने नार्वे की कंपनी से 1661 करोड़ रुपये के एवज में 6200 करोड़ रुपये कमाए. या इसलिए कि जब ए राजा पर्यावरण मंत्री थे, तब उन्होंने बेजा तरीक़ों से रेड्डी बंधुओं की कई ग़ैर क़ानूनी खानों को क्लीयरेंस सर्टीफिकेट दे दिए थे. या फिर दलाल नीरा राडिया से अपने दिग्गज नेता अनंत कुमार की गहरी नज़दीकियों के कारण भाजपा ने अपनी ज़ुबान पर ताले जड़ लिए हैं. अनंत कुमार जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तब सुपर दलाल नीरा राडिया मैज़िक एयर के नाम से अपना एयरलाइंस शुरू करना चाहती थीं और वह भी महज़ एक लाख रुपये में. नीरा राडिया के दीवाने अनंत कुमार ने नीरा के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मसले की नज़ाकत समझी और उन्होंने अनंत कुमार के उत्साह पर पानी फेरते हुए नीरा के प्रस्ताव पर विचार करने तक से मना कर दिया. ख़ैर, कांग्रेस को घेरने के जोश के अतिरेक में भाजपा नेता अरुण जेटली ने संसद में इस मुद्दे को उछाल तो दिया, पर जब भाजपा नेतृत्व को लगा कि इस कीचड़ में उनका दामन भी दागदार होना है तो भाजपा नेताओं ने चुप बैठ जाना ही मुनासिब समझा. आज की तारीख़ में आप किसी भी भाजपा नेता से पूछ लीजिए, वह सुपर कॉरपोरेट दलाल नीरा राडिया को नहीं जानता. यहां तक कि संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले अरुण जेटली भी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ़ घोटाले की जानकारी है, नीरा राडिया क्या बला है, उन्हें नहीं पता. वैसे तो सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने भी 29 फरवरी 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर संचार मंत्री ए राजा द्वारा 2 जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस जारी करने संबंधी निर्देशों को ख़ारिज करने को कहा था, क्योंकि वे निर्देश नियमों के विरुद्ध दिए गए थे और सीताराम येचुरी को यह अंदेशा था कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली की गई है. पर जैसे ही राजा के साथ नीरा राडिया का नाम उछला और नीरा की फोन टैपिंग के रिकॉर्ड आम हुए, सीपीआई और सीपीएम नेताओं को भी मानो सांप सूंघ गया, क्योंकि आज की तारीख़ में वामपंथियों के सबसे बड़े नेता प्रकाश करात ने नीरा राडिया के कहने पर ही हल्दिया पेट्रोकेमिकल सौदे में रिलायंस की मदद की थी. यह बात भी साफ हो गई कि नीरा के कई महत्वपूर्ण एवं बड़े वामपंथी और सीटू नेताओं से क़रीबी संबंध रहे हैं. इसके अलावा नीरा राडिया उन तमाम औद्योगिक घरानों के लिए दलाली का काम करती रही है, जिनसे सीपीआई-सीपीएम का साबका किसी न किसी बहाने पड़ता रहा है. आज जब सीताराम येचुरी से यह पूछा जाता है कि क्यों नहीं वे लोग ए राजा के ख़िलाफ़ लामबंद हो रहे और नीरा राडिया की अविलंब गिरफ़्तारी की मांग सरकार से करते, तो वह मीठी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं कि उन्होंने तो बहुत पहले ही 2 जी स्पेक्ट्रम में हो रहे घोटालों के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. हां, नीरा राडिया कौन है, इसकी विशेष जानकारी उन्हें नहीं. ख़बरों की मार्फत ही उन्हें यह पता चल पाया है.

वहीं सीपीएम के बुज़ुर्ग नेता ए बी वर्धन यह सवाल सुनते ही भड़क उठते हैं कि क्या उन्हें नीरा राडिया के बारे में पता है? नाराज़गी भरे लहजे में वह कहते हैं कि देश में ग़रीब जनता से जुड़ी इतनी समस्याएं हैं और आप हैं कि नीरा राडिया की चिंता में दुबली हुई जा रही हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तो नीरा राडिया के नाम पर बात करने को तो क्या, मिलने तक को राजी नहीं होते. गोया, जैसे उन्होंने अगर इस मसले पर अपना मुंह खोल लिया तो गुनाह हो जाएगा. राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की चुप्पी भी ज़हन में कई सवाल खड़े करती है. सबकी ख़बर रखने वाले और हर किसी की दुखती रग पर हाथ रखने को हमेशा तैयार रहने वाले लालू प्रसाद भी नीरा राडिया से उतने ही अनभिज्ञ हैं, जितने कि उनके दूसरे सियासी साथी. नीरा का नाम सुनकर लालू यादव घूर कर देखते हैं और अपनी नज़रें फिरा लेते हैं.

कौन है नीरा राडिया? यह सुनते ही जनता दल अध्यक्ष शरद यादव की पहले से ख़राब चल रही तबियत कुछ और बिगड़ जाती है. वह कहते हैं कि इस बारे में वह कभी बाद में बातें करेंगे. फ़िलहाल तो वह अस्पताल जा रहे हैं. जबकि सच यही है कि इन सभी को मालूम है कि नीरा राडिया कौन है और न सिर्फ़ ए राजा, बल्कि अन्य कई रसूखदार नेताओं के साथ नीरा की जुगलबंदी का राज क्या है? पर मसला यह कि दल और जमात से इतर सभी नेताओं के पेंच कॉरपोरेट मामलों की दलाली के मामलों में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं या सीधे तौर पर यह कह लें कि दलाली के इस हमाम में सभी नंगे हैं. लिहाज़ा ज़ुबान खोलना ख़ुद के लिए ही ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए सभी चुप हैं. और तो और, बड़े पत्रकार कहे जाने वाले बरखा दत्त और वीर सांघवी के नामों की चर्चा करते हुए भी इन दिग्गज नेताओं की ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है. जिन औद्योगिक घरानों के लिए नीरा दलाली का काम करती रही है. वे सभी घराने देश की सभी बड़ी पार्टियों से जुड़े हैं. सभी जानते हैं कि टाटा, अंबानी, मित्तल जैसे पूंजीपति ही इन दलों की आर्थिक रीढ़ हैं. पार्टियों के रोज़ाना ख़र्चे से लेकर चुनाव तक का भार ये कुबेर उठाते ही इसलिए हैं कि उनके पोषित दल सत्ता के साझीदार बनें तो उनके सारे जायज़-नाजायज़ काम बग़ैर नियम-क़ानून के धड़ल्ले से हो सकें. तो चूंकि हाथ सबके काले हैं तो अब कौन किसके चेहरे पर कालिख़ मले?

ये बरखा दत्त और वीर सांघवी की टीआरपी ही है, जो कोई भी इनके ख़िलाफ़ मुंह खोलने को तैयार नहीं. पायोनियर, द हिंदू, मिड डे जैसे अख़बार और मीडिया पोर्टल भड़ास फॉर मीडिया की बात छोड़ दें तो दूसरे किसी भी अख़बार ने इस मुद्दे पर सुगबुगाहट तक नहीं दिखाई है. छोटी से छोटी ख़बरों को तान देने वाले न्यूज़ चैनल तो जैसे अंधे-बहरे बने बैठे हैं. शशि थरूर, लालू यादव, मायावती, बंगारू लक्ष्मण आदि के मसलों पर हफ्तों चीखने वाले न्यूज़ चैनलों को कुछ भी दिखाई-सुनाई नहीं दे रहा है. ये उनकी आर्थिक मजबूरी है या यह डर कि उनके चैनलों के नामचीन पत्रकार भी चैनलों के हितार्थ कहीं न कहीं दलाली का प्रपंच रच रहे हैं. सभी अपनी-अपनी टीआरपी भुना रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो बेहद घाटे में चल रहा एनडीटीवी का व्यवसायिक घाटा एक साल में ही इतना कम नहीं हो गया होता. यह नीरा राडिया और बरखा के मैनेजमेंट का ही कमाल है, जिसके तहत हाई प्रोफाइल इंटरव्यू किए गए और खुलेआम उन लोगों की इमेज मेकिंग का काम किया गया. ऐसे में एनडीटीवी प्रबंधन तो बरखा के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकता. सरकार भी कोई कार्रवाई करने की नहीं सोच सकती. सत्ता के गलियारे में प्रियंका गांधी, जयंती नटराजन, पी चिदंबरम, शशि थरूर से लेकर फारुख अब्दुल्ला तक से बरखा की गहरी छनती है. फारुख अब्दुल्ला तो बरखा के इतने मुरीद हैं कि हाल ही में एनडीटीवी के एक टॉक शो में उन्होंने एंकर बरखा से ऑन एयर बड़े ही शायराना अंदाज़ से कहा कि बरखा, हमारे-तुम्हारे रिश्तों की चर्चा तो संसद के गलियारों तक हुई है. बरखा की सियासी दबंगई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एडमिरल सुरीश मेहता ने कारगिल युद्ध के दौरान बरखा को तीन जवानों की हत्या का दोषी माना था. बरखा कारगिल का लाइव कवरेज कर रही थी. इस दरम्यान वह अपनी ख़बरों को पुख्ता बनाने और सनसनी फैलाने की गरज से भारतीय जवानों की सही पोज़ीशन का भी ज़िक्र कर रही थी. मोर्चे पर तैनात जवान बार-बार बरखा को ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर बरखा नहीं मानी. सुरीश मेहता ने 4 दिसंबर 2008 को नेवी डे के मौक़े पर पत्रकारों से यह बात कही कि ग़ैर ज़िम्मेदाराना कवरेज की वजह से तीन जवानों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी. पाकिस्तानी सैनिकों ने बरखा के बताए ठिकाने को ट्रेस कर भारतीय जवानों की जान ले ली. हालांकि एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय ने सुरीश मेहता की बात को सरासर बेबुनियाद बताया था. एडमिरल मेहता आज भी अपनी बात पर कायम हैं.

वीर सांघवी तो ख़ैर ख़ुद राज्यसभा सदस्य बनते-बनते रह गए, पर उन्होंने सत्ता की जोड़-तोड़ में महारत हासिल कर ली. वह न सिर्फ़ भारत के राजनीतिज्ञों पर, बल्कि विदेशी सियासत में भी खासी दख़ल रखते हैं. क़ानूनी तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए मशहूर थाइलैंड सरीखे देश के प्रधानमंत्री ने वीर को द फ्रेंड ऑफ थाइलैंड अवार्ड से सम्मानित किया है. अरबपतियों से ख़ातिरदारी कराने में वीर सांघवी पुराने माहिर हैं. वह टाटा समूह के आलीशान होटलों में ठहरते हैं तो उनकी विमान यात्राओं का बिल अंबानी भरते हैं. ज़ाहिर है, इन सबके एवज में वीर सांघवी सरकारी गलियारे में नीरा राडिया जैसी दलालों की बैसाखी बन अपनी पत्रकारिता की बोली लगाते हैं.

जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में ही जब ए राजा पर ढेरों आरोप लगे थे, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दोबारा संचार मंत्री बनाया गया. तो इसका साफ मतलब है कि इसमें सोनिया गांधी की सहमति थी. और अगर ऐसा नहीं था तो इसका आशय यह है कि यूपीए सरकार में मंत्री सत्ता के दलाल बनाते हैं, न कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह. 29 नवंबर 2008 को सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा के ख़िलाफ़ तमाम सबूत सौंपते हुए पत्र लिखा कि ए राजा को मंत्रिमंडल से फौरन हटा दिया जाए, क्योंकि वह लगातार घोटाले कर रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. 31 अक्टूबर 2009, 8 मार्च और 13 मार्च 2010 को सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से मनमोहन सिंह के नाम चिट्ठियां लिखीं, तब 19 मार्च 2010 को स्वामी के पास केंद्र का जवाब आया कि राजा को कैबिनेट से हटाने या उन पर मुक़दमा चलाने का फ़ैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी जांच चल रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं. आख़िरकार 12 अप्रैल 2010 को स्वामी ने अदालत में इस सिलसिले में अपनी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कौन है नीरा राडिया? यह सुनते ही जनता दल अध्यक्ष शरद यादव की पहले से ख़राब चल रही तबियत कुछ और बिगड़ जाती है. वह कहते हैं कि इस बारे में वह कभी बाद में बातें करेंगे. फ़िलहाल तो वह अस्पताल जा रहे हैं. जबकि सच यही है कि इन सभी को मालूम है कि नीरा राडिया कौन है और न सिर्फ़ ए राजा, बल्कि अन्य कई रसूखदार नेताओं के साथ नीरा की जुगलबंदी का राज क्या है? पर मसला यह कि दल और जमात से इतर सभी नेताओं के पेंच कॉरपोरेट मामलों की दलाली के मामलों में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं या सीधे तौर पर यह कह लें कि दलाली के इस हमाम में सभी नंगे हैं.

ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही देश की अकेली ऐसी पार्टी है, जिसमें भ्रष्ट एवं बेईमान नेता पाए जाते हों.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सरकार की भूल सुधार

सरकार अपनी एक पुरानी गलती को सुधारने के लिए गंभीरता से प्रयास करने का मन बना रही है. इस सरकारी कार्रवाई से कई नौकरशाहों के प्रमोशन की संभावना को ग्रहण लग गया था. हाल के दिनों में ज्वाइंट सेक्रेट्री स्तर के कम से कम पचास बाबुओं के प्रमोशन की दौड़ में पीछे छूटने और उन्हें कनिष्ठ अधिकारियों के मातहत काम करने को मजबूर होने के बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की शरण में जाना पड़ा था. इसकी एकमात्र वजह यह थी कि वे अपनी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) को नहीं देख सकते थे.

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि यदि विभागीय प्रमोशन कमेटी प्रमोशन के लिए किसी नौकरशाह के नाम पर विचार करती है, लेकिन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर वह वांछित योग्यता हासिल नहीं कर पाता है, तो संबद्ध अधिकारी को अपने एसीआर की एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और पंद्रह दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने का मौका उसके पास होगा. कार्मिक सचिव शांतनु कंसुल के अनुसार, इस निर्णय से प्रमोशन से वंचित किए गए अधिकारियों को अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर विभागीय प्रमोशन कमेटी के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रखने में मदद मिलेगी. अब तक हो यह रहा था कि सरकार विभागीय प्रमोशन कमेटी के विचार के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास अच्छी

ग्रेडिंग वाली एसीआर ही भेजा करती थी.

सरकार के इस निर्णय से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारियों ने भी अपनी प्रमोशन पॉलिसी पर फिर से विचार करने का फैसला किया है. सेना प्रमुख वी के सिंह ने अलग–अलग विभागों से मिले फीडबैक के आधार पर पिछले साल लागू की गई प्रमोशन पॉलिसी पर पुनर्विचार का आदेश दिया है. कहा जा रहा है कि नई प्रमोशन पॉलिसी कनिष्ठ अधिकारियों के लिहाज से अच्छी है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के मुफीद नहीं है.

भ्रष्टाचार पर वार

वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ आयकर विभाग के छापों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्रियों और आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्तियों की ऑनलाइन घोषणा करने का आदेश दिया है. अब महाराष्ट्र सरकार भी मध्य प्रदेश के नक्शेकदम पर चल पड़ी है. माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय एक ताजा सर्वे के परिणामों पर आधारित है. सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य नौकरशाही की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है. इस बीच केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने दिल्ली में बताया कि वर्तमान समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 84 और पुलिस सेवा के 33 अधिकारियों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं.

उम्मीदों के मुताबिक ही महाराष्ट्र के नौकरशाह राज्य सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं. उनका तर्क है कि यदि उन्हें अपनी संपत्तियों की घोषणा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसके लिए पहले ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में बदलाव करना होगा. उनका यह भी मानना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिज्ञों का दिमाग काम कर रहा है, जो यह साबित करना चाहते हैं कि नौकरशाह राजनीतिज्ञों से कहीं ज्यादा भ्रष्ट हैं.

इस बीच खबर यह भी है कि राज्य सरकार नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक कमेटी के गठन का विचार कर रही है, जिसमें अन्ना हजारे, अभय बंग, प्रकाश आम्टे जैसे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व नौकरशाहों को शामिल किया जा सकता है. इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्ट अधिकारी सरकार के निशाने पर हैं.

dilipcherian@chauthiduniya.com

सोनिया गांधी इस घोटाले में शामिल नहीं हैं!

पृष्ठ 1 का शेष

याचिका दाख़िल की. अदालत ने उनकी अपील मान ली है. स्वामी की याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी.

लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को इस महाघोटाले के बाबत कोई जानकारी नहीं थी. नीरा राडिया और राजा के बीच बातचीत के टेपों के आधार पर आयकर विभाग ने सरकार को अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट जुलाई 2009 में ही सौंप दी थी. सरकार इस काले धंधे की हक़ीक़त से वाक़िफ़ हो चुकी थी. फिर भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि इस खेल में अगर नीरा राडिया नायिका के तौर पर भूमिका निभा रही थी तो कांग्रेस के कई कद्दावर नेता नीरा के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे. सरकार की नीतियों और नियमों को प्रभावित करने वाले कॉरपोरेट जगत के एक मज़बूत हिस्से जैसे टाटा, अंबानी, वेदांता, सहारा एयरलाइंस, रेमंड, सीआईआई, डीबी, यूनीटेक, स्टार न्यूज़, एनडीटीवी, नई दुनिया, न्यूज़ एक्स आदि नीरा राडिया की गोद में खेल रहे थे. नीरा की कंपनियों में भारत सरकार के दिग्गज नौकरशाह रह चुके पूर्व ऊर्जा सचिव और ट्राई अध्यक्ष प्रदीप बैजल, पूर्व वित्त सचिव सी एम वासुदेव, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन एस के नरुला, फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अजय दुआ वग़ैरह सलाहकार और निदेशक के तौर पर नीरा के जरख़रीद बन कर उसका हुक्म बजा रहे हैं. ज़ाहिर सी बात है, नीरा राडिया महज़ एक दलाल होते हुए भी इतनी मज़बूत है कि सरकार अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो यह उसके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने सरीखा होगा. यही वजह है कि मामले की जांच करने वाले सीबीआई डीआईजी विनीत अग्रवाल ने जब सरकार से दोषियों पर मुक़दमा चलाने की इजाज़त मांगी तो उनका तबादला कर वापस उनके होम काडर भेज दिया गया.

सोचिए ज़रा, आईपीएल विवाद में शशि थरूर और उनकी मित्र सुनंदा पुष्कर की क्या फ़ज़ीहत हुई. राहुल गांधी के ख़ास होने के बावजूद शशि का मंत्रालय उनके हाथ से निकल गया. साठ करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ और देश की सरकार बदल गई. पर 60 हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद भी संचार मंत्री ए राजा न सिर्फ़ अपने पद पर बने हुए हैं, बल्कि उनकी चहेती नीरा राडिया अपना सारा माल समेट कर लंदन में ऐश कर रही है. और तो और, भारत में उसकी सभी पीआर कंपनियां अपना काम पहले की तरह ही ठाठ से कर रही हैं, पर सरकार चुप है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ख़ामोश हैं. भारतीय युवाओं को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले और विरोधियों की ख़ामियों पर धारदार हमला बोलने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी मूकदर्शक की भूमिका में हैं. क्या वाकई नीरा राडिया के रिश्ते सोनिया गांधी से घनिष्ठता भरे हैं? क्योंकि नीरा राडिया तो यही प्रचारित कर रही है. यक़ीनन, ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी को चाहिए कि वह साबित करें कि उनका नीरा राडिया और इस घोटाले से कोई संबंध नहीं है और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं तथा इसकी शुरुआत तत्काल इस पूरे मामले की गंभीर जांच की घोषणा से हो.

ruby@chauthiduniya.com

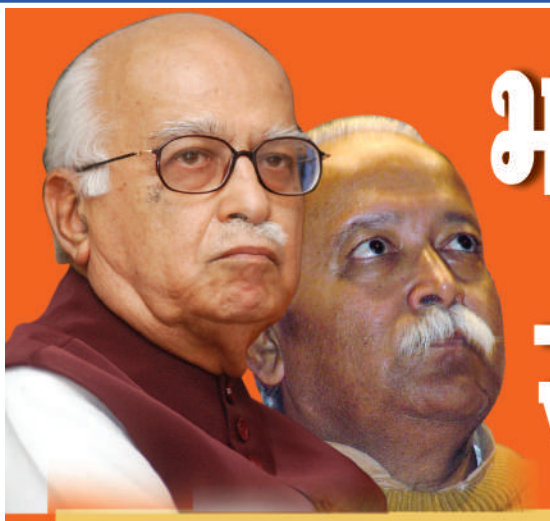

भाजपा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ढोंग

निर्मल रानी

नितिन गडकरी को जब राजनाथ सिंह के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, उसी समय दो बातें बिलकुल स्पष्ट हो गई थीं. एक तो यह कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी ऐसे नेता को भाजपा प्रमुख के पद पर आसीन करना चाहता था, जो संघ की पृष्ठभूमि का हो और संघ एवं उसकी नीतियों के प्रति वफादार रहे. लिहाज़ा संघ के रणनीतिकारों की नज़र नितिन गडकरी पर जा टिकी. भाजपा अध्यक्ष बनने से पूर्व गडकरी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले नेता हरगिज नहीं थे. दूसरी बात यह कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एवं राजनाथ के बाद गडकरी जैसे प्रदेश स्तर के नेता को भाजपा की राष्ट्रीय कमान सौंप दी गई. यहीं पर यह ग़ौर करना ज़रूरी है कि यदि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे अधिक ढिंढोरा पीटने वाला कोई संगठन है तो वह आरएसएस और भाजपा है.

अब ग़ौर कीजिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजावाहक गडकरी द्वारा गत दिनों चंडीगढ़ की सार्वजनिक सभा में दिए गए उस भाषण को, जिसने एक बार फिर यह एहसास करा दिया कि भाजपा वास्तव में पार्टी विद ए डिफरेंस है. गडकरी ने फरमाया कि लालू यादव एवं मुलायम सिंह यादव शेर की तरह गुर्राते हैं, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर जाकर... उनके तलवे चाटते हैं. गडकरी के भाषण के इस बेहूदे अंश को लेकर मीडिया ने उन्हें आईना दिखाना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, देश यह देख ले. कुछ ही देर बाद गडकरी को संभवत: अपनी गलती का एहसास हो गया और इससे पहले कि तमाम टीवी चैनल गडकरी की शान में कसीदे पढ़ने में मशगूल हो जाते, उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए झटपट माफी मांग ली. उनके माफी मांगने के बावजूद देश को यह पता लग गया कि गडकरी के नेतृत्व में भाजपा आने वाले समय में किस स्तर तक जा सकती है और इस पार्टी में पहले से ही मौजूद फायर ब्रांड नेता आगे चलकर और कैसी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं.

अटल बिहारी वाजपेयी, भैरो सिंह शेखावत, लालकृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी आदि वे नाम हैं, जिनके बलबूते भाजपा स्वयं को अनुशासित एवं पार्टी विद ए डिफरेंस होने का दावा करती थी. पर जैसे–जैसे इन नेताओं के हाथों से निकल कर पार्टी का नेतृत्व दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाने लगा, वैसे–वैसे भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दावा खोखला पड़ता नज़र आने लगा. कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके बंगारू लक्ष्मण रिश्वत में मिलने वाले नोटों के बंडल गिनते हुए खुफ़िया कैमरे के सामने रंगे हाथों पकड़े गए तो कभी वाजपेयी मंत्रिमंडल में रहे केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव रुपये की तुलना खुदा से करते पाए गए. पार्टी में कई और भी नेता हैं, जिन पर संसद में प्रश्न पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप लग चुका है और उन पर कार्रवाई भी हो चुकी है. यानी इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहले भी कई बार बेनक़ाब हो चुका है.

ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही देश की अकेली ऐसी पार्टी है, जिसमें भ्रष्ट एवं बेईमान नेता पाए जाते हों. संभव है, इससे भी अधिक भ्रष्ट और बदज़ुबान नेता अन्य पार्टियों भी हों, लेकिन कोई अन्य राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा ढोल नहीं पीटता, जैसा भाजपा के नेताओं द्वारा पीटा जाता है. एक सत्य यह भी है कि गडकरी जैसी बदज़ुबानी और बंगारू जैसी रिश्वतखोरी के जीते–जागते प्रमाण फिलहाल अभी तक किसी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों के विरुद्ध नहीं देखे गए. बात जब भाजपा नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा शैली की चल पड़ी है तो एक बार फिर याद दिला दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्वयं को कभी सरदार पटेल का वारिस बताने की कोशिश करते हैं तो कभी खुद में देश का प्रधानमंत्री बनने की संभावना तलाश करने लगते हैं, द्वारा भी कभी– कभी ऐसी भाषा शैली का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है कि पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दावा महज़ एक ढोंग दिखाई देने लगता है.

दरअसल भाजपा में नेतृत्व का अकाल तो उसी समय महसूस होने लगा था, जबकि वेंकैया नायडू और उसके बाद राजनाथ सिंह जैसे दूसरी श्रेणी के नेताओं के हाथों में पार्टी की बागडोर सौंपे जाने का दौर शुरू हुआ था.

याद कीजिए, एक बार नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के विषय में कहा था कि उन्हें रहने के लिए कोई अपना मकान भी किराए पर नहीं देगा. स्वयं को रामराज्य का रहबर और सोनिया गांधी को रोमराज्य का प्रतीक तो मोदी प्राय: कहते ही रहते हैं. मोदी ने ही राहुल गांधी के विषय में एक बार टिप्पणी की थी कि राहुल को तो कोई अपनी कार का ड्राइवर भी नहीं रखेगा. ग़ौर फरमाइए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के ऐसे राजनीतिक आकलन. यहां यह बताने की ज़रूरत नहीं कि इन टिप्पणियों और नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों के बावजूद, जिन्हें वह पूरा जोर लगाकर गुजरात में कर रहे हैं, आज सोनिया गांधी पर जनता द्वारा कितना विश्वास किया जा रहा है. जबकि रामराज्य के मोदी सरीखे ध्वजावाहक को अभी कुछ समय पहले एसआईटी द्वारा दो दिनों तक लगातार गुजरात दंगों के सिलसिले में पूछताछ हेतु अपने कार्यालय में बुलाया जा चुका है. वैसे भी मोदी स्वयं को कितना भी बड़ा क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त, हिंदुत्व का अलमबरदार और भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पहरेदार क्यों न बताते फिरें, परंतु वास्तविकता यही है कि इस समय देश के सबसे विवादित मुख्यमंत्री वही हैं. इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरेंद्र मोदी के विषय में की गई उस टिप्पणी से हो जाती है, जिसमें गुजरात दंगों के सिलसिले में मोदी को गुजरात का नीरो बताया गया था.

दरअसल भाजपा में नेतृत्व का अकाल तो उसी समय महसूस होने लगा था, जबकि वेंकैया नायडू और उसके बाद राजनाथ सिंह जैसे दूसरी श्रेणी के नेताओं के हाथों में पार्टी की बागडोर सौंपे जाने का दौर शुरू हुआ था. वेंकैया नायडू ने अपनी वाकपटुता एवं हिंदी बोलने के अपने लोकप्रिय अंदाज़ से देश की जनता को जबरदस्ती इंडिया शाइनिंग हज़म करवाने का प्रयास किया था. उसके पश्चात जिस प्रकार राजनाथ सिंह एवं अरुण जेटली के मध्य रस्साकशी चली और बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजनाथ सिंह को उनकी राजनीतिक हैसियत की पहचान कराई, उससे भी यह अंदाज़ा होने लगा था कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है. रही–सही कसर भैरो सिंह शेखावत के बयान ने पूरी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, जबसे मैं राजनीति कर रहा हूं. गत लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी द्वारा सांप्रदायिकतापूर्ण ज़हरीला भाषण दिया गया और उसे तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा समर्थन दिया गया. बल्कि राजनाथ सिंह ने एटा (उत्तर प्रदेश) की जेल में जाकर वरुण से मुलाकात करके कुछ विशेष संदेश देने की भी कोशिश की.

इन कदमों से स्पष्ट होने लगा था कि भाजपा अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कथित सिद्धांतों से दूर होती जा रही है और पार्टी विद ए डिफरेंस का नारा बेमानी साबित होता जा रहा है. लिहाजा नितिन गडकरी द्वारा चंडीगढ़ में सार्वजनिक रूप से कहे जाने वाले अपशब्दों को गंभीरता से लेने के बजाय यह समझ लेना चाहिए कि न केवल भाजपा, बल्कि इसे पिछले दरवाज़े से निर्देश जारी करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ स्वयंसेवकों का वास्तविक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या. कहा जा सकता है कि भाजपा नेता अब अपनी उपलब्धियां एवं गुण जनता को बताने के बजाय दूसरों को अपमानित करने और दूसरे नेताओं के विरोध में अपनी बढ़त तलाश कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 12
दिल्ली, 31 मई–6 जून 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नक्सलवाद का प्रभाव उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है, जहां खनिज अयस्क प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं? इन खनिज तत्वों पर भारत के आम नागरिकों का हक़ बनता है.

चिदंबरम को सिविल सोसाइटी का जवाब

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

> आपको आख़िर हो क्या गया है चिदंबरम साहब, आप तो भले इंसान हुआ करते थे. फेयरग्रोथ मामले में दोषी न होने के बावजूद आपने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. जीवन का मतलब चंद पैसों के एवज़ में अदालतों में जिरह करना नहीं है. इसका वास्तविक मतलब तो उसके पक्ष में तर्क देने से है, जो सही है.

प्रिय श्री चिदंबरम,

यह आपके उन बयानों के जवाब में है, जो आपने एनडीटीवी पर अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था. इंटरव्यू में आपने कहा था कि समाज को नक्सलवादियों की अनावश्यक मारकाट का प्रतिकार करना चाहिए. ऐसा लगता है, जैसे यह एक सुनियोजित इंटरव्यू था, जिसका उद्देश्य माओवादियों से मुक़ाबले हेतु सुरक्षाबलों और वायुसेना के ज़्यादा इस्तेमाल के लिए कैबिनेट की सहमति हासिल करना था. अरुण जेटली के अप्रत्यक्ष समर्थन, अब चाहे इसके लिए उन्होंने आपको घायल शहीद ही क्यों न कहा हो, का असल मक़सद भी यही था और वह भाजपा शासित राज्यों के खान मालिकों के हितों को ध्यान में रखकर बोल रहे थे. समाज का एक सदस्य होने की हैसियत से मेरा यह मानना है कि निर्दोष आदिवासियों के ख़िलाफ़ आपके तीखे रवैये से मैं असहमत हो सकता हूं. यह भी उम्मीद करता हूं कि यदि मैं आपसे यह कहूं कि नक्सलवाद के उदय और उसके विकास के लिए आप भी ज़िम्मेदार हैं, तो आप ज़्यादा आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि नक्सलवाद के उदय के दौर में आप देश के वित्त मंत्री थे.

क्या यह सही नहीं है कि पिछले दस सालों में तेज़ी से विकसित होकर नक्सलवाद आज देश और समाज के लिए एक नासूर बन चुका है? सच तो यह है कि एनडीटीवी पर अपने इंटरव्यू के दौरान आप ख़ुद भी इस बात को मान चुके हैं. क्या यह सही नहीं है कि नक्सलवाद की लोकप्रियता में इज़ाफ़े के साथ-साथ लौह अयस्कों के खनन से होने वाले लाभ में भी इज़ाफ़ा हुआ है? लौह अयस्कों के खनन में लाभ की दर पहले पचास रुपये प्रति टन थी, जो पिछले दस सालों में बढ़कर पांच हज़ार रुपये प्रति टन से भी ज़्यादा हो चुकी है. क्या यह सही नहीं है कि नक्सलवाद का प्रभाव उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है, जहां खनिज अयस्क प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं? इन खनिज तत्वों पर भारत के आम नागरिकों का हक़ बनता है, लेकिन परस्पर लाभ के उद्देश्य से इन्हें खान मालिकों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया गया है. यह वास्तव में पूंजीवाद का छुपा हुआ रूप है. यही वजह है कि अरुण जेटली आपके सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं, क्योंकि भाजपा शासित चार राज्यों में सरकार का अस्तित्व खान माफ़िया से मिलने वाले पैसे पर ही टिका है.

क्या यह सच नहीं है कि वित्त मंत्री के रूप में आपके साढ़े चार सालों के कार्यकाल के दौरान कॉरपोरेट घरानों ने क़ानूनी और ग़ैरक़ानूनी खनन से दो लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा लाभ की कमाई की? इस मुनाफ़े का बंटवारा कैसे हुआ? क्या यह सही नहीं है कि वित्त मंत्री के रूप में आपके पूरे कार्यकाल के दौरान लौह अयस्क पर रॉयल्टी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह आश्चर्यजनक रूप से सात से सत्ताइस रुपये प्रति टन (लौह अयस्क की गुणवत्ता के आधार पर) और औसत पंद्रह रुपये प्रति टन के निम्न स्तर पर बना रहा? इस रॉयल्टी को न तो एड वेलोरम घोषित किया गया और न ही साल 2000 के बाद इसमें कोई बदलाव किया गया, जबकि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लौह अयस्क की क़ीमतें आसमान छू रही थीं.

क्या यह सच नहीं है कि देश के नागरिक इन खनिज पदार्थों के मालिक हैं? क्या लौह अयस्कों के खनन से होने वाले मुनाफ़े पर 0.5 प्रतिशत की मामूली रॉयल्टी उसके मालिकों के लिए पर्याप्त हर्ज़ाना है? क्या आप अपनी एक करोड़ की संपत्ति पचास हज़ार रुपये में बेचने के लिए राजी होंगे? क्या मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपने देश के संविधान का पालन करने के अपने वचन को पूरा किया है? ख़ासकर संविधान की धारा 39 (बी) और (सी) का, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि देश के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल सार्वजनिक हित में होना चाहिए. यदि खनन से होने वाले मुनाफ़े का पच्चीस प्रतिशत भी खनन क्षेत्रों में रहने वाले ग़रीब और आदिवासियों पर ख़र्च किया गया होता, तो क्या नक्सलवाद की समस्या आज मौजूद होती? जबकि सच्चाई यह है कि इन ग़रीब लोगों की ज़िंदगियां लालची कॉरपोरेट और खान माफ़ियाओं के चलते तबाह हो चुकी हैं और इसमें उन्हें क़ानून एवं नीति निर्माण करने वाले लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला है. लौह अयस्क खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर इसे पीएसयू या एनडीएमसी, जिसके एक रुपये वाले शेयरों को तीन सौ रुपये प्रीमियम पर हाथोंहाथ लिया गया, के हाथों में देने और उससे होने वाले मुनाफ़े को लोगों के हित में इस्तेमाल करने से सरकार को किसने रोका था? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे खनिजों के मामले में धनी और कम जनसंख्या वाले देश में भी खनन से होने वाले मुनाफ़े पर चालीस प्रतिशत टैक्स आरोपित किया जाता है? क्या भारत जैसा ग़रीब देश इतने बड़े मुनाफ़े को यूं ही छोड़ देने की हालत में है?

क्या आप बताएंगे कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से आपने कितनी बार सार्वजनिक हित के मामलों की पैरवी की है? एक पेशेवर वकील के रूप में आपने कितनी बार कॉरपोरेट घरानों का पक्ष लिया है? कॉरपोरेट घरानों के प्रति आपके लगाव को देखते हुए यह सवाल मौजूं है, क्योंकि इन घरानों के हित ग़रीब जनता के हितों से मेल नहीं खाते. यदि समाज यह सोचे कि गृह मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में आप कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करते रहे हैं (पहले उन्हें खनिजों को लूटने की अनुमति देकर और फिर खानों को उनके हाथों में देकर) तो इसमें क्या बुराई है? ऐसा करके आप कम से कम आम लोगों के हितों की सुरक्षा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ग़रीब और आदिवासी जनता तो इन लालची तत्वों और राजनीतिक दलों के छुपे पूंजीवादी रवैये से त्रस्त है. वैसे भी आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आप वेदांता रिसोर्सेज के निदेशकों में शामिल रहे हैं. एनडीटीवी पर इंटरव्यू के दौरान आपने द्विआयामी एप्रोच की चर्चा की थी और यह भी कहा था कि इनमें से एक कमज़ोर पड़ चुका है. कमज़ोर तो विकास की प्रक्रिया पड़ चुकी है और वास्तविकता तो यह है कि यह अब कहीं नज़र भी नहीं आती. रॉयल्टी से प्राप्त होने वाली राशि सुरक्षा ख़र्चे तो दूर, खनन उद्योग के चलते स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल, सड़क, पुनर्वास आदि क्षेत्रों में होने वाले घाटे की भरपाई करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है. क्या यह सच नहीं है कि निर्दोष सुरक्षाकर्मियों एवं आदिवासियों की हो रही हत्याएं खनन उद्योग को कॉरपोरेट घरानों और उनके साथ मिल-बांटकर खाने वाले राजनीतिक दलों के लिए सुरक्षित रखने की नीति का परिणाम हैं? यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि वित्त मंत्री के रूप में अपने पांच साल के कार्यकाल को पूरा न कर पाने से आप निराश हैं. क्या आपके लिए यह मुद्दा कॉरपोरेट घरानों की लूटमार और इसके चलते हो रहे ख़ूनखराबे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है?

> यदि समाज यह सोचे कि गृह मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में आप कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करते रहे हैं (पहले उन्हें खनिजों को लूटने की अनुमति देकर और फिर खानों को उनके हाथों में देकर) तो इसमें क्या बुराई है? ऐसा करके आप कम से कम आम लोगों के हितों की सुरक्षा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ग़रीब और आदिवासी जनता तो इन लालची तत्वों और राजनीतिक दलों के छुपे पूंजीवादी रवैये से त्रस्त है.

यह कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि खनन माफ़िया के पैसे के बल पर अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही राज्य सरकारें वायुसेना के इस्तेमाल के पक्ष में हैं, ताकि खनन उद्योग को हमेशा के लिए सुरक्षित और लाभकारी बनाया जा सके. चुनावों में पैसे की भूमिका से आप वैसे भी अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, क्योंकि आप खुद अपनी जीत सुरक्षित करने में तो कामयाब रहे ही, डीएमके के सांसद भी आसानी से अपनी सीटें बचाने में सफल रहे. राजा तो अपना मंत्रालय तक बचाने में कामयाब रहे. वास्तविकता यह है कि सरकार की विश्वसनीयता ही दांव पर लगी है, क्योंकि वह खनन माफ़िया के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ताक़त का इस्तेमाल कर रही है. इतना ही नहीं, ख़ुद उसके हित भी इन्हीं माफ़ियाओं से जुड़े हैं और खनन माफ़िया की मुनाफ़ाख़ोरी भी उसके छुपे पूंजीवादी रवैये से ही फल-फूल रही है. सरकार को यदि अपनी साख बचानी है तो सबसे पहले उसे सभी खदानों को दोबारा अपने हाथ में लेना चाहिए और यह वचन देना चाहिए कि खनन से होने वाले मुनाफ़े का कम से कम पच्चीस प्रतिशत स्थानीय लोगों के हित में खर्च किया जाएगा. यह समस्या का केवल तार्किक समाधान ही नहीं है, बल्कि देश का संविधान भी यही कहता है. सरकार पहले अपनी विश्वसनीयता दोबारा बहाल करे, तभी आगे कोई कदम उठाने का अधिकार उसके पास होगा. हम तो यह उम्मीद करते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माओवादी विचारधारा के प्रतिकार का सबसे अच्छा तरीका आमजनों के मालिकाना हक़ वाले संसाधनों के आधार पर विकास की ईमानदार कोशिश ही है.

आपको आख़िर हो क्या गया है चिदंबरम साहब, आप तो भले इंसान हुआ करते थे. फेयरग्रोथ मामले में दोषी न होने के बावजूद आपने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. जीवन का मतलब चंद पैसों के एवज में अदालतों में जिरह करना नहीं है. इसका वास्तविक मतलब तो उसके पक्ष में तर्क देने से है, जो सही है. आपने एनडीटीवी पर इंटरव्यू के दौरान हम पर नाहक ही शातिर और कुटिल होने का आरोप लगा दिया, क्योंकि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते. आप जो कुछ भी करते हैं, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते. तेल के बदले अनाज कार्यक्रम मुद्दे पर संसद में बहस के दौरान रिलायंस को पाठक कमेटी के दायरे से बाहर रखने के लिए आपने जो तर्क दिए, वे वास्तव में क़ाबिलेतारीफ थे. लेकिन उक्त तर्क रखते हुए कहीं आप अपने शातिर दिमाग़ और कुटिलता का परिचय तो नहीं दे रहे थे? कम से कम इतना रहम तो करें कि अपने निर्णयों के लिए समाज को बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें. इन मुद्दों से हमारा इतना ही वास्ता है कि जिन चीजों पर आम जनता का हक़ है, वे उसके ही हाथों में रहे और निर्दोष लोगों, चाहे वे सुरक्षाकर्मी हों या माओवादियों का हाथ थामने के लिए मजबूर हुई जनता, को कॉरपोरेट घरानों के मुनाफ़े के चलते अपनी जानें न गंवानी पड़ें. हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि क़ानूनी पचड़ों और पुलिस ज्यादतियों के बूते सरकार पर नकेल डाल सकें. मानवाधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करने वाले लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसा करते हैं और इसके लिए हमें उनकी आलोचना नहीं, बल्कि इज्ज़त करनी चाहिए.

व्यक्तिगत हैसियत से मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहूंगा. सरकार द्वारा पॉस्को और आर्सेलर मित्तल को तीन लाख करोड़ रुपये का लौह अयस्क उपहार में देने के मामले में मेरी जनहित याचिका पर जिरह करने के लिए क्या आप अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे (जैसा पालकीवाला ने मिनर्वा मिल केस में किया था)? अदालती कार्रवाई में अनुकूल परिणाम मिलने की पूरी गारंटी है, क्योंकि क़ानून, तथ्य और सबसे बढ़कर आप ख़ुद मेरे पक्ष में होंगे. यदि आप ऐसा करने को राजी होते हैं तो मेरा दावा है कि वित्त मंत्री के रूप में छह महीने का बचा कार्यकाल पूरा करने के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा साख अर्जित करने में कामयाब होंगे. यदि आप इसमें अपनी रुचि दिखाएं तो अपील की एक प्रतिलिपि आपको भेज दूंगा. हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का जवाब ज़रूर देंगे. लंबे समय से आप सारा दोष सिविल सोसाइटी पर थोपते आ रहे हैं. अब हम भी आपसे जवाब चाहते हैं.

सधन्यवाद
ए के अग्रवाल

feedback@chauthiduniya.com

यह परंपरागत बालू खनन का रोज़नामचा है कि भोर बाद में होती है, उससे पहले बालू मज़दूरों की नावें नदी में उतर जाती हैं.

माफ़ियाओं से जूझते बालू मज़दूर

आदियोग

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले के उन मजदूरों का कसूर मात्र इतना था कि उन्होंने अपना शोषण करने वाले ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी, जो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद और विधायक हैं. बदले में पुलिस-प्रशासन ने उन पर जमकर कहर बरपाया. आख़िर कहां है सर्वजन हिताय और भयमुक्त समाज का नारा बुलंद करने वाली सरकार?

नाव से लोगों को नदी पार ले जाते, कंधों और पतवारों की जुगलबंदी से नाव खेते, बिखेर कर मछली का जाल फेंकते और शाम के धुंधलके में वापस लौटते मछुवारों की लयबद्ध छवियां बहुत सुहानी लगती हैं. लहरों की धुन पर हिचकोले खाते उनके गीत इस दृश्य को और अधिक दिलकश बनाते हैं. उनके तीन काम हैं और उसके लिए तीन संबोधन. अगर मछली मारते हैं तो मछुवारे, नदी पार कराते हैं तो केवट और नदी की तलछट से बालू निकालते हैं तो बालू मज़दूर. इसमें मांझी की पहचान लोकगीतों, तस्वीरों और रुपहले पर्दे पर ख़ूब उतरी है और उसने लोगों के जेहन में कमाल की जगह बनाई है, लेकिन इधर समय ने कुछ ऐसी करवट बदली कि उनके जीवन की पतवार धरती के प्रभुओं के हाथ बंधने लगी. उनकी आजीविका पर यमुना और गंगा तट पर बालू माफ़िया के वेश में विराजमान सर्वशक्तिमान प्रभुओं की बुरी नज़र लग गई.

हर कहीं मछुवारों की बस्तियों का हाल लगभग एक जैसा होता है. उनमें पालतू जानवरों के अलावा ग़रीबी, अभाव, गंदगी और बीमारी भी पलती है. अशिक्षा और पिछड़ेपन की गश्त भी रहती है. ऊपर से दारू भी चढ़ती है. इस माहौल में कहीं किसी कोने में अपराध की झाड़ भी उग आती है. यमुना नदी इलाहाबाद और कौशांबी ज़िले की सीमा रेखा है. उसके दोनों तटों पर बालू मज़दूरों की बस्तियां हैं और उनका भी यही हाल है. 90 फ़ीसदी वाशिंदों के पास खेती लायक़ ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत ख़राब है और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लगभग लापता हैं. उल्टे हालात में भी बेफ़िक्री मछुवारों के मिजाज़ में शामिल है, लेकिन यहां इस पर ग्रहण लग गया. मैंने इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लॉक के प्रतापपुर समेत यमुना के दूसरे छोर पर कौशांबी ज़िले के चायल ब्लॉक में बसे मल्हेपुर एवं नंदू के पूरे गांव का दौरा किया और उन्हें ख़ौफ़ से थोड़ा सहमा और उससे ज़्यादा गुस्से से गर्म पाया. बाद में यह अच्छी ख़बर मिली कि बीते 28 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीयूसीएल की जनहित याचिका पर दिए गए फ़ैसले में मशीन से बालू खनन पर रोक लगा दी है. इस तरह एक मई को मनाया जाने वाला मज़दूर दिवस इस बार बालू मज़दूरों की जीत का उत्सव भी बन गया. इस मौक़े पर बीड़ी, पत्थर खदान और खेतिहर मज़दूरों की भी मांगें प्रमुखता से उठीं.

वर्ष 2004 में यमुना के घाटों पर बालू खनन की मशीनें पहुंचने लगी थीं. उनकी घरघराहट ने बालू मज़दूरों की आजीविका पर हमला बोला और उनके बीच असंतोष की आग दी. मानव श्रम पर टिके परंपरागत बालू खनन की रफ़्तार बहुत सुस्त होती है. मशीनों ने इसे कई गुना बढ़ा दिया या कहें कि बालू मज़दूरों की छाती पर मूंग दलने लगीं. क्षोभ और तनाव पसरने लगा. मरता क्या न करता. मार्च 2005 में लावा अचानक फूट पड़ा. कई घाटों पर हज़ारों मज़दूरों ने धावा बोला और मशीनों को तोड़ कर पानी में डुबो दिया. माफ़ियाओं के गुंडे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भाग निकले. नदी पार कराने या मछली मारने पर लगे गुंडा टैक्स की भी हवा फिस्स होने लगी. मशीन से बालू खनन रुक गया.

कोई तीन साल तक बालू माफ़ियाओं का आतंक सिर नहीं उठा सका. इस बीच वे बालू मज़दूरों की एकता को तोड़ने की जोड़-जुगत में ज़रूर जुटे रहे और एक सीमा तक उसमें कामयाब भी रहे. बालू मज़दूरों को संगठित करने और उन्हें संघर्ष के रास्ते पर ले जाने का काम अखिल भारतीय मज़दूर किसान सभा ने किया था. संगठन का प्रभाव क्षेत्र दोनों ज़िलों के कोई दो सौ गांवों तक है. बालू माफ़िया की नज़र यमुना तट पर लगभग तीन सौ मीटर चौड़ी और दस किलोमीटर लंबी बालू की पट्टी पर थी, जो बारिश के मौसम में नदी का हिस्सा बन जाती है. इस बालू का उठना किनारे पर बसे गांवों के लिए ख़तरा है. संगठन ने ककड़ी, खरबूज और तरबूज की खेती के लिए उसे बालू मज़दूरों के बीच बांट दिया.

इससे बालू माफ़िया तिलमिला उठे और उनके पक्ष में पहले से खड़ा ज़िला प्रशासन बेचैन होने लगा. संगठन में लाल सलाम का अभिवादन प्रचलित है. संगठन का नाम लंबा है, इसलिए लाल सलाम पार्टी का नाम चल निकला. इस आधार पर मज़दूर किसान सभा और माओवादियों के बीच रिश्ते सूंघे जाने लगे. हालांकि लाल सलाम पार्टी दरअसल, सीपीआई (एमएल-न्यू डेमोक्रेसी) का जन संगठन है. सभी जानते हैं कि सीपीएम से अलग होकर बना सीपीआई (एमएल) आज दर्जनों धड़ों में बंटा हुआ है, लेकिन प्रशासन को इस ब्यौरे या तथ्य से क्या मतलब कि सीपीआई (एमएल-न्यू डेमोक्रेसी) कोई प्रतिबंधित पार्टी नहीं है? वैसे यह सवाल भी अपनी जगह है कि सीपीआई (एमएल) में टूटन दर टूटन आख़िर क्यों कर आई? इसके पीछे सैद्धांतिक मतभेद से ज़्यादा इलाक़ेदारी की ठसक ज़िम्मेदार रही है या फिर ग़रीब-वंचितों के व्यापक हित में उनके बीच न्यूनतम सहमति पर साझा पहल की गुंजाइश नहीं बन पाई?

ख़ैर, लंबी चुप्पी के बाद कई जगहों पर बालू खनन की मशीनें चालू हुईं. जवाब में मज़दूरों ने भी पुराना इतिहास दोहराया और कई मशीनों का कचूमर निकाल दिया. यह ख़बर आग की तरह फैली और बाक़ी मशीनें आनन-फानन हटा ली गईं. यह फरवरी 2008 की बात है. कुछ समय तक मामला ठंडा रहा, लेकिन बालू के लुटेरे पुराना सबक भूल कर एक बार फिर लौटने लगे. घटना के तुरंत बाद कौशांबी के पुरखास गांव में पुलिस-पीएसी ने डेरा डाल दिया. उसका काम था यथास्थिति और शांति बनाए रखना, लेकिन वर्दीधारी बालू माफ़िया के हाथ में मज़दूरों को डराने-धमकाने और सताने की लाठी बन गए. बालू चांदी की तरह चमकती है और उसके धंधे में मुनाफाखोरों की ख़ूब चांदी भी कटती है. बालू खनन लीज पर होता है और लीज धन-बल के ज़रिए हासिल होती है. सरकार 23 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी वसूल करती है और एक ट्रक में 14 घन मीटर बालू आती है. एक ट्रक बालू की रॉयल्टी कुल 308 रुपये. लीज होल्डर इसका परमिट सात सौ रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से छोटे ठेकेदारों में बांट देता है. ज़ाहिर है कि ठेकेदार अपना मुनाफा बालू मज़दूरों की मेहनत से चूसते हैं. उधर लीज होल्डर नाव के मालिक से 60 रुपये अलग से वसूलते हैं. संगठन के प्रमुख नेता सुरेश चंद्र की मानें तो बालू मज़दूरों के प्रतिरोध के चलते पिछले पांच साल में बालू माफ़िया को कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. इलाक़े में एक दर्जन बालू माफ़िया हैं.

यह परंपरागत बालू खनन का रोज़नामचा है कि भोर बाद में होती है, उससे पहले बालू मज़दूरों की नावें नदी में उतर जाती हैं. नदी से बालू निकालना, नाव को बालू से भरना, उसे खींच कर तट पर लाना, तसले में 35-40 किलो बालू भरकर उसे सिर पर ढोना और ऐसे कई चक्करों में दूर खड़े ट्रक को भरना हाड़तोड़ मेहनत का काम है. इतना कि कमज़ोर काठी को खटिया भी पकड़ा सकता है. कम से कम चार नावों पर लगी मेहनत से औसत आकार का ट्रक भर पाता है और एक नाव को बालू से भरने के लिए छह-सात मज़दूर तक़रीबन नौ घंटे लगाते हैं. ठेकेदार से अपनी मेहनत का सौदा और फिर मेहनताना हासिल करना भी आमतौर पर झिकझिक से होकर गुजरता है. हालांकि हर मज़दूर को दो सौ रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन यह काम रोज नहीं मिलता. इसलिए कि मज़दूरी रोटेशनल होती है और उसे ख़ुद बालू मज़दूर तय करते हैं. तो भी दो सौ रुपये की दिहाड़ी कम नहीं होती. दुखद यह कि उसका बड़ा हिस्सा दिन भर की थकान उतारने के नाम पर दारू में बह जाता है और अक्सर झगड़ा-झंझट खड़ा कर देता है. खामियाज़ा महिलाएं एवं बच्चे भुगतते हैं, वे हिंसा और अभाव झेलते हैं.

सबसे लंबा और कठिन काम बालू खोदना और उसे नदी की सतह पर लाना होता है. हाथों की मेहनत एक नाव को बालू से भरने में घंटों लगाती हैं, जबकि मशीनें एक घंटे में दो नाव भर देती हैं. बाक़ी बचता है नाव को तट पर लाने और बालू को ट्रक पर चढ़ाने का काम. इसकी कुल मज़दूरी 20 रुपये फेरा. तो मशीनों की आमद और बालू माफ़िया के आतंक ने एक बार फिर जोर पकड़ा और मज़दूरों के बीच आरपार की लड़ाई का माहौल बनने लगा. इसी कड़ी में पिछली 24 जनवरी को नंदा के पूरे गांव में हज़ारों मज़दूर एकत्र हुए. सभा के अंत में उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूंक कर किया.

इसके डेढ़ घंटे बाद गांव को पुलिस ने घेर लिया. तब तक संगठन के नेता अपने गांवों को लौट चुके थे. नूरा का पूरा में संगठन की कौशांबी ज़िला इकाई का दफ्तर है. बंद दफ्तर का दरवाजा तोड़ दिया गया. साइकिल, मेज, कुर्सी, तख्त और आलमारी जो कुछ भी मौजूद था, उसे कबाड़ में बदल दिया गया. संगठन के कागज़ात फाड़ दिए गए और चंदे में जमा की गई नौ हज़ार रुपये की रकम लूट ली गई. इसके बाद गांव के 55 घरों पर धावा हुआ. इसमें एक घर संगठन के उपाध्यक्ष छेदीलाल का भी था. सभी घरों में जमकर तोड़फोड़ और लूट हुई. खुरपी, हंसिया, चूल्हा, मछली पकड़ने का जाल तहस-नहस कर दिया गया. फूंस की झोपड़ियां उजाड़ और खपरैल घरों की छतें रौंद दी गईं. जो सामने दिखे या तनिक कसमसाए, उन्हें लात-घूंसा-लाठी और गाली मिली. महिलाओं के साथ भोंड़ा बर्ताव अलग से हुआ. उन पर भी दनादन लाठियां बरसीं. पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वह 70 साल की बूढ़ी रुक्मणी हो या 30 साल की अंधी विमला देवी. पुलिसिया कहर बच्चों पर भी टूटा. पुलिस ने लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. बदहवासी छा गई. भगदड़ में कई जख्मी हो गए. यह सीन बगल के उजैहिनी, मल्हेपुर और केवटपुरवा में भी दोहराया गया. पूरे इलाक़े की नाकेबंदी कर दी गई और पुलिस की फाइलों में संगठन के कई नेता गैंगस्टर बना दिए गए. बालू माफ़िया ने अगले दमन के लिए देव नाम से गुंडों का गिरोह भी खड़ा कर दिया.

प्रशासन को मंजूर नहीं कि बालू माफ़िया के ख़िलाफ़ कोई हवा बहे. हालात को काबू में रखने के लिए नंदा का पूरा गांव से कोई चार किलोमीटर दूर पुरखास में पुलिस ने कैंप डाल रखा है. यह सरकारी ताक़त की नुमाइश है कि ख़बरदार अगर किसी ने चूं-चपड़ करने की जुर्रत की. दरअसल बालू के महाबलियों में तीन सगे भाई भी हैं और तीनों जनप्रतिनिधि हैं. कपिलमुनि करवरिया फूलपुर से सांसद हैं. सूर्यभान करवरिया कौशांबी ज़िले के सरसवां ब्लॉक के प्रमुख रहे हैं और अब विधान परिषद के सदस्य हैं. दोनों बसपाई हैं. तीसरे भाई उदयभान करवरिया भाजपाई हैं और बारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. दलगत जुड़ाव में विभिन्नता है तो क्या, तीनों के बीच मज़बूत भाईचारा है. ज़ाहिर है कि एक बड़े इलाक़े पर तीनों भाइयों का साझा दबदबा है. इलाक़े की बड़ी आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र नदी भी है और उससे तीनों भाइयों का सीधा रिश्ता रहा है.

बताते चलें कि करवरिया बंधुओं के दिवंगत पिता वशिष्ठ करवरिया उर्फ भुक्कल महराज के आतंक के किस्से कभी दूर-दूर तक सुने जाते थे. ख़ासकर चुनाव के दौरान राजनेताओं के बीच उनकी मांग बढ़ जाती थी. इलाहाबाद में वह ज़मीन-जायदाद हड़पने

सतीश चंद्र

के उस्ताद माने जाते रहे. बाद में भुक्कल महराज ने राजनीति के खेल में भी क़िस्मत आजमाई. चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. उनके क़ाबिल बेटों ने ज़रूर चढ़ती जवानी में ही राजनीति की महिमा को पहचान लिया. भुक्कल महराज अपराध को राजनीति से जोड़ना चाहते थे और बेटों ने राजनीति को अपराध से जोड़ने का निरापद रास्ता पकड़ा. बाप-बेटों के बीच का कुल फ़र्क़ यही है. यहां गड़े मुर्दे उखाड़ना प्रासंगिक होगा. करवरिया बंधु के पितामह बाबा जगत करवरिया फतेहपुर ज़िले की खागा तहसील के चक नरई गांव के वाशिंदे थे. पूरे इलाक़े में उनकी तूती बोलती थी. दबंग किस्म के कुछेक पासियों से उनकी तीखी अदावत थी. इसी उठापटक में आठ पासी पुलिस के हत्थे चढ़ गए. मुक़दमे की पेशी के लिए उन्हें अदालत में पहुंचना था कि उससे पहले पुलिस हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई. ज़ाहिर है कि शक की उंगली बाबा जगत करवरिया पर उठी. इस मामले के कुछ दिनों बाद ही उनकी भी हत्या हो गई. आतंक की बादशाहत टूटी तो करवरिया परिवार का खागा में रहना असुरक्षित हो गया और उसे उजड़ कर इलाहाबाद में बसेरा जमाना पड़ा. यहीं से भुक्कल महराज ने अपना खाता खोला और आगे चलकर अपने पिता से कहीं अधिक बढ़त हासिल की. ताना-बाना ऐसा बनाया कि उनका कोई बाल बांका न कर सका. उनके बेटों ने राजनीति का दामन थाम कर दहशतगर्दी को और आसान बना डाला.

सब कुछ भकोस लेने की जालिम हवस में मेहनतकश ग़रीबों के निवालों पर नज़र गड़ाना और उन्हें अभाव की गहरी खाई में ढकेल देना तो इंसानियत का गला मरोड़ देना है. यह तो महापाप है और अगर यह धतकरम जन प्रतिनिधियों के हाथों से हो, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? बसपा का हाथी भले ही कमल से बिदकता हो या कमल हाथी से चिढ़ता हो, लेकिन कौशांबी में दोनों का याराना है. यमुना तट पर हाथी मज़दूरों को रपटाते हुए चिंघाड़ता है और उसकी सूंड पर विराजमान कमल मुस्कराता है. इसे कहते हैं प्रतिद्वंद्वी पहलवानों के बीच का तालमेल. सर्वजन हिताय और भयमुक्त समाज के नारों और दावों की यही हक़ीक़त है. फ़िलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले ने बालू मज़दूरों को ज़रूर बहुत बड़ी राहत और ताक़त देने का काम किया है.

feedback@chauthiduniya.com

तिब्बत से बहकर असम में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम की सभ्यता, संस्कृति और अर्थनीति के लिए जीवनरेखा की तरह है.

राहुल के सामने चुनौतियों का पहाड़

अजय कुमार

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं. पहले दलितों की बस्ती में चौपाल लगाकर सुर्खियां बटोरने वाले राहुल ने आजकल कांग्रेस संदेश यात्राओं के माध्यम से पार्टी को मज़बूती प्रदान करने का अभियान छेड़ रखा है. इन यात्राओं को विधानसभा चुनाव 2012 के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है. दो चरणों में चलने वाली यह यात्राएं 10 नवंबर को इलाहाबाद में सोनिया गांधी की जनसभा में तब्दील होकर संपन्न हो जाएंगी. यात्रा का पहला चरण 14 अप्रैल से 31 मई तक था और दूसरा चरण गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा. 10 नवंबर को स्वराज भवन में जनसभा करके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी की कामयाबी की कहानी जनता को सुनाएंगी. कांग्रेस की संदेश यात्रा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी. 2012 के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस की संदेश यात्रा मील का पत्थर साबित हो सकती थी, लेकिन शुरुआत ही शुभ नहीं रही. विपक्ष को तो ऐसे आयोजनों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेसी भी राहुल के सपने को पूरा नहीं होने दे रहे. ज़िलों में जब यात्रा पहुंचती है तो स्थानीय नेता वर्चस्व के लिए आपस में भिड़ जाते हैं. इसी वजह से अंदर से लेकर बाहर तक संदेश यात्रा विवादों में घिर गई है.

काफी सोच-विचार के बाद कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत का समय और स्थान तय किया था. लंबे समय से दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की मुहिम में लगे राहुल गांधी ने जब संदेश यात्रा निकालने का मन बनाया तो उनके दिलोदिमाग़ में दलितों के अलावा कोई नहीं था. इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत अंबेडकर नगर से करने का फ़ैसला लिया. अंबेडकर नगर बसपा प्रमुख मायावती का गढ़ है. यहां से वह कई बार चुनाव जीत चुकी हैं. बसपा को कांग्रेस के कार्यक्रम के बारे में पता चला तो उसके कान खड़े होना स्वाभाविक था. यही वजह थी 14 अप्रैल को अंबेडकर नगर में बसपा और कांग्रेस के बीच चले सियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स मज़ेदार रहा. अंबेडकर जयंती पर बसपा ने भी शहर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रखे थे. स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दोनों कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पसीने आ गए. कहा तो यहां तक गया कि अंबेडकर नगर प्रशासन ने राहुल द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण में भी काफी रोड़े अटकाए. उधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर कांग्रेस ने संदेश यात्रा के लिए जो पोस्टर छपवाए, उनमें बाबा साहेब का चित्र ग़ायब था. इससे बसपा को कांग्रेस की नीयत पर उंगली उठाने का मौक़ा मिल गया. बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसी के कारण बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिला. बहरहाल संदेश यात्रा के पोस्टर में बाबा साहेब का चित्र न होने की ग़लती का एहसास होते ही आनन-फानन में दूसरा पोस्टर बनवा कर लगवा दिया गया, जिसमें गांधी-नेहरू परिवार, जगजीवनराम, बाबा साहेब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के चित्र थे. कांग्रेस इस हादसे से उबर भी नहीं पाई थी कि 16 अप्रैल को बुलंदशहर में संदेश यात्रा के दौरान हुई स्वागत सभा में चीयर गर्ल्स के फूहड़ नृत्य ने यात्रा की किरकिरी करा दी. बुलंदशहर में एक कॉलेज के मैदान में हुए अश्लील नृत्य के इस कार्यक्रम को स्थानीय टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया. इसे लेकर बसपा और अन्य दलों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. मामला इतना गरमाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने जांच का आदेश दे दिया. बाद में कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे लोकनृत्य बताकर मामला शांत किया. संदेश यात्रा के दौरान एक के बाद एक ग़लती कर रहे कांग्रेसियों की नीयत पर विपक्ष को उंगली उठाने का मौक़ा मिल गया. रही-सही कसर कांग्रेसियों की आपसी गुटबाज़ी ने पूरी कर दी. जिन ज़िलों से यात्रा गुजरी, वहां-वहां कांग्रेसियों की गुटबाज़ी देखने को मिली. फर्क़ केवल इतना है कि कहीं यह दबी-छिपी थी तो कहीं खुलकर सामने आ गई. मऊ, मेरठ और इलाहाबाद में तो गुटबाज़ी का रंग सड़क पर साफ़-साफ़ दिखाई पड़ा. यात्रा के चौथे दिन मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में स्वागत सभा में शुरू हुई आरोप-प्रत्यारोप की जंग का अंत ताबड़तोड़ फायरिंग से हुआ, जिसमें आठ राउंड गोलियां चलीं. कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के दो बेटों रमन और तरुण के ख़िलाफ़ रिपोर्ट तक दर्ज हो गई. बताया गया कि यात्रा के दौरान मंच पर ही मशरूर अहमद और राजेंद्र शर्मा की नोकझोंक हुई थी. समर्थकों ने उत्साह में नारेबाज़ी और फायरिंग कर दी. इसके बाद मामला अधिक गरमा गया.

मेरठ के स्थानीय नेताओं की लंबे समय से चली आ रही तनातनी के कारण इस बात की उम्मीद पहले से थी कि यहां हंगामा हो सकता है. दरअसल, संदेश यात्रा शुरू होने से पूर्व मंडल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी यहां आई थीं. इस मौक़े पर मेरठ के कांग्रेसी न केवल आपस में भिड़ गए, बल्कि रीता बहुगुणा जोशी के साथ भी अभद्रता की गई. इस पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने स्थानीय नेताओं को फटकार भी लगाई. मामला फिर भी ठंडा नहीं हुआ तो दिल्ली और लखनऊ में बैठे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने यहां आने का कार्यक्रम ही टाल दिया. रीता बहुगुणा ने मोबाइल फोन पर लोगों को संबोधित करके काम चला लिया. हालांकि अब कांग्रेसी इस बात से इंकार कर रहे हैं कि उन लोगों के बीच किसी तरह की फायरिंग भी हुई थी. उनका आरोप तो यह है कि पुलिस बसपा सरकार को ख़ुश करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रही है. ऐसा ही नज़ारा मऊ में भी देखने को मिला. संदेश यात्रा के दौरान कोपागंज में दस मई की रात हालात तब ख़राब हो गए, जब दो गुटों में बंटे कांग्रेसी संदेश यात्रा का नेतृत्व कर रहे सचिव डॉ. भोलानाथ पांडे को अपने-अपने मंच पर लाने के लिए भिड़ गए. अंतत: एक गुट पुलिस की लाठियां खाते हुए भी पांडे को अपने साथ लेकर ओड़ियाने के मैदान में सभास्थल पर पहुंच गया. घटना को लेकर हाईवे पर यातायात ठप हो गया. आधा दर्जन कांग्रेसियों को चोटें भी आईं.

काफी सोच-विचार के बाद कांग्रेस ने यात्रा की शुरुआत का समय और स्थान तय किया था. लंबे समय से दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की मुहिम में लगे राहुल गांधी ने जब संदेश यात्रा निकालने का मन बनाया तो उनके दिलोदिमाग़ में दलितों के अलावा कोई नहीं था.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाज़ी ने आलाकमान के कान खड़े कर दिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की सख्त हिदायत के बाद भी कांग्रेस नेता स्थानीय गुटबाज़ी से उबर नहीं पाए. संदेश यात्रा के दौरान कोई भी ज़िला ऐसा नहीं दिखा, जहां सभी कांग्रेसी एक साथ खड़े दिखाई दिए हों. इसी कारण कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संदेश यात्रा से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझी, जिसका नुक़सान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है. राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा पर कांग्रेसियों की गुटबाज़ी कुठाराघात कर सकती है. ख़ुशी की बात बस इतनी है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी आपस में भले ही सिर फुटौव्वल कर रहे हैं, लेकिन राहुल के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है. प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाज़ी से परेशान राहुल इस बार क़दम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा की सफलता का ज़िम्मा अपने क़रीबी युवा चेहरों के कंधों पर डाल रखा है. राहुल के कहने पर प्रदीप जैन, आरपीएन सिंह, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन जैसे युवा चेहरों को संदेश यात्रा के साथ प्रमुखता से जोड़ा गया है. यह नेता संदेश यात्रा के बाद भी किसी न किसी बहाने उत्तर प्रदेश में रहकर राहुल का हाथ मज़बूत करते रहेंगे. दरअसल राहुल का मानना है कि प्रदेश में और कोई ऐसा युवा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, जिसके सहारे आगे की लड़ाई लड़ी जा सके. दूसरी तरफ़ कांग्रेस के पास पूरे देश में तमाम युवा नेता हैं. उत्तर प्रदेश की कमी अब इन नेताओं के सहारे पूरा करने की मुहिम छेड़ी जा रही है. इस क्रम में राहुल गांधी के निर्देश पर पूर्व मिस्टर दिल्ली एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आस्कर फर्नांडिस के फिटनेस सचिव राकेश राजपूत एटा और उन्नाव में कांग्रेस की जनजागरण यात्रा में शिरकत भी कर चुके हैं. कई हिंदी फ़िल्मों में अभिनय कर चुके राजपूत ने राहुल गांधी के अभियान को सफल बनाने के लिए युवाओं से अपील की. उन्होंने युवाओं को राहुल का संदेश भी दिया कि बेहतर कल के लिए कांग्रेस का साथ देना ही उचित विकल्प है.

उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को समझना होगा कि अगर प्रदेश में उन्हें अपनी खोई हुई साख फिर से हासिल करनी है तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा. उनके सामने बसपा की चुनौती है, क्योंकि जनाधार और काडर के आधार पर वह उत्तर प्रदेश की नंबर वन पार्टी है. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी कम नहीं आंका जा सकता, जो राजनीति की बिसात पर कब कैसे अपना घोड़ा चल दें, कोई नहीं जानता. 2007 में राज्य में जीत का परचम लहराने वाली बसपा का रंग 2009 के लोकसभा चुनाव ने कुछ फीका ज़रूर कर दिया है, लेकिन उसे कम आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता. जहां तक कांग्रेस की स्थिति का सवाल है तो उसके पास ख़ुश होने के लिए 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 22 सीटों पर फतह हासिल करने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है. बस इसी जीत ने कांग्रेसियों के पंख लगा दिए हैं. उनके सामने राजनीति का पूरा मैदान है और राहुल जैसा यूथ आइकॉन, जिसके जुझारूपन का लोहा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, विपक्ष भी मानता है. राहुल की अगुवाई में कांग्रेसी खुद को भले ही ख़ुशनसीब समझ रहे हों, लेकिन राहुल के सामने सबसे बड़ी समस्या है मज़बूत संगठन का अभाव और ज़िला स्तर पर व्याप्त गुटबाज़ी. कांग्रेसियों की गुटबाज़ी का नज़ारा विभिन्न ज़िलों से गुजर रही संदेश यात्रा के दौरान टकराव के रूप में जहां-तहां देखने को मिल रहा है. कहना ग़लत न होगा कि अगर समय रहते प्रदेश के कांग्रेसी नहीं सुधरे तो जनता को फिर मुंह मोड़ने में देर नहीं लगेगी. जहां तक बात राहुल की है तो वह चाहे जितने पसंदीदा नेता हों, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता.

feedback@chauthiduniya.com

ब्रह्मपुत्र पर चीन का बांध और असम

दिनकर कुमार

ब्रह्मपुत्र असम के लिए जीवनरेखा की तरह है. पड़ोसी देश चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है. इस ख़बर का अर्थ है कि वहां के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है. चीन अपने तिब्बत के हिस्से में ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है. जब भारतीय उपग्रह ने बांध के निर्माण से संबंधित तस्वीरें मुहैया कराईं तो उसी समय से इस विषय को लेकर शंका ज़ाहिर की जा रही थी. चीन काफ़ी दिनों से इस ख़बर का खंडन करता रहा था, लेकिन उसने भारत से कहा है कि वह ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बना रहा है, साथ ही चार और बांध बनाने की योजना बनाई गई है. विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने राज्यसभा में बताया कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के जांगमू में चीन ने ब्रह्मपुत्र पर बांध का निर्माण किया है. विदेश मंत्री ने सफाई दी कि जांगमू पनबिजली संयंत्र का आकार छोटा है और इसका मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति करना नहीं, बल्कि पनबिजली का उत्पादन करना है. यह 540 मेगावॉट की बिजली परियोजना है, जिसे बनाने में 1138 करोड़ येन ख़र्च किए जाएंगे. पांच कंपनियों के साथ सरकार ने निर्माण कार्य के लिए समझौता भी किया है और इन कंपनियों ने संयंत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है.

यह सभी जानते हैं कि तीव्र विरोध का सामना करते हुए भी चीन तिब्बत इलाक़े पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है. यह इलाक़ा जल संपदा की दृष्टि से समृद्ध है. विश्व के वर्तमान हालात को देखते हुए चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास में जल संपदा का अहम योगदान होगा. यही वजह है कि चीन तिब्बत में मौजूद जल संपदा का इस्तेमाल अपने विकास कार्यों में करने की योजना बनाता रहा है. ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपों नदी के नाम से जाना जाता है. मीडिया की ख़बरों के अनुसार, चीन सांगपो नदी पर बांध बनाकर जहां पनबिजली का उत्पादन करना चाहता है, वहीं सूखे से प्रभावित अपने पूर्वोत्तर के प्रांतों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए जलापूर्ति का इंतज़ाम भी करना चाहता है. वर्ष 2009 के अंत तक चीन बांध बनाने की ख़बर पर दृढ़ता के साथ खंडन करता रहा था, लेकिन कोपेनहेगेन में आयोजित जलवायु सम्मेलन में जब इन दोनों देशों ने एक-दूसरे को सहयोग देने की बात कही, तब चीन की तरफ़ से बांध बनाने की बात स्वीकार की गई. बीजिंग यात्रा के बाद भारत लौटे विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने राज्यसभा में बताया कि चीन के विदेश मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पनबिजली संयंत्र को छोड़कर जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी और पड़ोसी देशों को इस बांध से किसी तरह का ख़तरा नहीं होगा.

तिब्बत से बहकर असम में आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम की सभ्यता, संस्कृति और अर्थनीति के लिए जीवनरेखा की तरह है. असम के लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि जब तिब्बत में उद्गम क्षेत्र में ही ब्रह्मपुत्र की जलधारा को बांध बनाकर रोका जाएगा तो इसका दुष्प्रभाव असम पर पड़ेगा. असम के अलावा पड़ोसी बांग्लादेश को भी इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है. असम के जनसंगठन इस बात पर क्षोभ प्रकट कर रहे हैं. उनका कहना है कि ब्रह्मपुत्र भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई अंतरराष्ट्रीय नदी है और चीन एकपक्षीय रूप से इस पर बांध बनाकर अंतरराष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है. इस तरह का बांध बनाने से पहले उसे भारत और बांग्लादेश की सरकारों से बात करनी चाहिए थी. मीडिया का कहना है कि भले ही चीन छोटी पनबिजली परियोजना की बात कर रहा है, लेकिन हक़ीक़त में वह हज़ारों मेगावॉट बिजली पैदा करने के लिए बड़े बांध बनाने की गुपचुप तैयारी भी कर रहा है. जानकार मानते हैं कि बड़े बांध के निर्माण में स्वाभाविक जलधारा सिकुड़ती चली जाएगी और असम एवं बांग्लादेश की जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा. इस बड़े बांध की वजह से असम एवं पूर्वोत्तर भारत को भी नुक़सान पहुंच सकता है.

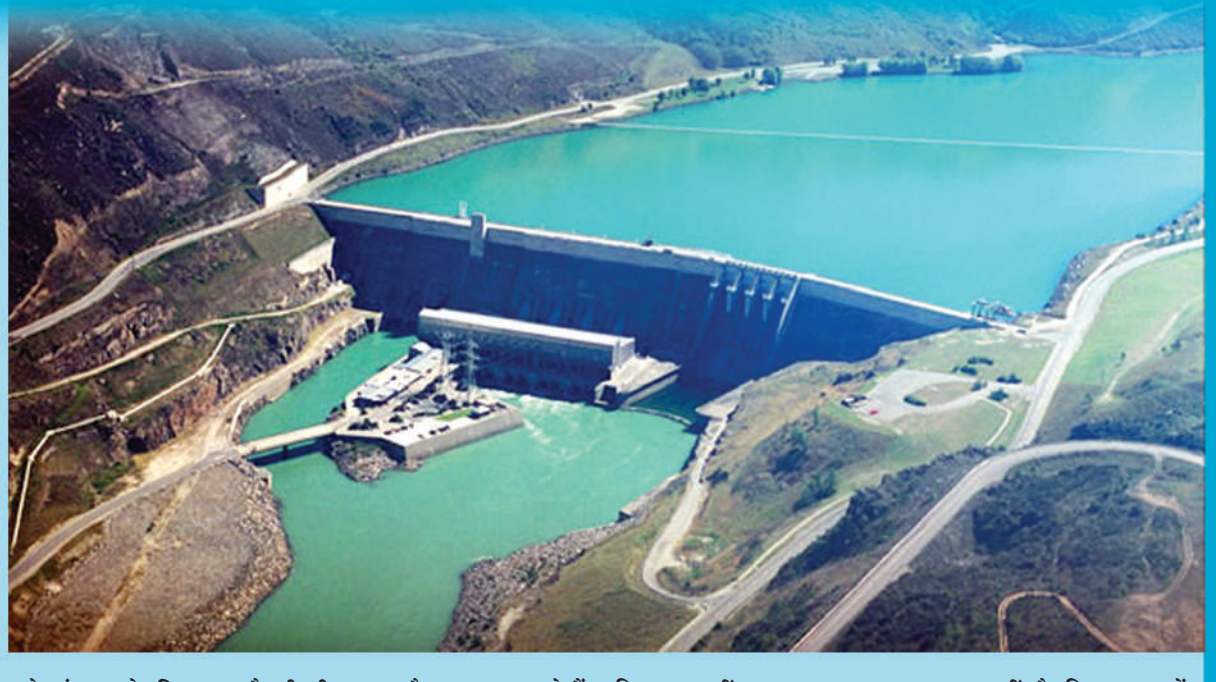

हालांकि चीन दिलासा दिला रहा है कि बांध के निर्माण से ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्से में जलधारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता. वैसे भी चीन की मंशा हमेशा शक के दायरे में रहती है और भारत उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता. भारत भूला नहीं है कि 1962 में हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे को उछालने वाला चीन अचानक आक्रामक हो उठा था और उसने भारत पर हमला कर दिया था. जानकारों का कहना है कि केवल चीन के आश्वासन पर भरोसा न करते हुए भारत को तथ्यों के आधार पर चीन के साथ इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए. अगर सरकार ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया तो असम को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

उन्नाव की ज़मीं पर अभी भी जनविरोधी औद्योगिक विकास योजनाएं राजनेताओं, माफ़ियाओं, देशी-विदेशी उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के गठजोड़ से ज़ोरों पर चल रही हैं.

संकट में जनजीवन

राजधानी लखनऊ से महज़ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश का जनपद उन्नाव अपने पौराणिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक महत्व के बावजूद आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. विकास के नाम पर विनाश की खेती धड़ल्ले से जारी है. सबको पता है, लेकिन हर शख्स ख़ामोश है, कहीं से कोई पहल नहीं हो रही. आख़िर वजह क्या है?

गिरजेश कुमार

गंगा और सई नदी के दोआब में स्थित उत्तर प्रदेश का ज़िला उन्नाव ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी गौरवपूर्ण जनपद रहा है, लेकिन आज यह अपनी पहचान खोता जा रहा है. यहां समस्याओं की भरमार है. पेयजल, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, जाति-वर्ग भेद, परस्पर वैमनस्य, कृषि उत्पादन में निरंतर गिरावट, सेज, कॉरपोरेट खेती, जनविरोधी योजनाएं, अधिग्रहण से घटती भूमि पर बढ़ता जनसंख्या घनत्व एवं कृषि योग्य भूमि की कमी ज़िले की आजीविका, आत्मनिर्भरता और गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है. आज भ्रष्टाचार की मार झेल रहा उन्नाव कभी खेती और जल के मामले में काफी ख़ुशहाल माना जाता था.

अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गंगा और सई नदियों के दोआब में 4558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जनपद की सीमाएं उत्तर-पूर्व में लखनऊ, दक्षिण-पश्चिम में फतेहपुर एवं कानपुर, पश्चिम-उत्तर में हरदोई और दक्षिण-पूर्व में रायबरेली आदि जनपदों से घिरी हैं. पूर्व-दक्षिण से उत्तर-पश्चिम की ओर इस जनपद का विस्तार 67 से 107 किमी तक, पूर्व से पश्चिम तक 41 से 50 किमी तक है. यह अवध क्षेत्र का हृदयस्थल है. वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 27,00,426 थी और जनसंख्या घनत्व 592 प्रति वर्ग किमी. यदि 1971 से 2001 की जनसंख्या वृद्धि का आकलन किया जाए तो वर्तमान 2010 में यहां की जनसंख्या लगभग 32,67,516 होगी और जनसंख्या घनत्व 717 प्रति वर्ग किमी. उन्नाव देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भी है.

यह जनपद गंगा के उस मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी से बना है. अभी ज़्यादा समय नहीं गुज़रा है, जब पेयजल, ग़रीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के बावजूद यहां की ज़मीन सोना उगलती थी. उसी ज़मीन और मेहनत के बूते यहां के लोग कभी किसी के मोहताज नहीं रहे. लेकिन पिछले कुछ सालों से उद्योगपति एवं पूंजीपति अपने फ़ायदे के लिए जनपद की बेशक़ीमती ज़मीन हथियाने का अभियान सा चला रहे हैं. इस साज़िश में जनता के वोट से चुनी गई सरकारें शामिल रहीं, चाहे वह किसी भी पार्टी या गठबंधन की हों. विकास के बहाने कृषि योग्य उपजाऊ ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं. जनपद में

आधारशिला 1973 में रखी गई थी और मगरवारा के पास अकरमपुर एवं सोनिक के पास दही चौकी नामक दो क्षेत्र औद्योगिक पट्टी के रूप में विकसित किए गए, जिनमें अन्य किसी उद्योग का विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन चर्मशोधक एवं रासायनिक कारखानों का निरंतर विकास ज़रूर हो रहा है. इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्थापित कानपुर के चर्म उद्योग को भी बंथर क्षेत्र में लेदर पार्क के रूप में स्थापित किया जा रहा है. उक्त औद्योगिक इकाइयां उन्नाव को तो प्रदूषित कर ही रही हैं, साथ ही आसपास के 40 किमी इलाक़े तक क़हर बरपा रही हैं. दही चौकी क्षेत्र का पानी लोनी ड्रेन द्वारा गंगा नदी को सेमरी के पास प्रदूषित करता है तो दूसरी तरफ अकरमपुर एवं बंथर क्षेत्र का पानी लगभग 25 किमी जलभराव और रिसाव का रास्ता तय करता हुआ गंगा के बलायघाट पर गिरता है, जिससे लगभग 40 गांव प्रभावित होते हैं. चर्मशोधक एवं रासायनिक फैक्ट्रियां सिर्फ़ नालों की समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीनों को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि इनकी वजह से भूमिगत जलस्तर भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इस क्षेत्र का जल पीने योग्य नहीं रहा. दिखावे के नाम पर जलशोधन संयंत्र लगे हैं, लेकिन ख़र्च बचाने के चक्कर में कचरा नालों और खेतों में बहा दिया जाता है. साथ ही गहरी बोरिंग करके प्रदूषित पानी भूमिगत जलस्रोत में मिलाया जा रहा है, जिससे नागरिक एवं पशु-पक्षी गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं. जनता घुट-घुट कर जीने को मजबूर है. आजीविका का संकट गहराता जा रहा है.

1971 से 2001 तक की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व एवं जनपद की कुल भूमि

वर्ष	कुल भूमि	जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी
1971	4558 वर्ग किमी	14,84,393	22.78	326
1981	4558 वर्ग किमी	18,22,591	22.80	400
1991	4558 वर्ग किमी	21,87,840	20.70	480
2001	4558 वर्ग किमी	27,00,426	21.00	5322011
2011	?	संभावित जनसंख्या लगभग 32,67,516	विविध योजनाओं में जनपद की भूमि घटेगी. 1971 के आंकड़े के आधार पर जनसंख्या घनत्व-717* प्रति वर्ग किमी लगभग हो सकता है.	

यह सिलसिला यहीं नहीं थमता. उन्नाव की ज़मीं पर अभी भी जनविरोधी औद्योगिक विकास योजनाएं राजनेताओं, माफियाओं, देशी-विदेशी उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के गठजोड़ से ज़ोरों पर चल रही हैं. हरदोई की सीमा से रायबरेली की सीमा तक 130 किमी लंबी और 155 मीटर चौड़ी उत्तर से दक्षिण गंगा एक्सप्रेस हाइवे योजना (नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित 8 लेन सड़क) गंगा के 2-5 किमी दूरी तक, जीटी रोड बिल्हौर से लखनऊ तक 6 लेन रोड लगभग 70 किमी लंबा और 130 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें 72 ग्राम पंचायतों (50 जनपद उन्नाव, 22 जनपद लखनऊ) की कृषि योग्य भूमि एवं उससे जुड़ी आजीविका के लोग प्रभावित होंगे.

संभावित जनसंख्या लगभग 32,67,516 विविध योजनाओं में जनपद की भूमि घटेगी. 1971 के आंकड़े के आधार पर जनसंख्या घनत्व 717* प्रति वर्ग किमी लगभग हो सकता है. उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यद्यपि कृषि क्षेत्र निरंतर आवास एवं औद्योगीकरण योजनाओं द्वारा घट रहा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व 1971 से 2001 तक 326 से बढ़कर 532 और वर्तमान में 680 प्रति वर्ग किमी पहुंच गया है. यदि उपरोक्त योजनाओं में भूमि अधिग्रहीत कर ली गई तो जनपद की कृषि योग्य भूमि समाप्त प्राय: हो जाएंगी. इतिहास गवाह है कि सरकारों ने हमेशा असंगठित जनता को मोटे मुआवज़े एवं पुनर्वास का झांसा देकर उनकी भूमि अधिग्रहीत करके औद्योगिक घरानों को सौंप दी और जनता को तबाही, तंगहाली एवं भुखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया. इसके लिए समय रहते अपने अधिकारों के प्रति जनता की समझ विकसित करने और संगठित होकर संघर्ष के लिए खड़े होने की आवश्यकता है. देश में खाद्यान्न की पैदावार घट रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है. इन जनविरोधी योजनाओं से लाखों किसान बेरोज़गार, विस्थापित और तबाह होंगे. कृषि भूमि की बदौलत पलने वाले जनसामान्य और पशुओं पर घोर संकट आने वाला है. इससे पर्यावरण का भयंकर क्षरण होगा. संकल्पहीन एवं लचर राजनीतिक नेतृत्व और उदासीन-लापरवाह नौकरशाही से आम जनता के पसीने की कमाई बर्बाद होगी. जनपद की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावर्णीय दुर्गति होगी. तमाम तरह की बीमारियां व आपदाएं बढ़ेंगी. अगर समय रहते शासन ने सुध न ली तो उन्नाव के हालात बदतर हो सकते हैं.

(लेखक विकास भारती संस्था के अध्यक्ष हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बुंदेलखंड प्राचीन धरोहरों एवं स्थलों के लिए प्रसिद्ध और समृद्ध रहा है. यहां के कण-कण में इतिहास समाहित है.

ज़मींदोज़ होती धरोहर

सुरेंद्र अग्निहोत्री

वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों, विशिष्ट पुरातात्विक धरोहरों की नगरी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग एवं राज्य सरकार के अड़ियल और उदासीन रवैये के कारण अपनी विरासत को ज़मींदोज़ होते देख रहा है. सतयुग से लेकर कलयुग तक के इतिहास के साक्षी अनेक स्थलों की हालत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है. इन ऐतिहासिक धरोहरों पर अतिक्रमण की भरमार है. दरवाजे, परकोटे और क़ीमती पत्थर हजम किए जा चुके हैं. दास्तान-ए-बदहाली राजधानी लखनऊ से ललितपुर तक एक जैसी है. लखनऊ का ऐतिहासिक सतखंडा भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. बिठूर के गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर पर लगातार ख़तरा मंडरा रहा है. अयोध्या में हनुमान गढ़ी सहित अनेक ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें लम्हा-लम्हा क्षरण की शिकार हो रही हैं. फैज़ाबाद में बहू बेगम के मकबरे का ऐतिहासिक द्वार क़ब्ज़े का शिकार हो गया है. मिर्ज़ापुर में चुनार का किला चंद्रकांता के रहस्यमय घटनाक्रम का साझी है. इस किले पर तस्करों की नज़र लगी हुई है. वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर अहेरोरा से 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित विंध्य पर्वत घाटी के लखनीयादरी नामक स्थान पर हज़ारों वर्ष पूर्व के भित्तिचित्र रखरखाव के अभाव में नष्ट हो रहे हैं. लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी तहसील में राजा विराट के समय की धरोहरों एवं पुराअवशेषों को संजोने की फ़िक्र न सरकार को है और न पुरातत्व विभाग को.

हमीरपुर जनपद के मौदहा क़स्बे में स्थित तेरहवीं शताब्दी की दरगाह रखरखाव के अभाव में नष्ट होने की कगार पर है. श्रावस्ती में बौद्ध धर्म के भग्नावशेष खंडहर में तब्दील हो रहे हैं. मसूद गाजी का जंजीरी गेट, प्राचीन जैन मंदिर, लखीमपुर खीरी में 10वीं शताब्दी का खैरीगढ़ किला, तांत्रिक विधि से बना ओपल मेढ़क मंदिर, शाहजहांपुर में जमदग्नि ऋषि का आश्रम एवं राजधानी से लगा बख्शी का तालाब मुगल-भारतीय स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं. कन्नौज में 13वीं सदी का अन्नपूर्णा मंदिर, आजमगढ़ में भैरव जी, दुर्वासा ऋषि का आश्रम, वाराह रूप मंदिर, आंवक ग्राम में मिले भग्नावशेष, जौनपुर का शाही किला, अटाला मस्जिद, चंदौली का रामनगर किला, बलिया का भृगु मंदिर, सोनभद्र का विजयगढ़ किला, सीतापुर के बोहरबीरम का प्राचीन मंदिर, जालौन के रामपुरा की गढ़ी, कालपी की लंका एवं चौरासी गुंबद, मेरठ का लाक्षागृह, वाराणसी के अनेक प्राचीन मंदिर, कौशांबी और इलाहाबाद के अनेक ऐतिहासिक स्थल घोर उपेक्षा के शिकार हैं. हज़ारों साल का इतिहास ख़ुद में समेटे कालिंजर के किले, ललितपुर के दस्ताऔतार मंदिर, बरुवा सागर किला, महोबा, लखनऊ के रूमी दरवाजे और भूलभुलइया जैसे कुछ स्थलों के संरक्षण हेतु एएसआई की अनूठी पहल सदैव याद की जाती रहेगी. लेकिन जितनी ऐतिहासिक विरासत प्रदेश की सरजमीं पर मौजूद है, उसके संरक्षण के लिए एएसआई के प्रयास अपर्याप्त हैं.

संस्कृति विभाग के तहत आने वाले बांदा के छत्रसाल एवं देवगढ़ संग्रहालय में ताला जड़ा है. फैज़ाबाद में तो हद हो गई है. अवधकालीन धरोहर बहू बेगम के मकबरे के रूप-रंग को मनमाने ढंग से बदला जा रहा है. मकबरे का ऐतिहासिक द्वार बंद कर दिया गया है. उसके बाहर स्थित जगह को किराए पर उठाकर मुतबल्ली मज़े कर रहे हैं. अभी तक मकबरे से होने वाली आय को बैंक में रखने के लिए खाता नहीं खोला जा सका. ग़ौरतलब है कि नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी इम्मतुल जोहरा (बहू बेगम) के मकबरे का निर्माण 1825 में किया गया था. मकबरे तक पहुंचने के लिए तीन भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए थे. उत्तरी दिशा में निर्मित प्रवेश द्वार को क़ब्ज़ेदारों ने अवैध निर्माण करके बंद कर दिया है. उत्तर-पूर्व और पश्चिम के मकबरे की भूमि पर अवैध निर्माण जारी है.

रानी लक्ष्मीबाई के किले और महाराजा गंगाधर राव की समाधि को छोड़ दूसरे सभी स्थल दयनीय हालत में हैं. चाहे वह हाथीखाना, आंतिया तालाब हो या लक्ष्मी ताल, सबके सब उपेक्षित पड़े हैं. पर्यटक जब झांसी पहुंचते हैं तो उन्हें रानी झांसी के किले की दीवारों और रानी महल को देखकर ही संतोष करना पड़ता है. रानी की अन्य कोई भी वस्तु या उनके शासन से संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है. रानी की तलवार, ध्वज और राजमुद्रा जैसी कोई वस्तु अथवा साहित्य तक झांसी में नहीं है. आज हालत यह है कि सभी परकोटों पर अतिक्रमण हो चुका है, ऐतिहासिक महत्व के मोटे-मोटे दरवाजे लोग टुकड़े-टुकड़े करके उठा ले गए. उनका लोहा और लकड़ी लाखों रुपये में बेच दिया गया और पुरातत्व विभाग को ख़बर तक नहीं हुई.

एक जमाने में सभी दरवाजों के ऊपर एक ताम्रपात लगा रहता था, जिसमें पूरा विवरण होता था यह ताम्रपात तीन इंच मोटा और एक फुट लंबा हुआ करता था. बड़ागांव दरवाजे पर लगे ताम्रपात के प्रत्यक्षदर्शी आज भी जीवित हैं, लेकिन यह ताम्रपात कुछ वर्षों पहले रातोरात चोरी हो गया. कुछ ऐसी ही स्थिति बड़ागांव दरवाजे की भी है, जहां का परकोटा अब पता ही नहीं चलता कि कहां से कहां को गया था. बड़ागांव दरवाजे से गोपाल की बगिया की ओर काफी लंबा-चौड़ा परकोटा था, जिसे एक भूमाफ़िया ने लोगों को बेच दिया. लक्ष्मी तालाब एवं भूतनाथ का काफी हिस्सा भूमाफ़िया पचा गए. हालत यह है कि न बड़ागांव गेट में दरवाजा है और न ही किसी खिड़की में. दतिया गेट से सत्तार बाबा की मीनार की ओर जाने वाले मार्ग पर कभी 12 इंच मोटा परकोटा हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने परकोटे को तोड़कर अपना मकान बना लिया. यदि झांसी के ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के दस्तावेज़ निकलवाए जाएं तो कई स्मारक वर्तमान में अपनी जगह से ग़ायब मिलेंगे. दोषी पुरातत्व विभाग है, जो इनके रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार है. विभाग का ही नियम है कि किसी भी पुरातत्व स्मारक के 200 मीटर के दायरे में नया निर्माण वर्जित है, लेकिन इसे देखने वाला कौन है. अतुल्य भारत का नारा बदहाल बुंदेलखंड में बेमानी हो चला है. यहां के 176 संरक्षित स्मारकों के लिए पुरातत्व विभाग के पास न तो पूरे कर्मचारी हैं और न ही धरोहरों के रखरखाव के लिए पैसा. हालत यह है कि पौने दो सौ स्मारक संरक्षित करने का दावा करने वाले विभाग के पास कुल 69 कर्मचारी हैं. 29,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले इन 176 संरक्षित स्मारकों में से 149 में कर्मचारी ही नहीं हैं और पुरातत्व विभाग के लोग लखनऊ, झांसी एवं इलाहाबाद में बैठकर काग़ज़ी खानापूरी कर रहे हैं. काग़ज़ी आंकड़ों के अनुसार, गत वर्ष इन स्मारकों पर 1.53 करोड़ रुपये ख़र्च हुए.

बुंदेलखंड प्राचीन धरोहरों के लिए प्रसिद्ध और समृद्ध रहा है. यहां के कण-कण में इतिहास समाहित है. इन स्थलों की पहचान के बाद संरक्षण की ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की बनती हैं, लेकिन शासन एवं पुरातत्व निदेशालय की अनदेखी से यहां के पुरातात्विक महत्व के 50 से ज़्यादा स्थल लावारिस हालत में हैं और असुरक्षित एवं असंरक्षित होने के कारण अपना अस्तित्व खो देने की कगार पर पहुंच गए हैं. पुरातनकाल की उक्त गौरव गाथाएं ब्रिटिश शासनकाल में भी उपेक्षित रहीं. बावजूद इसके यदि प्राचीन स्थल, मंदिर, किले और स्मारक अपनी संप्रभुता बचाए है तो यह इनका अपना सौभाग्य है, किसी का एहसान नहीं. कालांतर में कुछ स्मारक ज़मींदोज़ हो गए. इतिहास को साक्षी मानकर ऐसे तमाम स्थलों की खोज की गई. आज़ादी के बाद जहां-तहां हुई खुदाई में तमाम अवशेष और स्मारक भी मिले. इनके रखरखाव की ज़िम्मेदारी प्रदेश के पुरातत्व विभाग को दी गई. उसने सैकड़ों स्थलों की खुदाई कर चिन्हित भी किया है. इनमें से 35 स्थलों को विभाग ने संरक्षित घोषित किया है, जबकि 16 स्थल प्रतीक्षा सूची में हैं. इन स्थलों के संरक्षण के नाम पर विभाग सिर्फ़ साइन बोर्ड एवं पत्थर लगाने तक सीमित रहा. इन स्थलों की देखरेख के लिए पर्याप्त अमला नहीं है. विभाग के पास सिर्फ़ चार चौकीदार हैं, जिनमें से दो बरुवा सागर किले, एक-एक झांसी मंदिर एवं पनवाड़ी के शांतिनाथ मंदिर में तैनात हैं. बाक़ी बचे स्थल लावारिस हालत में हैं. पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की मानें तो संरक्षण के नाम पर मात्र ढाई लाख रुपये का बजट जारी होता है, जिसमें बिजली-पानी के बिल के अलावा सर्वे पर जाने वाली टीम का ख़र्चा भी शामिल है. पर्याप्त बजट न मिलने से इन महत्वपूर्ण स्थलों की सही तरीक़े से देखभाल नहीं हो पा रही है. विभाग के पास न तो इंजीनियर हैं और न कर्मचारी. अर्से से इन सभी के पद रिक्त पड़े हैं.

क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी ए के दुबे ने बताया कि निदेशालय एवं शासन का कई बार ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. यदि शासन एवं निदेशालय जल्द ही इन स्थलों पर ग़ौर नहीं करेगा तो इनके धूल में मिलने के बाद दोबारा खोज पाना नामुमकिन हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

एक जमाने में सभी दरवाजों के ऊपर एक ताम्रपात लगा रहता था, जिसमें पूरा विवरण होता था यह ताम्रपात तीन इंच मोटा और एक फुट लंबा हुआ करता था. बड़ागांव दरवाजे पर लगे ताम्रपात के प्रत्यक्षदर्शी आज भी जीवित हैं, लेकिन यह ताम्रपात कुछ वर्षों पहले रातोरात चोरी हो गया.

संरक्षित स्थल एक नज़र में

कुल संख्या-34.

झांसी में तीन, बरुवासागर में एक, पनवाड़ी में एक, तालबेहट में आठ, महरौनी में छह, ललितपुर में नौ, मडावरा में तीन एवं चरखारी में तीन.

संरक्षण के लिए प्रस्तावित-16.

चरखारी में एक, कुलपहाड़ में दो, महोबा में पांच, कुपनवाड़ी में एक, मऊरानीपुर में एक, बामौर में एक, बंगरा में दो, मऊ में तीन.

बुंदेलखंड 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की जोरदार तैयारी कर रहा है. वहीं किले के बाहर संग्राम की झलक दिखाती रणबांकुरों की प्रतिकृतियां एवं स्थल देखरेख न होने से बदहाली की कगार पर हैं. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच लड़े गए भीषण युद्ध का चित्रण मूर्तियों के माध्यम से किया गया है. इसका निर्माण बीएचईएल और पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया था. इस स्थल का लोकार्पण तत्कालीन राज्यपाल सत्य नारायण रेड्डी ने 21 फरवरी 1993 में किया था. इसका उद्देश्य युद्ध के दौरान अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों और उनसे लोहा लेती झांसी की सेना एवं महारानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को दिखाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख ले सकें . एक अनुमान के मुताबिक़, तीन-चार सौ देशी-विदेशी सैलानी प्रतिदिन किला देखने आते हैं, जो इस स्थल को भी देखते हैं. प्रतिकृतियों के बारे में जानकारी देने के लिए लगाई गईं पट्टिकाएं उखड़ चुकी हैं. प्रतिकृतियों का पेंट भी उखड़ने लगा है. हमीरपुर जनपद के कुरारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले झलोखर गांव में भुवनेश्वरी देवी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है. ललितपुर के पाली-बालाबेहट मार्ग पर बीहड़ में लगभग एक हज़ार वर्ष पुरानी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक ऐसी विशाल प्रतिमा दम तोड़ रही है, जिसके मुक़ाबले की कोई कृति उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कहीं नहीं है. पाली-बालाबेहट मार्ग के ग्राम दुधई के बीहड़ में सैंड स्टोन की चट्टान काटकर बनाई गई लगभग 56 फीट की यह विशाल प्रतिमा कुछ वर्षों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है. दशकों से लगातार वर्षा का पानी गिरने, काई, हवा और धूप की मार से इसका मूल स्वरूप क्षतिग्रस्त होता जा रहा है. देवगढ़ के दशावतार मंदिर, तालबेहट किले, सीरोन एवं सिरसी की गढ़ी की हालत भी काफी ख़राब है.

हम भारतीय मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में एएमयू की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा कर देखने की आदत पाल ली है.

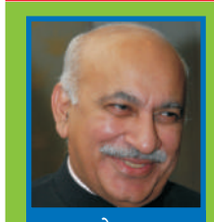

एम जे अकबर

पटकथाएं लिखने के बाद अमर सिंह अब अभिनय करेंगे

अमर सिंह को किस भूमिका के लिए अपनी अभिनय क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत है, चौदह सालों तक मुलायम सिंह यादव के सहयोगी की भूमिका में या फिर किसी मलयालम फ़िल्म में डिंपल कपाड़िया के पति की भूमिका में?

राजनीति में उम्र को मापने के लिए घटनाओं का इस्तेमाल होता है, समय का नहीं. साझेदारियां और आपसी सहयोग बरक़रार रहें, इसके लिए संबंधों में आंतरिक विश्वास का होना ज़रूरी है, ताकि वे ग़लतफहमियों और संदेहों के दायरे से बाहर निकल सकें. राजनीति की नसों में ख़ून नहीं बहता, बल्कि पारा बहता है. राजनीति मानवीय है और जब व्यक्तिगत अहम की बात आती है तो राजनीतिक चर्चाएं अक्सर बेतुकी लगने लगती हैं. श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ निस्संदेह प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन यह गुण अक्सर उनकी स्वाभाविक विद्रोही विचारधारा के साथ आते हैं. पार्टियों के शीर्ष नेता अपने कनिष्ठों की प्रतिभा से ख़ुश तो होते हैं, लेकिन उनकी खामियां उन्हें रास नहीं आतीं. प्रतिभासंपन्न लोग अक्सर बेतुकी बातों को आईने में देखने की चाहत रखते हैं, लेकिन जब यह आईना उल्टा होता है तो तस्वीर का रुख़ पूरी तरह बदल जाता है. ईर्ष्या और धोखा महत्वाकांक्षा के सबसे बड़े साथी होते हैं. प्रतिभावान लोग यदि महत्वाकांक्षी न हों तो वे शायद राजनीति में नहीं होते.

कोई भी संस्था, चाहे वह पार्टी हो या सरकार, विवाद रहित स्थायित्व की इच्छा रखती है. वह उन लोगों को भी चुप रखना चाहती है, जो ख़ुद को प्रतिभाशाली समझते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं और ज़िम्मेदारियों के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें दी गई ज़िम्मेदारियां उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करती हैं. जयराम रमेश एक विद्वान और चतुर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान अक्सर फिसल जाती है. पर्यावरण मंत्री के रूप में उनका कामकाज भी अच्छा रहा है. कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात पर क़ायम रहने का जज़्बा भी दिखाया है. लेकिन सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना की मांग यही होती है कि आपको अपनी व्यक्तिगत सोच छुपाकर रखना होता है. चीन पर उनका दिया गया बयान सही भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसे खुलेआम व्यक्त करने की ग़लती कर दी, जो शायद सही नहीं है. अक्सर कुछ लीक से हटकर करने की चाहत रखने वाले अमर सिंह इस मामले में रमेश के मुक़ाबले ज़्यादा सतर्क राजनीतिज्ञ हैं. ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में अपने व्यक्तिगत नज़रिए को परे रखने में वह काफी हद तक सफल रहे हैं. संबंधों में दुराव आ जाए तो इसका पहला असर पुरानी यादों पर पड़ता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमर सिंह की ख़ूबियों को नज़रअंदाज़ करना शायद ज़्यादती होगी. मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट तो मिलते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में ज़्यादा महत्वपूर्ण है विनिंग वोट हासिल करना. बंद दरवाजे के अंदर तैयार की गई रणनीतियां मुश्किल परिस्थितियों में विजेता को उपविजेता में तब्दील कर सकती हैं. रामपुर के चुनावी अखाड़े में किस तरह जयाप्रदा वास्तविक बेगम में तब्दील हो गईं, भारतीय लोकतंत्र के किसी

भी विश्लेषण में इसकी चर्चा किए बग़ैर नहीं रहा जा सकता. अमर सिंह ने अब अपने सामने और भी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है, ख़ुद को नए सिरे से पेश करने का.

राजनीति के मैदान में अभिनेता अक्सर फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशंसा और प्रशंसकों को संभालने में महारत हासिल होती है. उन्हें ग्लैमर के विज्ञान की अच्छी समझ होती है और वे इस तथ्य से भी भलीभांति वाक़िफ़ होते हैं कि ग्लैमर की चमक ज़्यादा दिनों तक क़ायम नहीं रहती. मधुबाला आज तक आइकॉन बनी हुई हैं तो इसकी एकमात्र वजह यही है कि क़रीब तीस साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई, जब वह अपने फ़िल्मी करियर की बुलंदियों पर थीं. डिंपल कपाड़िया एक अपवाद हैं, क्योंकि फ़िल्म बॉबी ने उनकी छवि को हमेशा के लिए एक सोलह साल की बाला के रूप में तब्दील कर दिया. फिर उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है, जो किसी घरेलू महिला से मेल नहीं खाता. अभिनेत्रियां शादी को सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर के रूप में देखती हैं. कुछ अभिनेत्रियों को यह एहसास हो जाता है कि चालीस की दहलीज पार करने के बाद फ़िल्मी दुनिया में उनके लिए ख़ास जगह नहीं बचती, लेकिन यह उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि गुमनामी के अंधेरे में खो जाएं और वे कोई नया करियर अपना लेती हैं. पुरुष अभिनेता यदि अपने शरीर को लेकर सावधान रहे तो उसका करियर थोड़ा लंबा खिंच सकता है. राजनीतिज्ञों में इतना साहस नहीं होता कि वे अभिनय की दुनिया में क़दम रखें, लेकिन अमर सिंह इसके लिए तैयार हो रहे हैं. राजनीति के मैदान में कई पटकथाएं लिखने के बाद अब अमर पटकथा के हिसाब से अभिनय के लिए कमर कस रहे हैं.

राजनीति हो या अभिनय, इन दोनों पेशों की ख़ासियत होती है कि दर्शक नहीं मिले तो आप किसी काम के नहीं हैं. मुलायम सिंह के साथ उनकी साझेदारी फ़ायदे का सौदा थी, क्योंकि किसी भी हाल में पूरी नहीं तो थोड़ी-बहुत सफलता की गारंटी होती थी. वैसे भी वह कांग्रेस पार्टी की तरह किसी मल्टी स्टारर फ़िल्म का हिस्सा नहीं थे. अमर-मुलायम की कहानी में बस दो लोगों की ही भूमिका होती थी और अमर सिंह अपने नेता मुलायम सिंह के पूरक की भूमिका में फिट बैठते थे. संबंधों में यह दुराव भी अवश्यंभावी था और फिर उनके रास्ते भी अलग होने ही थे. मुलायम सिंह के पास समर्थक तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन क्या वह इसे जीत के फ़ार्मूले में तब्दील कर सकते हैं? अमर सिंह के पास जीत का फ़ार्मूला तो है, लेकिन इसे आजमाने के लिए उनके पास समर्थक कहां हैं?

जब इन सवालों का जवाब ढूंढा जाता है तो जवाब अक्सर विरोधाभासों के तंग गलियारों में गुम हो जाते हैं. इसका सही जवाब तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद ही मिल सकता है. यदि अमर सिंह अपने स्वजातीय ठाकुर मतदाताओं का वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो इससे मुलायम सिंह के मुक़ाबले कांग्रेस को ज़्यादा नुक़सान होगा, क्योंकि वह ऊंची जातियों के साथ अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का ताना-बाना बुन रही है. वोटों का यह बंटवारा मायावती के लिए भी ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि उनका वोटों का आधार अभी भी क़ायम है. हालांकि दलितों के अलावा अन्य जातियों के उनके वोट बैंक में लगातार कमी आती जा रही है. नृत्य को यदि अपनी इच्छाओं की भावाभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है तो राजनीति में भी कथनी और उद्देश्यों के बीच ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. परिष्कृत नाटकीयता में लोकलुभावन चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी है, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शब्दाडंबर ही काफी होता है. मतदान केंद्र तक पहुंचते-पहुंचते मतदाता भी इसी शब्दाडंबर में उलझ कर रह जाता है और अविश्वसनीय बातों पर भी विश्वास कर बैठता है.

अमर सिंह कैमरे के सामने कहीं भी फिट बैठते हैं, चाहे वह स्टूडियो हो या फिर धूल और गर्द से भरी गलियां.

feedback@chauthiduniya.com

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की समस्याएं

सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि अलीगढ़ से मेरा कोई ख़ास वास्ता नहीं है. मुझे कभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पढ़ाई करने का मौक़ा नहीं मिला. फिर भी कुछ ऐसी वजहें बताना चाहूंगा, जिनके चलते मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय से मेरा भी कुछ रिश्ता है. मैंने अपना करियर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही बतौर जूनियर लेक्चरर शुरू किया था, लेकिन अगले दो सालों के भीतर ही मैं दिल्ली तक पहुंच चुका था नई नौकरी की तलाश में. दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में मैंने इंटरव्यू दिया. हर जगह मुझसे एक ही सवाल किया जाता, आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट छोड़ कर कॉलेज में क्यों आना चाहते हैं? मेरे पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था, क्योंकि सही जवाब देने से मेरे वे घाव हरे हो जाते, जिन्हें मैं छुपाना चाहता था.

दूसरी बात, मेरी सबसे बड़ी बेटी ने अलीगढ़ में प्री-यूनिवर्सिटी से बीएससी तक चार साल की पढ़ाई की है. पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उसने यहां रुकने से इंकार कर दिया और हिमाचल चली गई. मेरे बाक़ी किसी भी बच्चे ने अलीगढ़ में पढ़ाई करने की इच्छा नहीं दिखाई. मेरे इस व्यक्तिगत अनुभव में कुछ मर्म तो नहीं छुपा है? एएमयू के मामलों से अपने जुड़ाव की तीसरी वजह बताने के लिए मैं किसी तीसरे शख़्स के बयान की मदद लूंगा. मशहूर उर्दू लेखक प्रो. राशिद अहमद सिद्दीकी, जो इसी विश्वविद्यालय के छात्र और फिर शिक्षक रहे हैं, ने एक बार लिखा था, जब भी मेरा सामना किसी सुशिक्षित और अच्छे संस्कारों वाले भारतीय मुस्लिम से होता है, तो मैं यही सोचता हूं कि उसने एएमयू से शिक्षा हासिल की होगी. यदि मेरा अंदाज़ा सही निकला तो मैं यह सोचकर ख़ुश हो लेता हूं कि ऐसे प्रतिभाशाली नौजवान एएमयू से ही निकल सकते हैं. यदि अंदाज़ा ग़लत निकला तो मुझे निराशा होती है, यह सोचकर कि ऐसे प्रतिभाशाली नौजवान को, जिसे अल्लाह ने इतनी सारी ख़ूबियों से नवाजा है, एएमयू में पढ़ने का मौक़ा क्यों नहीं मिल पाया. जब मैंने यह पढ़ा तो मैं लेखक के संकीर्णतावादी विचारों पर आश्चर्यचकित रह गया. भारत में कौन ऐसा पढ़ा-लिखा मुसलमान होगा, जो एएमयू के विचारों से प्रभावित न हुआ हो, चाहे उसने वहां पढ़ाई की हो या नहीं. एक भारतीय मुस्लिम होने के नाते मेरा भी इन सब बातों से कुछ वास्ता ज़रूर है. एएमयू से संबंधित मामलों में यह वास्ता कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यह एक भावनात्मक मुद्दा है. राजनीति में अपना भविष्य देखने वाले और मुस्लिम हितों के संरक्षक होने का तथाकथित दावा करने वाले अक्सर यह मांग करते हैं कि एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र को दोबारा बहाल किया जाना चाहिए. यह मांग उठी नहीं कि हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर शुरू हो जाता है.

मेरा मानना है कि मुस्लिम कौम को हमेशा के लिए अलीगढ़ मुद्दे के नाम पर बंधक नहीं बनाया जा सकता. इसलिए हम सब लोगों की भलाई इसी में है कि एएमयू एक शैक्षिक संस्थान के रूप में अपनी खोई हैसियत हासिल करे और इसका माहौल शांतिपूर्ण बना रहे. शैक्षिक गतिविधियों के लिए मानसिक शांति और अनुकूल माहौल की ज़रूरत होती है, लेकिन निराशाजनक तथ्य यह है कि एएमयू में इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी है. अपनी स्थापना के बाद से ही एएमयू विवादों और दावों-प्रतिदावों के बीच उलझा रहा है. सबसे पहले तो इसकी स्थापना ही विवाद का विषय रही. यदि कोई इस बात से इत्तेफ़ाक़ न रखता हो तो साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल के पुराने अंकों पर नज़र डाले. अबुल कलाम आज़ाद की इस पत्रिका का प्रकाशन पिछली सदी की शुरुआत में उसी दौरान शुरू हुआ था. मायो कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदलने की तैयारी हो रही थी.

मुझे लगता है कि हम भारतीय मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में एएमयू की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा कर देखने की आदत पाल ली है. अलीगढ़ के साथ जुड़े अलीग शब्द, इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव और इसके अल्पसंख्यक चरित्र जैसे राजनीतिक नारों के चलते भी ऐसा हुआ है. एएमयू की इस भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में द अलीगढ़ ओल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन ने भी बख़ूबी योगदान किया. इस सारे शोरशराबे में सबसे पहले सच्चाई ही छुप जाती है. विवादों और दावों-प्रतिदावों के इस जंजाल में यह बात दबकर रह जाती है कि एएमयू सबसे पहले एक शैक्षिक संस्थान है. एएमयू में कोई बदलाव या सुधार से पहले इस पर विचार होना चाहिए कि एक शैक्षिक संस्थान के रूप में इसकी क्या भूमिका है. यदि यह अपनी उस भूमिका का निर्वाह कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए. नीचे लिखी बातों में मैं एएमयू से वास्ता रखने वाले हर इंसान का ध्यान कुछ ऐसे तथ्यों की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा, जिन्हें विश्वविद्यालय से संबंधित हर चर्चा में दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन जो कौम के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण हैं.

अक्सर कहा जाता है कि एएमयू में शिक्षा का स्तर तेज़ी से गिर रहा है. यहां से निकले छात्र अब पहले की तरह योग्य नहीं होते और देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में यह अपना वजूद खो चुका है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि ऐसा क्यों हो रहा है. सच्चाई यह है कि 1947 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में देश में काफी प्रगति हुई है. एएमयू यदि अपनी पुरानी हैसियत या अपना अखिल भारतीय स्वरूप खो चुका है तो इसके लिए यह ख़ुद कतई ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इसकी कई अन्य वजहें भी हैं. बदलते दौर में सुदूर एर्नाकुलम या त्रावणकोर से महज़ बीए की डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को अलीगढ़ भेजना आर्थिक लिहाज़ से तर्कसंगत नहीं लगता. हर तरह की शिक्षा अब पूरे देश में उपलब्ध है. इसके चलते एएमयू में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों के कैचमेंट एरिया में भी बदलाव आया है और सच्चाई यह है कि अब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रहा. हालांकि कहने के लिए इसके नाम के साथ सेंट्रल शब्द अभी भी जुड़ा हुआ है. एएमयू में पढ़ाई के लिए आने वाले अधिकांश छात्र अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बिहार के ही होते हैं और वास्तविकता यह है कि अब यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रांतीय विश्वविद्यालय बनकर रह गया है.

कैचमेंट एरिया में आया यह बदलाव छात्रों के वर्ग चरित्र, भाषा और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी देखने को मिलता है. देश के विभाजन से पहले तक एएमयू संभ्रांत लोगों की संस्था थी. भारतीय मुस्लिम समाज के ऊपरी तबके के छात्र इसके कैचमेंट एरिया में आते थे. यह सामंतवादी मुस्लिम समाज का अंतिम गढ़ था, जो उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू-मुस्लिम संस्कृति से भलीभांति परिचित था. काली शेरवानी पहनने वाला यह तबका पारसी पुट के साथ खालिस उर्दू ज़ुबान बोलता था और हाफ़िज़ एवं ग़ालिब के शेरों को गुनगुनाता था, लेकिन अब यह तबका ही नहीं रहा. देश के विभाजन और जमींदारी क़ानून के ख़ात्मे के बाद भारत में मुसलमानों के जमींदार वर्ग का अस्तित्व भी ख़त्म हो गया. इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और जो बचे, वे सामाजिक बिखराव के चलते निचले तबकों में शामिल होने को मजबूर हो गए या फिर उनका दुखद अंत हो गया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के धनाढ्य किसान एएमयू के लिए नया कैचमेंट एरिया बन गए. अब आपको एसएस हॉल के गलियारों में हाफ़िज़ और ग़ालिब के शेरों को गुनगुनाते छात्र नहीं मिलेंगे. इसके बदले चालू अवधी या बिहारी ज़ुबान में एक-दूसरे पर चिल्लाते छात्र मिलते हैं. मुस्लिम समाज से जुड़े और एएमयू में पढ़ाई कर चुके केंद्र सरकार के एक पूर्व अधिकारी ने मुझे बताया कि कई दशकों बाद जब वह एएमयू पहुंचे तो छात्रों को बिना शेरवानी पहने शमशाद मार्केट में घूमते देख भौचक्के रह गए. उन्होंने यह भी बताया कि उनके जमाने में ऐसा करना तो दूर, सोचना भी गुनाह माना जाता था. मुझे हार कर उन्हें बताना पड़ा कि समय बदल चुका है और आप पसंद करें या नहीं, लेकिन बदलाव की इस बयार से एएमयू भी अछूता नहीं है.

किसी विश्वविद्यालय में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं छात्र, शिक्षक और प्रशासन. दूसरा तथ्य यह है कि आईआईटी, आईआईएम, जेएनयू एवं मुंबई या दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे सभी अच्छे शैक्षिक संस्थान संभ्रांतवादी हैं. कोई भी फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, चाहे वह कितना भी सुनियोजित या विस्तृत क्यों न हो, तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि छात्रों की गुणवत्ता पर ध्यान न दिया जाए. उक्त सभी संस्थानों की एक बड़ी ख़ासियत यह है कि वे नियुक्ति प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि छात्रों के नामांकन में भी काफी सावधानियां बरतते हैं.

इस तर्क का लब्बोलुवाब यह है कि सुधार की कोई भी कोशिश तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक कि इससे संबंधित सामाजिक कारकों पर ध्यान नहीं दिया जाता. प्रशासकों को यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि शैक्षणिक सुधार एक लंबी प्रक्रिया है. इसके परिणाम एक दिन में नहीं मिल सकते. इसके लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है. हम बीज बो सकते हैं, लेकिन पौधे के उगने और उसमें फल लगने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है, जो गुज़रे जमाने के मशहूर शिक्षक शेख सादी कहा करते थे. एक राजा था. एक दिन वह अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकला. रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो पौधों में पानी डाल रहा था. राजा ने उससे पूछा, तुम उम्र के आख़िरी पड़ाव पर पहुंच चुके हो. क्या तुम्हें लगता है कि जब तक इन पौधों में फल लगेंगे, तब तक तुम ज़िंदा रहोगे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं किसी भी दिन मर जाऊंगा, लेकिन मैं इन पौधों की देखभाल अपने लिए नहीं कर रहा हूं. यह काम तो मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं. जीवन ऐसे ही चलता है. मेरे पुरखों ने जो बीज बोया, उसके फल का स्वाद मैंने चखा. अब वही काम मैं कर रहा हूं, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां इनका भोग कर सकें.

जीवन के इस मंत्र को यदि हम याद रखें तो कितना अच्छा हो!

औसाफ अहमद

(लेखक मशहूर शिक्षाविद् और इस्लामिक बैंकिंग के विशेषज्ञ हैं)

feedback@chauthiduniya.com

प्रियंका, राहुल और कांग्रेस

26 अप्रैल-2 मई के अंक की आवरण कथा पढ़ी. प्रियंका और राहुल की कार्यशैली से रूबरू हुआ. लेखक ने बड़ी बारीकी से विषय पर प्रकाश डाला है. वास्तव में प्रियंका और राहुल को ऐसे गुण विरासत में मिले हैं, जिससे दोनों भाई-बहन कांग्रेस की छवि और बढ़िया बना सकते हैं.

-जसवंत सिंह, *कटवारिया सराय, दिल्ली.*

और जनपयोगी बनाएं

आज मैंने पहली बार 3 मई-9 मई का चौथी दुनिया पढ़ा. मन प्रसन्नता से भर गया. इस अख़बार में वर्तमान स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है. बच्चों की कहानियां और स्वास्थ्य से संबंधित आलेख आदि प्रकाशित करके इसे और भी जनोपयोगी बनाया जा सकता है.

-आनंद मोहन रिछारिया, *सागर, मध्य प्रदेश.*

गठबंधन सरकारें

नीतीश एवं शरद के रिश्तों में तल्खी का समाचार राजनीतिक कुश्ती का पुराना दांव-पेंच ही लगता है. हर बार चुनाव से पहले इस तरह की बातें होना नया काम नहीं है. यह बात तो साफ है कि अब किसी भी राज्य में एक दल की सरकार संभव नहीं. लेकिन जनता पहले की तरह बेवकूफी करती रहेगी, यह मान लेना भी भूल होगी. मतदाताओं को चाहिए कि वे एक ही दल को पूर्ण बहुमत दें, ताकि वह पूरे पांच साल के लिए सरकार बनाए और राज्य का विकास एवं जनता की भलाई बिना किसी बाधा के कर सके.

-ए के शर्मा, *हुगली, पश्चिम बंगाल.*

श्रमिकों का पलायन

भारत में भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब है. कोई भी सकारात्मक क़दम नहीं उठाया जा रहा है. आख़िर वजह क्या है? बिहार से श्रमिकों का पलायन निरंतर बढ़ता जा रहा है. हम चाहते हैं कि आप अपने अखबार में पंचायती राज, मनरेगा, जनसंख्या एवं खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण निर्धनता, जलसंकट एवं कृषि नीति पर आधारित आलेख सरकार के पक्ष समेत प्रकाशित करें. आज हमारे देश की अहम चुनौती कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र हैं और यही दोनों ख़तरे में हैं.

-उपेंद्र, संतोष, विनोद एवं मुन्ना कुमार, *परसा-सारण, बिहार.*

ज़रा हटके है चौथी दुनिया

बहुत दिनों से इच्छा थी कि हिंदी में कोई ऐसा अख़बार निकले, जो अन्य अख़बारों से थोड़ा अलग हो. इस अख़बार की साजसज्जा और छपाई देखकर मन ख़ुश हो गया. इसकी क़ीमत भी वाजिब है, लेकिन अख़बार सहज उपलब्ध नहीं है. इस ओर हो सके तो ज़रूर ध्यान दें.

-रीना चौधरी, *कानपुर, उत्तर प्रदेश*

वित्त-व्यापार विषयक आलेख

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. यदि इसमें व्यापार और स्टॉक मार्केट से संबंधित विषयों पर भी आलेख प्रकाशित हों, अच्छा रहेगा. दरअसल स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग एवं म्युचुअल फंड की ख़रीद-फरोख्त अब कंपनियों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आम आदमी भी इसमें दिलचस्पी रखता है.

-राजकिशोर, *टाटा नगर, झारखंड.*

साहसिक कार्य

त्रिदीब रमण का लेख-राजा, टाटा, अंबानी और नीरा राडिया पढ़ा. इस प्रकरण पर विस्तार से लेख प्रकाशित करने का जो साहसिक कार्य आपने किया है, वह तारीफ़ के क़ाबिल है. किसी अख़बार की निष्पक्षता ही उसके प्रति जनसाधारण का विश्वास मज़बूत करती है.

-उमाशंकर मिश्र, *रामपुर, उत्तर प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

भैरो सिंह शेखावत और आचार्य राममूर्ति का जाना

मई दो हज़ार दस ने दो ऐसे लोगों को हमसे छीन लिया, जिन्होंने भारत की राजनीति और सामाजिक विकास के संघर्ष में बड़ा योगदान दिया था. भैरो सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति में सामान्य परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और रजवाड़ों तथा सामंतों की मानसिकता वाले प्रदेश में अपना ऐसा स्थान बना लिया, जो किसी के लिए भी ईर्ष्या का कारण बन सकता है. आचार्य राममूर्ति ने भी सामान्य परिवार में जन्म लेकर धीरेंद्र मजूमदार के साथ उनके निर्देशन में पहले बुनियादी शिक्षा का साकार स्वरूप बनाने में तथा बाद में सर्वोदय दर्शन का क्रांतिकारी स्वरूप निखारने में अपने को खपा दिया. अपनी ज़िंदगी की आख़िरी सांस तक आचार्य राममूर्ति क्रांति के जीवित शब्दकोष बने रहे.

भैरो सिंह शेखावत को भारतीय राजनीति में एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाएगा, जिसने केवल और केवल दोस्त बनाए. उनके दोस्त सभी दलों में थे. अटल जी उनके नेता भी थे और दोस्त भी थे. जब तक अटल जी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, बिना भैरो सिंह शेखावत की सलाह के क़दम नहीं उठाते थे. भैरो सिंह शेखावत कभी-कभी उदास भी हो जाते थे. मैं इसका गवाह हूं. उन्होंने सालों पहले कई बार कहा कि उन्होंने अटल जी से बार-बार कहा है कि वह भाजपा का दायरा तोड़ देश में घूमें और देश को सही आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार करें. यह बात अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले की है. भैरो सिंह जी बताते थे कि अटल जी भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन संघ का डर उन पर इस कदर बैठा है कि वह कोई नया क़दम नहीं उठा सकते. भैरो सिंह जी को लगता था कि अटल जी में देश को उद्वेलित करने की असीम क्षमता है. वह स्वयं को दूसरे नंबर का सब कुछ संगठित करने वाला व्यक्ति ही मानते थे.

सन् अट्ठासी के प्रारंभ की बात है, शायद जनवरी की. जयपुर से फोन आया और फोन पर भैरो सिंह थे. उन्होंने मुझसे जयपुर आने का आग्रह किया. मैं गया तो उन्होंने कहा कि वह ख़ामोशी से वी पी सिंह से मिलना चाहते हैं. तीसरे दिन भैरो सिंह जी दिल्ली आए और वी पी सिंह से मुलाक़ात की. उन्होंने वी पी सिंह से कहा कि वह कहेंगे तो वह भाजपा भी छोड़ देंगे, पर देश को बुनियादी परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए. वी पी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबरी मस्जिद के हल में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया तथा चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में तो उन्होंने इस मसले को लगभग हल ही कर लिया था. शरद पवार यदि राजीव गांधी को दो दिन पहले इसकी ख़बर न देते तो आज बाबरी मस्जिद विवाद का हल निकल चुका होता.

उपराष्ट्रपति रहते हुए भैरो सिंह शेखावत जी ने ग़रीबों के लिए बहुत से क़दम सुझाए. जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अंत्योदय योजना प्रारंभ की, जिसका ग़रीबों को बहुत फ़ायदा हुआ. उनके चलने का ढंग, उनके बात करने का तरीक़ा, उनका चेहरा मोहरा उन्हें आम आदमी के नज़दीक ज़्यादा ले जाता था. उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती चंद्रशेखर जी से थी. वह जब दिल्ली आते, अपना ज़्यादा समय चंद्रशेखर जी के साथ गुज़ारते. दोनों की आपस में अनौपचारिक बातचीत इतनी मीठी होती थी कि सुनने का लोभ कम ही नहीं होता था. चौथी दुनिया के वह पहले भी प्रशंसक थे और अंत तक रहे. उन्होंने अपने आप कहा कि वह चौथी दुनिया के लिए लिखेंगे. विषय भी उन्होंने स्वयं ही तय कर लिया था, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के विवाद के कारण और उनका हल. हम अंत तक प्रतीक्षा करते रहे, पर उनकी सेहत ने उन्हें उनकी यह इच्छा पूरी नहीं करने दी.

आचार्य राममूर्ति मूलतः एक शिक्षक थे. उनका सपना जननायक बनने का नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि समाज परिवर्तन के काम में लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही तैयार हों. उन्होंने अपना सारा जीवन ऐसे लोगों को तैयार करने में लगा दिया. जहां भी ऐसे लोगों के मिलने की संभावना होती, आचार्य जी वहां पहुंचने की कोशिश करते. उनके कुछ मतभेद तो अपने सर्वोदय आंदोलन के साथियों से भी थे. जब जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा बाद में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू किया तो आचार्य जी ने सबसे पहले उसका केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि पहले सिपाही की तरह उसमें कूद पड़े. उन्होंने संपूर्ण क्रांति के भाष्य का ज़िम्मा ख़ुद संभाल लिया.

इतिहास क्या मूल्यांकन करेगा भैरो सिंह शेखावत और आचार्य राममूर्ति का, पता नहीं, पर दोनों जाते हुए दुखी थे. देश की हालत, ग़रीबों की अनदेखी, इसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद का बढ़ना इन्हें चिंतित किए था. दोनों के अनुयायी उनकी इस चिंता को कितना समझेंगे, पता नहीं, पर अगर समझ सकें तो वे इस देश के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे.

आचार्य राममूर्ति की भाषा, विद्वान की भाषा नहीं थी, लेकिन विद्वान की भाषा से ज़्यादा तार्किक और ज़्यादा समझ में आने वाली भाषा थी. दिखने में सीधे-सादे, पहनने में ग्रामीण भारत की झलक देने वाले और समझाने में मार्क्स एंजेल का आभास देने वाले आचार्य राममूर्ति का जितना उपयोग होना चाहिए, उतना हो नहीं पाया. वी पी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आचार्य जी के सामने प्रस्ताव रखा कि वह राज्यपाल पद स्वीकार कर लें, पर आचार्य जी ने इसे अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह शिक्षा पर कोई बुनियादी काम करना चाहते हैं. वी पी सिंह सरकार ने राममूर्ति कमीशन बनाया, जिसने शिक्षा में बुनियादी सुधार की सिफ़ारिशें कीं. यह पहला कमीशन था, जिसने लंबा समय नहीं लिया और डेढ़ साल के भीतर अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को सौंप दी. अफसोस कि वह रिपोर्ट किसी अलमारी में बंद पड़ी है.

आख़िरी दिनों में आचार्य जी बिल्कुल अकेले रह गए थे. शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन उनका मस्तिष्क उनका सारथी था. उनका परिवार बहुत छोटा था, पर उसका सुख उन्हें नहीं मिला. उनके साथी कृष्ण कुमार जी और राम गुलाम जी उनके साथ आख़िरी समय तक रहे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लिखना चाहता हूं. जार्ज फर्नांडिस जब बीमारी की वजह से अशक्त हो गए तो अपने सारे मतभेद भुलाकर नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा. इसी तरह जब आचार्य राममूर्ति बिल्कुल अकेले रह गए, शरीर कमज़ोर होने लगा तो नीतीश कुमार ने एक समिति बना आचार्य जी को उसका अध्यक्ष बना दिया. आचार्य जी अपने आख़िरी दिनों में पटना में आराम से रहे. नीतीश से आचार्य जी की कभी अंतरंगता नहीं रही, न वैयक्तिक और न राजनैतिक. लेकिन जयप्रकाश आंदोलन के दौरान जितना संपर्क नीतीश कुमार का आचार्य जी से रहा, उसे वह भूले नहीं. इसीलिए जब आचार्य जी का साथ उनके परिवार वालों ने भी छोड़ दिया तो नीतीश कुमार आगे आए और आंदोलन में रहे सहयात्री का धर्म निभाया. आज राजनीति में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते. ऐसे उदाहरण देखने का मन करता है, क्योंकि यही राजनीति का मानवीय चेहरा है. नीतीश कुमार इसके उदाहरण हैं.

इतिहास क्या मूल्यांकन करेगा भैरो सिंह शेखावत और आचार्य राममूर्ति का, पता नहीं, पर दोनों जाते हुए दुखी थे. देश की हालत, ग़रीबों की अनदेखी, इसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद का बढ़ना इन्हें चिंतित किए था. दोनों के अनुयायी उनकी इस चिंता को कितना समझेंगे, पता नहीं, पर अगर समझ सकें तो वे इस देश के साथ अपना कर्तव्य निभाएंगे. भैरो सिंह शेखावत और आचार्य राममूर्ति को हमारा आख़िरी प्रणाम.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

आतंकवाद का रास्ता

फैसल शहजाद धनी है, ग्रेजुएट तक शिक्षा प्राप्त शहजाद दो बच्चों का बाप है और उसका पारिवारिक जीवन भी ख़ुशहाल है. उसके अपनी ज़िंदगी से दुखी होने का कोई कारण नज़र नहीं आता. फिर वह कौन सा कारण था, जिसके चलते फैसल टाइम्स स्क्वायर में बम रखने के लिए तैयार हुआ? फैजल के इस कृत्य ने पाकिस्तान में आतंकवाद के स्वरूप और चरित्र पर फिर से विचार करने को विवश कर दिया है. आमतौर पर यही माना जाता है कि आतंकवाद या उग्रवाद ग़रीबी और उससे उपजी निराशा का परिणाम है. अजमल कसाब इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ मज़दूरी करने वाले कसाब के सामने जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं न के बराबर थीं और आतंकी संगठनों द्वारा रंगरूट के रूप में बहाल किए जाने के लिए वह आसान लक्ष्य था. उक्त संगठन ऐसे युवाओं की ही ताक में लगे रहते हैं. छोटे शहर एवं कस्बे उनके निशाने पर होते हैं और इस काम में बेरोज़गारी उनकी मददगार होती है. हाथों में बंदूक़ लेकर चलने का लोभ संभाल पाना कसाब की उम्र के ग़रीब युवकों के लिए अक्सर मुश्किल होता है. मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसे समझना बेहद आसान है, लेकिन फैसल शहजाद समाज के इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता. सुख-सुविधा से भरपूर ज़िंदगी जी रहा फैजल आतंकवाद के रास्ते पर चलकर आख़िर क्या हासिल करना चाहता था, यह समझना किसी पहेली से कम नहीं है. फैजल के जैसे दूसरे युवा आतंक का रास्ता क्यों अख्तियार करते हैं, यह पता करना भी किसी रहस्य से कम नहीं है.

ऐसा लगता है, जैसे पाकिस्तानियों, ख़ासकर पाकिस्तानी युवाओं की मानसिक हालत ही कुछ ऐसी है, जिसके चलते वे हिंसा की ओर आकर्षित होते हैं. उनकी विचारशीलता ही उन्हें आतंक के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है. कोई शक नहीं कि जनरल जियाउल हक के सैन्य शासन और अफ़ग़ान युद्ध में पाकिस्तान की भागीदारी ने ऐसी सोच के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है. इस तथ्य को आफिया सिद्दीकी या यहां तक कि तालिबान को मिलने वाले समर्थन से भी समझा जा सकता है. हालांकि दो दशक पहले विमान दुर्घटना में जनरल जिया की मौत के बाद युवा वर्ग का एक छोटा तबका इस सोच से बाहर निकल उदारवादी रुख़ अपनाने में कामयाब रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा तबका अभी भी गुजरे दौर में ही जी रहा है और अपनी सोच को बदलने में नाकाम रहा है.

लेकिन ऐसी सोच का होना ख़तरे की घंटी है. अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि पाकिस्तानी सरजमीं पर आतंक की रणनीति बनाने के परिणाम कितने ख़राब हो सकते हैं. छात्रों को डर है कि उन्हें वीजा मिलने में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. पहले से ही अमेरिका में रह रहे पाक नागरिकों की शिक़ायत है कि अमेरिकी जनता उन्हें दुश्मन की नज़र से देखती है. इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है. सच्चाई यही है कि आज पूरी दुनिया आतंकवाद को पाकिस्तान से जोड़कर देखती है. ऐसा लगता है, जैसे तमाम आतंकी घटनाओं के सूत्र कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हैं और यह सच भी है. मुल्क के लिए इसके नतीजे भी बेहद नुक़सानदायक रहे हैं.

ऐसा लगता है, जैसे पाकिस्तानियों, ख़ासकर पाकिस्तानी युवाओं की मानसिक हालत ही कुछ ऐसी है, जिसके चलते वे हिंसा की ओर आकर्षित होते हैं. उनकी विचारशीलता ही उन्हें आतंक के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है. कोई शक नहीं कि जनरल जियाउल हक के सैन्य शासन और अफ़ग़ान युद्ध में पाकिस्तान की भागीदारी ने ऐसी सोच के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है.

आतंकवादियों को पराजित करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है उस सोच से मुक़ाबला करना, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है. संभव है कि तालिबान के ख़िलाफ़ चल रही लड़ाई में किसी तरह जीत हासिल हो जाए. देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में कई इलाक़ों को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने में कामयाबी भी मिली है. हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि बड़े नेताओं को गिरफ़्तार न किए जाने से आतंकियों की नकेल कसना अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है. ऐसे संकेत ख़तरनाक हैं. यदि सत्ता तंत्र के साथ तालिबान के सूत्रों को अभी बेनकाब और ध्वस्त न किया गया तो शायद यह भविष्य में कभी संभव भी नहीं हो पाएगा. हाल के दिनों में आर्मी हेड क्वार्टर पर हमला किया गया और रावलपिंडी में उन मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जहां शीर्ष सैन्य अधिकारी अक्सर आते-जाते रहते हैं. उक्त वारदातें मौजूदा हालात के ख़तरे का अहसास कराने के लिए पर्याप्त हैं और हम यदि इसे समझ नहीं पाए तो फिर दोबारा शायद ऐसे मौक़े न मिलें. यदि उत्तर-पश्चिम में तालिबान को नेस्तनाबूद करने का अभियान वास्तव में जारी भी रहता है, फिर भी हमें यह सोचना होगा कि उस मानसिकता को दूर करने के लिए क्या क़दम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते फैजल शहजाद जैसे युवा तालिबान के साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं.

अभी तो यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि शहजाद ने यह काम व्यक्तिगत स्तर पर किया है या फिर वह देश के विभिन्न हिस्सों से संचालित हो रहे विभिन्न आतंकी संगठनों में से किसी एक का हिस्सा है. ऐसे कई संगठन हैं. इनमें आपसी टूट-फूट से इतने छोटे-छोटे समूह बन गए हैं कि सबको याद रखना भी मुश्किल है. कई ऐसे संगठन हैं, जिन्होंने 9/11 के बाद अपने नाम बदल लिए हैं, जिससे यह काम और भी मुश्किल हो गया है. बड़े पत्रकारों को भी इनके नाम अपनी मेज पर लिखकर रखने पड़ते हैं, ताकि किसी नई वारदात की हालत में संभावित आरोपियों और उनके संगठनों के नाम की पहचान हो सके. लेकिन सवाल यह नहीं है कि फैजल शहजाद इनमें से किसी संगठन से जुड़ा था या नहीं. बड़ा सवाल यह है कि उसने वैसे ही काम किया, जैसे दूसरे आतंकवादी करते हैं. मतलब यह है कि फैजल आतंकियों की सोच और उनके काम करने के तरीक़े से इत्तेफ़ाक़ रखता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है.

हमें उस मानसिकता को बदलने की कोशिश करनी होगी, जिसके चलते न्यूयार्क जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है. यह मान लेना एक भूल होगी कि जियाउल हक के जमाने से चीज़ें बदल चुकी हैं. यह सही है कि पहले के मुक़ाबले समाज की हालत में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह भी सही है कि कट्टरवादिता बढ़ी है. मौजूदा हालात ईरान में क्रांति से पहले की हालत जैसे हैं और यह तुलना भयावह है. फिर पाकिस्तान के इस नए चेहरे में कई ऐसी चीज़ें हैं, जो दोहरेपन का अहसास दिलाती हैं. कई ऐसे लोग हैं, जो उदारवादी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन अधिकांश अहम मुद्दों पर उनके विचार कट्टरवादियों से मिलते-जुलते हैं. हाल के दिनों में कराए गए सर्वेक्षणों पर नज़र डालें तो क़रीब 80 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि राजनीतिक जीवन में धर्म के लिए भी जगह होनी चाहिए. हालांकि अच्छी बात यह है कि चुनावों में राजनीतिक दलों को धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलते. जनरल जिया के जमाने में अस्तित्व में आए दकियानूसी और रूढ़िवादी धार्मिक संगठन धीरे-धीरे ऐसे उदारवादी संगठनों को कमज़ोर करने में कामयाब होते जा रहे हैं, जो परंपरागत रूप से एशियाई उप महाद्वीप में सामाजिक और धार्मिक स्वरूप का हिस्सा रहे हैं. चिंता की बात यह है कि इन रूढ़िवादी संगठनों की विचारधारा धीरे-धीरे बड़े शहरों में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चों को भी अपनी गिरफ़्त में लेती जा रही है. स्कार्फ से मुंह ढंक कर सड़कों पर चलती हुई लड़कियों या खेल के मैदानों में बच्चों के बीच की आपसी बातचीत को सुनकर इसकी तस्दीक की जा सकती है.

इन हालात को बदलने के लिए ज़बरदस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है. लेकिन सच्चाई यह है कि मौजूदा दौर में ऐसी कोई ताक़त नज़र नहीं आती, जिसके पास इस काम को अंजाम देने के लिए ज़रूरी इच्छाशक्ति या प्रतिबद्धता हो. हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा मुल्क दुनिया भर में होने वाली आतंकवादी वारदातों का केंद्र स्थल क्यों बनता जा रहा है. यही वजह है कि संभव है कल कोई पाकिस्तानी नागरिक मुंबई, न्यूयार्क, लंदन या कहीं और किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाएगा और हम सब की ज़िंदगियां और भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएंगी.

हयात के.
feedback@chauthiduniya.com

कंप्यूटर कार इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से जुड़ा होता है और उसी के माध्यम से कार की स्टेयरिंग को आंखों की हरक़तों के अनुसार नियंत्रित करता है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

अभी तक हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का ग़लत इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देते हैं. इस अंक में हम आपको ऐसे ही एक और शब्द से परिचित करा रहे हैं. इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है संसदीय विशेषाधिकार का पेंच. सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना घटित हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यह नोट उन्हें सरकार के पक्ष में विश्वास मत के दौरान वोट देने के लिए घूस के रूप में मिले हैं, जिसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया था और उसे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था.

बाद में कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों और लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके वीडियो टेप सार्वजनिक करने की मांग की तो लोकसभा ने उन टेप को सार्वजनिक करने से मना कर दिया. लोकसभा ने बताया कि वीडियो टेप अभी संसदीय समिति के पास है और जांच की प्रक्रिया चल रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सूचना के सार्वजनिक करने से धारा 8 (1) (सी) का उल्लंघन होता है. इस धारा में बताया गया है कि ऐसी सूचना जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है.

ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें वर्तमान केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के ख़र्चों का ब्यौरा मांगा था. उन्हें यह कह कर सूचना देने से मना कर दिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष एक निजी ट्रस्ट है और सूचना क़ानून के दायरे में नहीं आता, जबकि शैलेश का मानना था कि राहत कोष एक पब्लिक बॉडी है और आयकर छूट का लाभ उठाती है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए इस सूचना के सार्वजनिक होने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है. एक मासिक पत्रिका से जुड़े रमेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के स्पीकर और स्टेट असेंबली के साचिव के पास एक आवेदन किया था. आवेदन के माध्यम से यह जानना चाहा था कि क्या कोई लेजिसलेटर अपने आप से कोई सरकारी ठेका ले सकता है और यदि ऐसा ठेका लिया गया है तो क्या ऐसे सदस्य की असेंबली से सदस्यता रद्द की जा सकती है?

असेंबली से रमेश को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह मामले को उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष ले गए. आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम ए ख़ान ने स्पीकर और सचिव को सूचना के अधिकार क़ानून के तहत नोटिस जारी कर दिया. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का आवेदन ख़ारिज़ कर दिया गया और उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि आयोग का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगे जाने से और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है. आयोग को आगे से ऐसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई.

राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों को हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है. आयुक्त ने मांगी गई सूचना को 15 दिनों के भीतर आवेदक को सौंपे जाने का आदेश दिया. कुल मिला कर देखें तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

ड्राइविंग का मज़ा हाथ से नहीं, आंख से

अब आपको कार चलाने के लिए हाथों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा. क्यों चौंक गए न. जनाब चौंकने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब ऐसा ही होने वाला है. इस समय ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए हर जगह होड़ मची है.

जर्मनी में बर्लिन की फ्री यूनिवर्सिटी की एक टीम ने ऐसी ही भावी कार के कंप्यूटर के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो आंख की पुतलियों को देखते हुए कार को उसी दिशा में मोड़ता, जहां आप देख रहे होते हैं. 23 अप्रैल को बर्लिन के एक पुराने हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सामने आईड्राइविंग नाम की इस प्रणाली का प्रदर्शन किया गया. परियोजना प्रमुख प्रोफेसर डॉ. राउल रोखास ने कहा कि कार में एक वीडियो कैमरा है, जो कार चालक की आंखों को देख रहा होता है. चालक दाहिने देख रहा है या बाएं, आंख की पुतलियों की हरकतों को पढ़ रहा कंप्यूटर उसे जान जाता है.

कंप्यूटर कार इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से जुड़ा होता है और उसी के माध्यम से कार की स्टीयरिंग को आंखों की हरकतों के अनुसार नियंत्रित करता है. यदि आप सड़क पर हैं और सीधे सामने की ओर जाना चाहते हैं, तो सीधे सामने की ओर देखिए, कार चल पड़ेगी. यदि आप दाहिने मुड़ना चाहते हैं, तो दहिनी ओर देखें, कार दाहिनी ओर मुड़ जाएगी. तो, इस तरह सड़क पर अपनी नजर की दिशा के द्वारा आप कार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं. केवल नुक्कड़ या चौराहे पर आप को अपनी आंख के सामने लगे वीडियो कैमरे को इशारा करना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं. लेकिन यह भी तो हो सकता है कि किसी बात से आप का ध्यान बंट गया, आप किसी और दिशा में देखने लगें, तब भी दुर्घटना नहीं होगी. कुछ लोगों ने कहा कि आपकी नजरें यदि किसी सुंदरी की तरफ फिसल गईं, तब? तब भी नहीं. कार यदि सेमी ऑटोमैटिक दशा में है तो वह यह भी जानती है कि सड़क यातायात के नियम-कानून क्या हैं, सड़क की सीमा कहाँ है. बर्लिन के प्रदर्शन के समय हमने दिखाया कि यदि कोई आदमी कार के सामने आ जाए, तो उसके सेंसर तुरंत जान जाते हैं कि रास्ते में कोई बाधा आ गई है और वे कार को तुरंत रोक देते हैं.

अल्ट्रासाउंड से गर्भ निरोध!

अमेरिका में वैज्ञानिक एक शोध कर यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड को पुरुषों के लिए अस्थाई गर्भनिरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना विश्वविद्यालय में हुए शुरुआती शोध के बाद जानकारों का कहना है कि पुरुषों पर अल्ट्रासाउंड मशीन के ब्लास्ट के सुरक्षित इस्तेमाल से छह महीनों तक शुक्राणुओं का बनना बंद हो सकता है. वैज्ञानिक बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिली एक लाख अमेरिकी डॉलर की राशि से इस दिशा में और प्रयोग कर रहे हैं. शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि वे दुनिया को जनसंख्या नियंत्रण का एक नया तरीका दे पाएंगे.

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर जेम्स सुरुता ने कहा, हमारे विचार में इस नए तरीके से मर्दों को छह महीनों के लिए एक भरोसेमंद और कम क़ीमत का गर्भनिरोधक मिल जाएगा.आमतौर पर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग गर्भ में शिशुओं की स्थिती जानने और शरीर के विभिन्न हिस्सों में अंदरूनी स्थित का पता लगाने के लिए किया जाता है. साथ ही खिलाड़ियों को लगने वाली चोट की जांच के लिए भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है. पुरुषों के लिए यह गर्भनिरोधक कितना कारगर होगा इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता. क्योंकि इस तरीके के दीर्घकालीन प्रभावों पर अभी शोध जारी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 31 मई–6 जून 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
स्वास्थ्य आपका स्वस्थ रहेगा. आपके पास कई विकल्प होंगे, जिनका आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदे में रहेंगे. व्यवसायिक क्षेत्र में किसी काम की शुरुआत करने में देर होगी. बिजनेस यात्रा आपकी उम्मीदों के मुताबिक़ सफल नहीं हो पाएगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
व्यवसायिक सफलता आपको ख़ुशियों से भर देगी. कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, जो मेहनत के बाद सफलता दिलाने वाला रहेगा. फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको अपने इंवेस्टमेंट पर फोकस रखकर चलना ज़रूरी होगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. पैसों से जुड़े मामले में आपके साथ बड़ों का आशीर्वाद रहेगा. व्यवसायिक स्तर पर आपका अस्त-व्यस्त व्यवहार तनाव का कारण बन सकता है. स्वास्थ्य को लेकर परेशान न हों.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
वक़्त के साथ आप कई दिक्कतों से बाहर निकल आएंगे. नए अवसर आपकी रिलेशनशिप में रोमांस व धैर्य लाएंगे. फाइनेंशियल बदलाव पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आपकी उम्मीदों से कम होंगे. आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
फाइनेंशियल फ़ायदे साधारण रहेंगे. अपने खाने का ख़ास ख्याल रखें, नहीं तो आप पेट से संबंधित किसी दिक्कत से गुजर सकते हैं. आप जो यात्रा करने जा रहे हैं, वह फ़ायदे से भरपूर रहेगी और आपको मनचाही सफलता दिलाएगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. इन दिनों चल रही प्रोफेशनल स्थितियां आपके कामों में रुकावट डालेंगी और आप कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में रहेंगे. किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति पर ख़र्च होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप यात्रा करने से बचें, नहीं तो आप बेहद थकान, हड्डियों में दर्द जैसी तकलीफों से गुज़रेंगे. इन्वेस्टमेंट में नए सिरे से प्लानिंग करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे. कोई बच्चा आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
फाइनेंशियल तौर पर कोई मज़बूत व्यक्ति काम के मामले में आपकी मदद करेगा. फाइनेंशियल फ़ायदे होंगे और आप उनको पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर चलेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
वाहन सावधानी से चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है. पेट से संबंधी शिक़ायत हो सकती है. ट्रैवल से जुड़े मामलों में बेहद ख़र्च होगा. फाइनेंशियल तौर पर कोई अकेली महिला आपके लिए मददगार रहेगी. किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
परिवार में कोई नई शुरुआत ख़ुशियां और शांति लाने का कारण बनेगी. वाणी पर मधुरता बनाए रखें नहीं तो किसी से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. आय के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग प्राप्त हो सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
लंबे समय से अधूरा पड़ा कार्य पूरा हो जाएगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. दोस्तों से अधिक बात न करें, क्योंकि लड़ाई-झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है. कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले सोच-विचार करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं , तो चुप रहने से बेहतर होगा कि आप अपनी परेशानी को दूसरे से शेयर करें. व्यर्थ की बातों में न उलझें, क्योंकि वह आपको पीड़ा पहुंचा सकती है. समाज के कुछ कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

मुल्क आज पिछली उपलब्धियों को याद करने भर से संतुष्ट नहीं है. 18वां संविधान संशोधन चाहे जितना भी अच्छा और दूरगामी क्यों न हो, जनता आज उससे आगे देख रही है.

समय पूर्व थकान की ख़तरनाक बीमारी

यह समय से पहले की थकान है, एक ऐसी सरकार और पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, जो काम या नए कार्यक्रमों के स्तर पर बिल्कुल मृतप्राय हो चुकी है और सब कुछ ठहर सा गया है. यह तुलना भले ही अटपटी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि मुशर्रफ़ को भी इस हालत में आने में चार-पांच साल लग गए थे. 2005-06 के आते-आते मुशर्रफ़ के धुर समर्थकों को भी उनकी बातों के खोखलेपन का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन इस सरकार ने यह कारनामा आधे से भी कम समय में कर दिखाया है और यही शायद इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है. वर्ष 2008 के बाद देश में लोकतंत्र की जो नई लहर चली थी,

परवेज़ मुशर्रफ़

उसका प्रमुख आधार मुशर्रफ़ विरोध था, लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ दूसरी समस्याएं सतह पर आने लगीं, मुशर्रफ़ विरोध का यह नारा कमजोर पड़ता गया. अब तो हालत यह है कि मुशर्रफ़ की चर्चा से भी बोरियत होती है. ख़ुद मुशर्रफ़ का हाल यह है कि प्रशंसकों के नाम पर वह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर अपने फॉलोअर्स के नाम गिनाते हैं. बुरे वक़्त का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले.

फरवरी 2008 के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों ने देश में न्यायपालिका को उसका वाजिब स्थान दिलाने के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था. पहले एक साल तक इसके समर्थन-विरोध का खेल चलता रहा, तभी जाकर ऐसा संभव हो पाया. आज मुल्क में न्यायपालिका फिर से स्थापित हो चुकी है, लेकिन इससे राष्ट्रीय पुनरुद्धार का रास्ता खुलने के जो सब्जबाग दिखाए गए थे, वे अभी भी दूर की कौड़ी बने हुए हैं. नए नायकों की तलाश कर रहा यह मुल्क न्यायिक तंत्र में अपने मसीहा की छवि देखने लगा था, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि न्यायपालिका भी पाकिस्तान के अन्य सत्ता प्रतिष्ठानों की तरह अति महत्वाकांक्षा की शिकार है. पाकिस्तान की त्रासदी यही है कि सेना हो या राजनीतिक तंत्र या फिर मौजूदा स्थिति में न्यायपालिका, कोई भी हाथ में सत्ता आते ही अपनी सीमाओं को लांघने का लोभ संवरण नहीं कर पाता और यही उसके पतन का कारण बन जाता है. हम अपने पैरों पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मारने की कला में पारंगत हैं और कई बार इसके परिणाम भी भुगत चुके हैं. इसे देखते हुए अब तक हमें अपने अंदर धैर्य और प्रगतिवादिता जैसे गुणों का विकास कर लेना चाहिए था. लेकिन जब बात राष्ट्रीय मुद्दों की आती है तो ऐसा लगता है, जैसे उक्त गुण हमारे सिद्धांतों की श्रेणी में आते ही नहीं. अब तक चार बार ऐसा हुआ है, जब सेना ने देश को बचाने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है और चारों मौक़ों पर पाकिस्तान को निराशा झेलनी पड़ी है. सत्ता का तीसरा स्तंभ मानी जाने वाली न्यायपालिका भी आज उसी रास्ते पर चल पड़ी है. तमाम तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, रोज नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं. इसके परिणाम क्या होंगे, पता नहीं. हम सांसें रोक कर इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते. राष्ट्रपति कार्यालय के पास बस एक ही काम है, किसी भी तरह ख़ुद को बनाए रखने का. राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और ज़िम्मेदारी के एहसास का जो अभियान एनआरओ के फ़ैसले ने शुरू किया था, उसे रोकने के लिए उसने अपनी सारी ताक़त लगा दी. देश की राजनीतिक व्यवस्था और सेना भले ही एक दोराहे पर खड़ी हो, इससे बेख़बर राष्ट्रपति अपनी चमड़ी बचाए रखने में लगे हैं.

देश का सर्वोच्च न्यायालय भी निराशा का अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि एनआरओ मामले में उसके फ़ैसले का उल्लंघन हो रहा है. यही वजह है कि वह कई बार खुलेआम अपने गुस्से का इज़हार कर चुका है, हालांकि ऐसा न करना शायद बेहतर होता. फिर भी स्विस बैंकों के साथ पैसों के ग़ैरकानूनी लेनदेन के मामलों को दोबारा खोलने के लिए स्विस अधिकारियों से संपर्क करने के लिए वह सरकार पर दबाव बना रहा है. स्विस बैंकों के इस मामले से आसिफ अली जरदारी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं. यह सत्ता प्रतिष्ठानों के बीच आपसी खींचातानी और फिर टकराव का निश्चित संकेत है. अदालत को यह लग रहा है कि जनता उसके पीछे खड़ी है, लेकिन यह एक छलावा भी हो सकता है. आम जनता राष्ट्र सुधार के ऐसे नारे पहले भी कई बार सुन चुकी है. उसे उन चीज़ों की ज़्यादा चिंता है, जिनसे वह सीधे तौर पर प्रभावित होती है, मसलन बढ़ती महंगाई, बिजली की कमी आदि. राष्ट्र के प्रति जवाबदेही उसकी इस सूची में काफी नीचे जा चुकी है. इस मुद्दे में अब वह आकर्षण नहीं रहा, जैसा कुछ दिनों पहले तक था.

मुल्क आज पिछली उपलब्धियों को याद करने भर से संतुष्ट नहीं है. 18वां संविधान संशोधन चाहे जितना भी अच्छा और दूरगामी क्यों न हो, जनता आज उससे आगे देख रही है. लेकिन हमारे राज-नेता हैं कि वे गुजरे दौर से ही बंधे रहना चाहते हैं. सवाल यह है कि इस सबका भविष्य क्या है? राजनीतिज्ञों को जनता की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान कहीं और लगा है, वे अपनी ज़िम्मेदारियों से भटक गए हैं. देश के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ग़ैर ज़रूरी, यह समझ अभी तक विकसित ही नहीं हुई है. आने वाली गर्मियों में हालात क्या रुख़ बदलते हैं, यह

नवाज़ शरीफ़

देखना रोचक होगा. हालांकि वास्तव में होगा क्या, यह तो केवल ख़ुदा ही जानता है. देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब, जो सही मायने में अकेले ही आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, में सत्ता पर क़ाबिज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (पीएमएल-एन) भी इसी व्यवस्था का एक हिस्सा है और अन्य दलों की तरह उसके पास भी नए विचारों या कार्यक्रमों का नितांत अभाव है. हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि नारेबाज़ी से अब काम नहीं चलने वाला. न्यायाधीशों को फिर से बहाल करने का मामला अब सुलझ चुका है, 18वां संविधान संशोधन भी अब भूतकाल की चीज बन चुका है. अब जरूरी है कि हम हालात को नए सिरे से समझें और नई संभावनाओं एवं नई दिशाओं की तलाश करें. सस्ती रोटी जैसी लोकलुभावन योजनाओं की उपयोगिता भी अब समाप्त हो चुकी है. सरकार को अब अपनी सीमाओं में रहकर जीना सीखना होगा. इस लिहाज़ से देखा जाए तो पंजाब सरकार को दानिश स्कूल वाली अपनी योजना पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बहुत ही ख़र्चीली योजना है. यह योजना मुख्यमंत्री के दिल के बेहद क़रीब है और यह भी जगजाहिर है कि वह अपने फ़ैसलों को इतनी आसानी से नहीं बदलते. बेहतर यही है कि हम अपनी ज़ुबान को बंद ही रखें.

देश की सेना भी इस मकड़जाल में उलझ कर रह गई है. स्वात घाटी और दक्षिणी वजीरिस्तान में उसके अभियानों को सफलता मिली है, लेकिन इसकी बड़ी क़ीमत भी चुकानी पड़ी है. उसे बड़ी संख्या में अपने जवानों की बलि देनी पड़ी. लेकिन सवाल यह है कि आगे का रास्ता कहां जाता है? आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है. तालिबान को भी कई झटके लगे हैं, लेकिन वह न तो पराजित हुआ है और न ही उसे पूरी तरह ख़त्म किया जा सका है. लेकिन फिर भी आज हम तालिबान के मुक़ाबले मज़बूत हालत में हैं और बेहतर यही है कि हम अभी उससे बातचीत करने की कोशिश करें. आज नहीं तो कल, हमें यह काम करना ही होगा. लेकिन एक बार जब अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने लगेगा, जो अगले साल कभी भी हो सकता है, तो संभव है कि हालात इतने ज़्यादा मुफीद न रहें.

निकट भविष्य में किसी बड़ी जीत या उपलब्धि की संभावना दूर तक नज़र नहीं आती. अभी से लेकर अगले साल तक सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ज़मीन बरक़रार रखना है. उसे उन इलाक़ों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना होगा, जिन्हें तालिबान के चंगुल से छुड़ाया गया है. कई बार लड़ाई जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम लड़ाई में हासिल जीत को बरक़रार रखना होता है. इसमें ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है. अगले बारह महीने सेना के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. पूरे मुल्क को अपने जांबाज़ों के लिए दुआ करनी चाहिए. सेना को भी अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने व्यवसायिक हितों की चिंता छोड़नी होगी. जिया उल हक के जमाने से लेकर परवेज मुशर्रफ़ का दौर आते-आते सेना का यह रूप कुछ ज़्यादा ही नज़र आने लगा था. स्वात और वजीरिस्तान से पहले

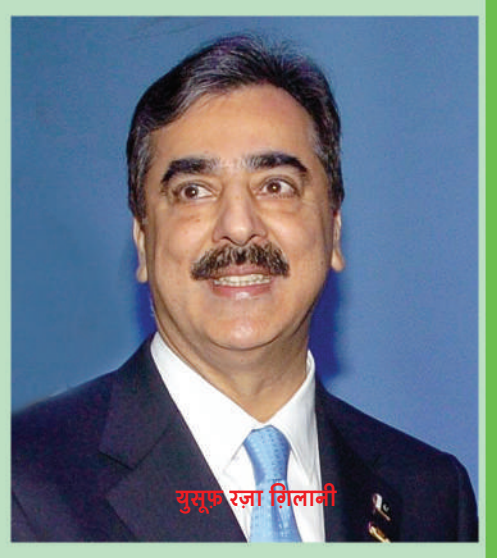

युसूफ़ रज़ा गिलानी

तक सेना की छवि ऐसी बनकर रह गई थी, जो मुश्किल परिस्थितियों में हथियार उठाने से ज़्यादा रीयल इस्टेट कंपनी की तरह काम करती थी. जिस तरह देश के राजनीतिक नेतृत्व को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, देश के सामने मौजूद समस्याओं से निबटने के लिए नए ढंग से सोचने की दरकार है, ठीक उसी तरह सेना को भी अपनी छवि और सोच में बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है. इस लिहाज़ से देखें तो तालिबानी आतंकवाद सेना के लिए एक बेहतरीन मौक़ा हो सकता है. लेकिन ऐसा तभी संभव होगा, जब देश का सैन्य तंत्र भी यह समझे कि पाकिस्तान को अपने भूतकाल से निकल कर नए रास्ते पर और नई दिशा में चलने की ज़रूरत है.

अयाज आमिर
feedback@chauthiduniya.com

e देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

साईबाबा हमें देते हैं अथाह प्रेम और संपूर्ण स्वीकार्यता. हम जैसे हैं जहां हैं, हमें उसी रूप में स्वीकारते हैं. अपने हृदय से लगाकर हमारे आंसू पोछते हैं.

साई मेरा कौन

हम भारतीयों की एक ख़ासियत रही है. हम लोग रिश्ते बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं. कोई दोस्त होता है तो बच्चे उसे चाचू या मौसी बना लेते हैं. इसके अलावा आंटी अंकल के बजाए हम उन्हें चाची, मौसी और काकी कहना ज़्यादा पसंद करते हैं. इससे न सिर्फ़ अपनेपन का एहसास होता है बल्कि ज़िम्मेदारी भी महसूस होती है. बदलते वक़्त में जहां आस पड़ोस और बाक़ी रिश्ते सिर्फ़ दिखावटी तौर पर रह गए हैं, ऐसे में सतगुरु और भगवान और भी दूर हो गए हैं. जब भी कोई मुश्किल आती है तो ही हम उसे याद करते हैं. जब मनचाहा काम नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमसे नाराज़ हैं. उसके बाद हम सारी शक्ति भगवान की अर्चना करने और उसे मनाने में लगा देते हैं. बिना जाने कि आख़िर वे कौन है और हमसे क्या चाहता है?

क्या सचमुच कोई पिता यह चाहेगा कि उसे ख़ुश करने के लिए उसका बच्चा नंगे पांव पेट के बल लेटकर उसके पास जाए, दिन भर भूखा रहे. कौन होगा ऐसा पिता? पर हमने साई को कभी भी पिता या किसी अपने रिश्ते के रूप में नहीं लिया. बस साई देने वाला था और हम लेने वाले. कभी यह जानने की कोशिश नहीं की वे क्या दे रहा है. दरअसल साईबाबा हमें देते हैं अथाह प्रेम और संपूर्ण स्वीकार्यता. हम जैसे हैं जहां हैं, हमें उसी रूप में स्वीकारते हैं. अपने हृदय से लगाकर हमारे आंसू पोछते हैं. चोट पर मरहम लगाते हैं. हमारे अंदर के आत्मबल को जगाकर हमें सहारा देता है. सही रास्ता दिखाता है. इस रास्ते पर चलकर हमें कांटे नहीं फूल मिलते हैं. जब इस रास्ते पर चलकर हमारा जीवन सुखमय होगा. साई को पहचान कर उससे नाता जोड़ें ताकि हम जीवन के हर पल को उत्सव की तरह जी पाएं. रिश्तों को फिर से जीवित करें और तमाम रिश्तों के अधिकार और अहमियत को समझें. रिश्तों में जिस अधिकार से हम कुछ मांगते हैं, उसी अधिकार से देना भी सीखें. हर बार रिश्तों का सहारा लेकर मांगना भी अच्छा नहीं है. बस बाबा को क्रोध, लोभ, अंहकार समर्पित कर दो, उनके विशाल मन में सब समा जाएगा. फिर आप देखेंगे कि जो बोझ आप उठा रहे थे, वह कितना हल्का हो गया है. अगर आप बाबा के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो बाबा के मंदिर में जाएं. मंदिर में पैसा, कपड़ा और प्रसाद न चढ़ाकर अपना गुस्सा चढ़ाएं. बाब से कहें कि आज मैं अपना गुस्सा तुम्हें समर्पित करता हूं. फिर बाबा का प्यार और स्नेह दिन भर अपने साथ रखें. दिन के अंत में आप देखेंगे कि आपका मन कितना शांत रहेगा. ऐसा करते करते आप न सिर्फ़ बाबा से एक ख़ास आपका रिश्ता महसूस होगा बल्कि आप ख़ुद भी सशक्त होते जाएंगे. तो आज ही तय करें कि आप बाबा से क्या रिश्ता रखेंगे. साई भक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए कृपया 09999313918 पर एसएमएस करें.

ॐ साई राम.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों की सच्ची कहानियां

शिरडी के साईबाबा– एक ऐसे संत जिन्हें आज भी लोग अपने आसपास महसूस करते हैं. सुख–दुख में उनके होने का अनुभव करते हैं. ऐसे ही कई अनुभव साईभक्त परिवार के सदस्यों के भी रहे हैं. 22–23 साल की लड़की सीमा बाबा को बचपन से ही बहुत मानती थी. उसने अपना अनुभव हमारे साथ बांटा.

सीमा

सीमा की दो बहनें विवाहित हैं. बहन और जीजा बाबा में विश्वास नहीं रखते थे. एक बार सीमा की बहन के घर एक दुर्घटना घट गई. हुआ यूं कि अचानक से बिजली चली गई. इन्वर्टर में भी कुछ समस्या आ गई थी. जब उसके जीजा देखने गए तो अचानक इन्वर्टर फट गया. इससे निकला एसिड उनकी आंखों में चला गया. सब लोग डर गए और बहन जैसे ही उन्हें बचाने गई तो उसकी आंखे भी चोटिल हो गईं. आंखों में एसिड जाने से इंफेक्शन हो गया. अब दोनों लोग आंखों से लाचार हो गए. डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा. सीमा को पूरा विश्वास था कि बाबा की कृपा से उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी. एक दिन लोधी रोड के साई बाबा मंदिर में सीमा बाबा की प्रतिमा के आगे खड़ी अपनी दीदी और जीजा की आंखों के लिए प्रार्थना कर रही थी, अचानक उसे बाबा की आंखें लाल नज़र आईं. वह बहुत हैरान हुई. उसने दोबारा बाबा की ओर देखा, उनकी आंखे वैसी ही लाल थी. उसने तुरंत बाहर निकलकर अपनी बहन को फोन करके पूछा कि जीजाजी कहां हैं? बहन ने बताया कि नहा रहे हैं. सीमा ने कहा कि उनसे पूछो कि उनकी आंखे कैसी हैं. जीजाजी ने शीशे में आंखे देखीं तो बिल्कुल ठीक थीं. न कोई जलन और न ही कोई लाली थी. दोनों तैयार होकर अपनी बेटी के साथ मंदिर पहुंचे. बाबा की प्रतिमा के आगे झुके. पुजारी ने कमल का फूल दिया, वहीं पर साथ बैठी छोटी बेटी को बाबा ने साक्षात दर्शन दिए. बाबा को न मानने वाले दीदी और जीजाजी का सिर बाबा के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम से झुक गया. अभी सीमा की दीदी की आंखों का ऑपरेशन होना बाक़ी था. दीदी ऑपरेशन के लिए तैयार भी नही थीं. उन्होंने बाबा के सामने प्रार्थना की और कहा बाबा मेरी रक्षा करो. अगले दिन डॉक्टर से मुलाक़ात थी. सुबह जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर हैरान रह गया. बोला कि इतनी जल्दी आंखे काफी हद तक ठीक हो गई हैं. अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ़ दवा डालने से काम चल जाएगा.

सीमा और उसका पूरा परिवार बाबा के इस प्रगाढ़ प्रेम और चमत्कार से अभिभूत हो गया. सीमा हर पल अपने आसपास बाबा को महसूस करती है. अब उसने अपने जीवन का मक़सद लोगों को फाउंडेशन तक लाने का बना लिया है, ताकि सभी लोग बाबा के प्रेम से परिचित हो सकें.

ॐ साई राम.

feedback@chauthiduniya.com

इस हफ्ते फाउंडेशन से

गत सप्ताह फाउंडेशन की गतिविधियां बहुत तेज़ रहीं.

- साई की महिमा कार्यक्रम का प्रसारण A2Z न्यूज़ चैनल पर हर रात 10 बजे, साधना टीवी पर सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है .
- हर रोज़ लोगों के सवालों के जवाब लगातार साई सच्चरित्र के माध्यम से दिए जा रहे हैं.
- फाउंडेशन अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधा संवाद कर रहा है. ताकि बच्चों का मानसिक तनाव दूर हो और उनका आत्मबल बढ़े. हाल ही में समर फील्ड स्कूल और प्ले स्कूल का दौरा किया गया है.
- फाउंडेशन 10 वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष हेल्पलाइन (011–6464005/06) शुरू कर रहा है. इसके ज़रिए परीक्षाओं के दौरान बढ़ते मानसिक तनाव और अन्य परेशानियों का समाधान किया जाएगा. ताकि कोई भी विद्यार्थी तनाव में आकर ख़ुदकुशी न कर सके.

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

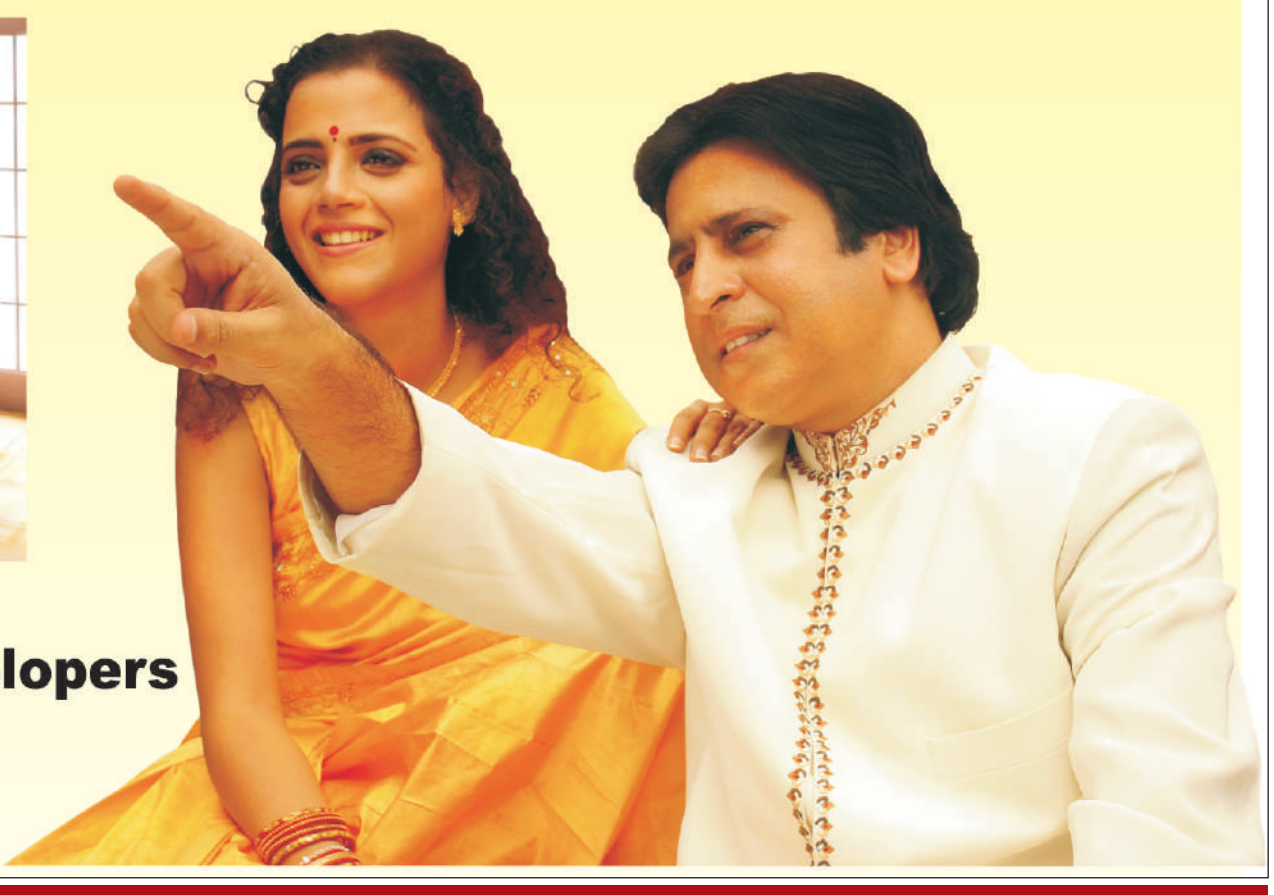

AUM Infrastructure & Developers

Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

राजनीति के भैरो बाबा

अनंत विजय

वर्ष दो हज़ार पांच की सर्दियों की बात है. वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय की दो किताबें राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थीं. तय हुआ कि दोनों किताबों का विमोचन भैरो सिंह शेखावत से कराया जाए. शुरू में मैंने इस बात का विरोध किया था कि जिस व्यवस्था और राजनीति के विरोध में ये दोनों किताबें हैं, जिनका लेखक लंबे समय से अपनी पत्रकारिता से राजनीतिक व्यवस्था की खामियों को लगातार उजागर करता रहा हो, जिसकी लेखनी सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ बेहद उग्र हो जाती हो, जो किसी भी क़ीमत पर पत्रकारिता के सिद्धांत से समझौता नहीं करता हो, उसकी किताबों का विमोचन उसी राजनीतिक व्यवस्था का अंग रहा कोई राजनेता कैसे कर सकता है. फिर शेखावत जी की विचारधारा को लेकर भी मेरा विरोध था. मेरा मानना था कि हिंदी में जो हालात हैं, उनके हिसाब से अगर किसी भी कृति के साथ किसी दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति या समूह का नाम जुड़ जाता है तो वह किताब हिंदी पर क़ाबिज़ वामपंथियों के लिए अछूत हो जाती है और उसकी चर्चा करने से तथाकथित प्रगतिशील लेखक-समीक्षक घबराने लगते हैं. मैं अपने तर्क पर क़ायम था, लेकिन फिर कई मित्रों की सलाह पर मैंने भी हथियार डाल दिए और तय हुआ कि भैरो सिंह शेखावत ही संतोष जी की दोनों किताबों का विमोचन करेंगे. लेकिन साथ ही यह तय करवाने में कामयाब हुआ कि वरिष्ठ पत्रकार एम जे अकबर भी शेखावत जी के साथ संयुक्त रूप से दोनों किताबों का विमोचन करेंगे.

फिर विमोचन की तारीख़ तय हुई. ग्यारह दिसंबर दो हज़ार पांच की सर्द शाम को दिल्ली के मौलाना आज़ाद रोड स्थित उपराष्ट्रपति निवास में विमोचन समारोह होना था, लेकिन उसके पहले भी तमाम तरह की औपचारिकताएं होनी थीं. भारतीय गणतंत्र के उपराष्ट्रपति होने के नाते कई प्रोटोकॉल थे, जिनका पालन अधिकारियों के साथ-साथ हमें भी करना पड़ रहा था. आमंत्रित मेहमानों की सूची हमें पहले ही सौंपनी पड़ी थी. पत्रकारिता पर किताब होने की वजह से मैंने हिंदी अकादमी के पत्रकारिता के छात्रों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया था. मेरी चिंता सिर्फ़ अपने छात्रों को लेकर थी कि उन्हें किसी तरह की दिक़्क़त न हो. लगातार सरकारी अड़चनों की वजह से मैं बेहद खिन्न था और मन ही मन यह तय कर चुका था कि विमोचन समारोह के बाद उपराष्ट्रपति से यह ज़रूर पूछूंगा कि उपराष्ट्रपति होने के बाद प्रोटोकॉल और सरकारी नियम-क़ानून की वजह से उन्हें जनता से दूर क्यों कर दिया जाता है.

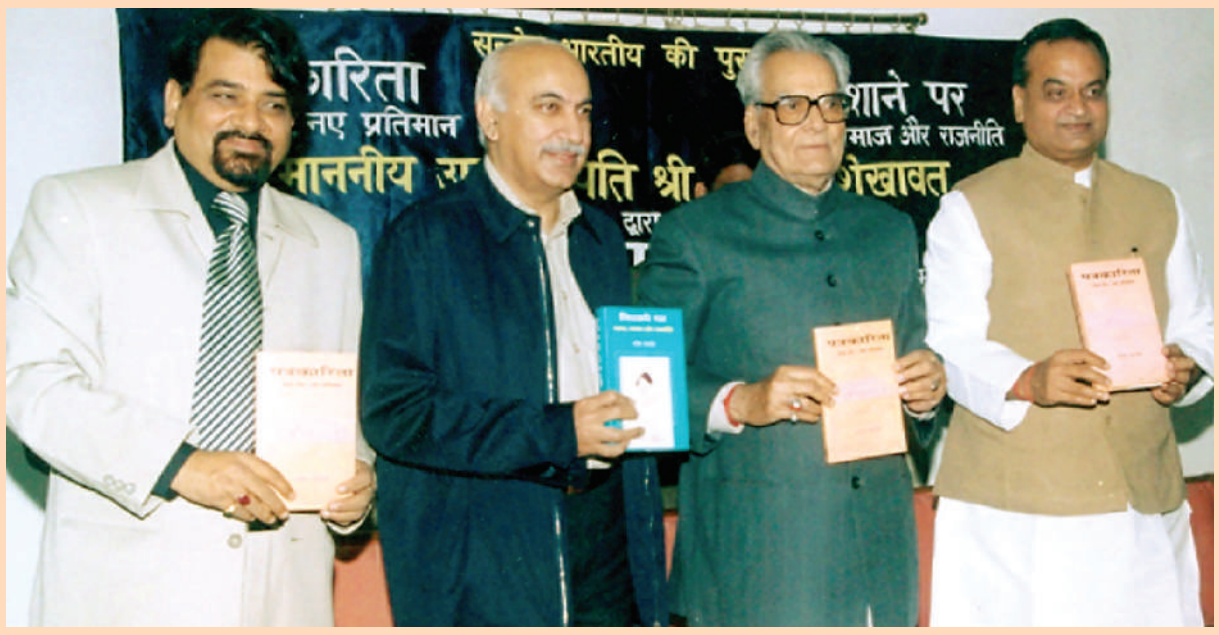

खिन्न मिजाज़ और कोफ्त के साथ विमोचन वाले दिन समारोह के दो घंटे पहले मैं अपने दो-तीन मित्रों के साथ उपराष्ट्रपति भवन जा पहुंचा. वहां तमाम इंतज़ाम दुरुस्त थे. हमसे पहले राधाकृष्ण प्रकाशन के मालिक अशोक माहेश्वरी ने मोर्चा संभाल रखा था. तमाम सावधानी के बावजूद एक बेहद मज़ेदार घटना हो गई. दरअसल एम जे अकबर साहब की गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति भवन में घुसती रही थी. इस समारोह के लिए भी उनकी गाड़ी का नंबर गेट पर सुरक्षाकर्मियों के पास पहले से दिया हुआ था. सो गाड़ी सीधे पोर्टिको में जाकर खड़ी हो गई. एम जे अकबर नीचे उतरे तो पोर्टिको में उनकी अगवानी करने वाला कोई नहीं था. जो सरकारी कर्मचारी थे, वे अकबर साहब को पहचानते तक नहीं थे, लिहाज़ा नाराज़ होकर अकबर साहब फिर गाड़ी में बैठे और वापस चल दिए. हमें पता ही नहीं चला कि कौन आया और कौन चला गया. हम अकबर साहब की अगवानी के लिए मेन गेट पर खड़े रहे. इस बीच मेहमानों का आना-जाना लगा रहा. मैं गेस्ट लिस्ट पर नज़र डाल रहा था तो देखा कि अकबर साहब के नाम के आगे टिक लगा हुआ था. मतलब कि वह आ चुके थे. फिर जब पूछताछ शुरू हुई तो पता लगा कि अकबर साहब आए थे और ख़फ़ा होकर वापस चले गए. हमने तुरंत शेखावत जी के साथ उनके कमरे में बैठे संतोष भारतीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के पास यह संदेश भिजवाया. दोनों बाहर निकल कर परेशान हो रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी शेखावत जी ने दूर कर दी और ख़ुद फोन कर अकबर साहब से खेद जताते हुए वापस आने का अनुरोध किया. तक़रीबन पंद्रह मिनट बाद अकबर साहब की गाड़ी फिर से आकर उपराष्ट्रपति निवास के पोर्च में रुकी.

इसके बाद विमोचन समारोह शुरू हुआ. पत्रकारिता नया दौर नए प्रतिमान के बैक कवर पर लिखा था- एम जे अकबर स्वभाव से बिल्कुल तानाशाहों जैसे जाने जाते हैं, पर अकबर तानाशाह हैं नहीं, लेकिन उन्हें कोताही कतई बर्दाश्त नहीं है. एम जे अकबर के शब्दकोश में किसी भी असफलता का कारण कोई मायने नहीं रखता है. वह हमेशा कहते कि आपके कारण बताने से न स्टोरी अच्छी बनती है और न फोटोग्राफ अच्छा खिंचता है. अब पूरा विमोचन समारोह इस बात पर ही केंद्रित हो गया. किताबों के लेखक ने भी इस बात की सफाई दी. शेखावत जी और दिग्विजय सिंह ने भी तानाशाह शब्द के बहाने पत्रकारों और आज की पत्रकारिता की चुटकी ली, लेकिन अकबर साहब ने तमाम बातों को साफ़ करते हुए लेखक की साफगोई के लिए तारीफ़ की. मुझे नहीं मालूम कि राधाकृष्ण प्रकाशन या उपराष्ट्रपति निवास में उस समारोह के भाषणों की रिकॉर्डिंग है या नहीं, लेकिन अगर यह रिकॉर्डिंग मौजूद है तो उससे बेहद दिलचस्प बातें सामने आ सकती हैं. शेखावत जी के भाषण और उनके चुटीले अंदाज़ एवं विनम्रता से मेरी उनके प्रति धारणा थोड़ी बदलने लगी थी. समारोह ख़त्म हो गया और उपराष्ट्रपति भवन के लॉन में चाय का इंतज़ाम था. हम सब लोग बाहर आ गए.

पत्रकारिता के छात्रों ने अचानक बाहर आकर मुझसे कहा कि वे भैरो सिंह जी से अनौपचारिक बात करना चाहते हैं. मैंने शेखावत जी के सहायक कोचर से यह अनुरोध किया, लेकिन उसने बात टाल दी. चाय की बातचीत के दौरान मैंने ख़ुद ही शेखावत साहब के सामने यह बात रखी कि जिन लोगों से आप घिरे हैं, वे जब चाहें आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के उन छात्र-छात्राओं से चलकर मिलिए, जिनके लिए अपने देश के उपराष्ट्रपति से मिलना बहुत बड़ी बात है. मेरी उम्मीदों के विपरीत शेखावत साहब झट से न केवल तैयार हो गए, बल्कि दिल्ली की तमाम नामचीन हस्तियों से बात करना छोड़ छात्र-छात्राओं के बीच चले आए.

बातचीत का सिलसिला घंटे भर चला. छात्रों के अनुरोध पर उनके साथ और अलग-अलग फोटो भी खिंचवाए. उन्होंने अकबर और संतोष भारतीय को भी वहीं बुलवा लिया. तक़रीबन घंटे भर की बातचीत के बाद छात्र-छात्राएं बेहद ख़ुश थे. इस बीच शेखावत साहब ने अकबर से उनके नाराज़ होने पर भी चुटकी ली एवं उन्हें मनाने का किस्सा भी छात्र-छात्राओं को सुनाया. मौक़ा देख मैंने भी सवाल दाग दिया कि देश का उपराष्ट्रपति जनता से इतना दूर क्यों है. शेखावत साहब ने तपाक से जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि दूसरों की क्या हालत है, लेकिन मैं हमेशा से सबके लिए सुलभ हूं. उनके साथ देश की राजनीति पर भी कई बातें हुईं, लेकिन इस बातचीत में जो एक ऊष्मा और सहृदयता मैंने महसूस की, वह दूसरे राजनेताओं से अलग हटकर थी. बातचीत में इस तरह की सहृदयता वी पी सिंह और चंद्रशेखर के साथ भी बात करते हुए महसूस की जा सकती थी. शेखावत साहब से बाद में कई मुलाक़ातें हुईं और उन्होंने अपने व्यवहार से मेरे मन की सारी भ्रांतियां दूर कर दीं. हर विषय पर बेबाक राय भी शेखावत साहब की विशेषता थी. अपनी इसी साफगोई की वजह से भैरो बाबा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कोपभाजन भी बने. लेकिन सिर्फ़ पार्टी ही नहीं, पार्टी के बाहर भी शेखावत का कद बेहद बड़ा था. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर के बाद शेखावत ही बचे थे, जिनकी हर पार्टी और हर समुदाय में न केवल स्वीकार्यता थी, बल्कि प्रतिष्ठा भी. विरोधी भी उनकी बात गंभीरता से सुनते थे. विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर के बाद भैरो सिंह शेखावत का जाना भारतीय राजनीति में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं दिखती. चौथी दुनिया परिवार की तरफ़ से भैरो सिंह शेखावत को प्रणाम और विनम्र श्रद्धांजलि.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

प्रदीप सौरभ

अगली सुबह घंटी बजी. वही महिला सामने खड़ी थी. उसको अंदर बुलाकर पैसे-वैसे की बात की. डेढ़ सौ रुपये में मामला पट गया था. नाम पूछा तो बोली, मुन्नी.

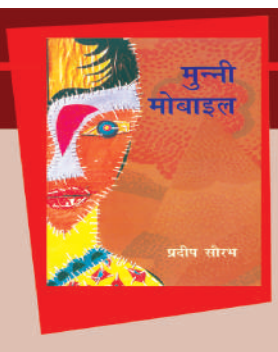

मुन्नी से आनंद भारती की यही पहली मुलाक़ात थी.

रेखा, पुष्पा और मुन्नी ने घर का मोर्चा संभाल लिया था. तीन- तीन महिलाओं को संभालना आनंद भारती के लिए टेढ़ी खीर थी. फिर भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. वह पत्रकारपुरम से पहले जहां भी रहे, उनके पास एक ही काम करने वाला था. सोनीपत, गुवाहाटी, शिमला, चंडीगढ़, अहमदाबाद सभी जगह उनके पास एक महिला या एक लड़का रहा. खाना बनाने से लेकर कपड़ा धोने तक का काम एक के ज़िम्मे रहा. घर की चाबी भी उन्हीं के पास होती थी. लेकिन यहां उन्हें तीन-तीन औरतों से मुक़ाबला करना पड़ रहा था. तिस पर खाना बनाने की समस्या बनी हुई थी.

तीनों महिलाओं में मुन्नी काम में ज़्यादा ध्यान देती थी. बाक़ी दोनों काम को बोझ की तरह लेती थीं. छुट्टी मारने में भी माहिर थीं. उनकी छुट्टियों के दौरान घर में सफाई नहीं होती और कपड़ों का ढेर लग जाता. आनंद भारती इन औरतों से निजात पाने के लिए किसी ऐसे लड़के की तलाश में थे, जो घर में रहे और सारा काम करे. इस अव्यवस्था के बीच वह मुन्नी से पैसे का लालच देकर इन दोनों की छुट्टियों के दौरान काम करवा लेते. इस तरह दो-तीन महीने गुजर गए थे. मुन्नी से उनकी सेटिंग धीरे-धीरे हो रही थी. एक दिन उन्होंने उससे पूछा, तुम कितनी जगह काम करती हो?

पांच जगह, मुन्नी ने बताया.

कितने पैसे कमा लेती हो?

आठ सौ रुपये. जोड़-जाड़ कर उसने बताया.

एक हज़ार रुपये दूं तो तुम मेरा सारा काम करोगी, आनंद भारती ने तुरंत पैसों का लालच दिया.

वह कुछ नहीं बोली.

बात आई-गई हो गई. मुन्नी समझ रही थी कि कुछ और पैसा बढ़ा कर बोलें तो पूरा काम संभाल लूं. वह आनंद भारती की मजबूरी को अंदर ही अंदर समझ रही थी. एक सप्ताह बाद उन्होंने फिर पूछा, तुमसे कुछ पूछा था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया. चलो बारह सौ रुपये दे देंगे.

मुन्नी उसी पल का इंतज़ार कर रही थी. उस प्रस्ताव पर मुन्नी राजी हो गई. उन्होंने रेखा और पुष्पा को हटा दिया. पुष्पा तो पहले से ही छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुकी थी. उसके पति की मर्दानगी जो जाग गई थी. पुष्पा ने बताया था कि अब उसका आदमी उसे बाहर काम पर नहीं भेजना चाहता. पुष्पा जब आनंद भारती के घर काम करने आई थी तो उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था. तब भी उन्होंने उससे पूछा था, बच्चे को लेकर काम करने में परेशानी नहीं होती.

इस पर उसने जवाब दिया था, होती तो है. आदमी कोई काम नहीं करता है. शराब पीकर पड़ा रहता है. रोटी उसे पूरी चाहिए. मैं तो भूखी रह लूं, लेकिन बच्चे को भूखा कैसे रख सकती हूं.

गतांक से आगे

अब तुम्हारा आदमी ठीक हो गया है? आनंद भारती ने पूछा.

हां, एक महीने से काम पर जा रहा है. शराब को भी हाथ नहीं लगाया है.

तो, अब तुम ख़ुश हो. आनंद भारती उसके भीतर की सच्चाई जानना चाहते थे.

उसने कोई जवाब नहीं दिया. उसके चेहरे से लग रहा था कि वह ख़ुश है.

रेखा ज़रूर जाते वक़्त बोली, आख़िर हमसे क्या ग़लती हो गई, जो आप मुझे हटा रहे हैं. उसकी आवाज़ में उलाहना था.

इसका आनंद भारती के पास कोई जवाब नहीं था. वह इतना ही बोले, तुम्हें दूसरा काम मिल जाएगा.

दूसरा काम छोड़कर पुष्पा के कहने पर ही मैं आई थी. आप अकेले रहते हैं तो मैंने सोचा कि आपकी मदद हो जाएगी, रेखा अहसान जताते हुए बोली.

अगले अंक में जारी

लद्दाख में बौद्ध-मुस्लिमों के बीच बदलते रिश्ते

योगी सिकंद

लद्दाख में रहने वाले तीनों प्रमुख समुदायों बौद्ध, शिया और सुन्नियों के बीच के रिश्ते परंपरागत रूप से सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजनीतिक कारणों से इन संबंधों में खटास आई है. इसकी अंतिम परिणति लेह ज़िले में बौद्धों द्वारा मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार के रूप में देखने को मिली, जब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) ने 1989 में इससे संबंधित घोषणा को अमलीजामा पहनाया. यह बहिष्कार 1992 तक जारी रहा और इस दौरान बौद्ध एवं मुस्लिम युवकों के बीच कई बार आपसी संघर्ष हुए. कई बार पुलिस फायरिंग की घटनाएं हुईं, जिनमें तीन लोगों की मौत हो गई, मुसलमानों के घर जला दिए गए और मुसलमानों को ज़बरदस्ती बौद्ध बनाने की घटनाएं भी हुईं. बहिष्कार के दौरान अपने मुसलमान रिश्तेदारों से मिलने-जुलने या उनकी दुकानों को बचाने की कोशिश करने वाले बौद्धों को एलबीए के कोप का सामना करना पड़ा और दोनों समुदायों के बीच सामाजिक रिश्ते क़रीब-क़रीब पूरी तरह ख़त्म हो गए. हालांकि बहिष्कार की घोषणा वापस लेने के बाद संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन दोनों समुदायों के बीच संदेह अभी भी बना हुआ है. लेह के बौद्धों और मुसलमानों के बीच रिश्तों में आए इस दुराव की जड़ में मौजूदा दौर की कई वजहें हैं, जो मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक हैं. इसे पुराने जमाने की रूढ़िवादिता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि गुजरे दौर में दोनों समुदायों के बीच के रिश्ते अपेक्षाकृत सौहार्द्रपूर्ण थे.

लेह के मुसलमानों के बहिष्कार की इस घोषणा से पहले स्थानीय बौद्ध समूहों ने कश्मीर में तथाकथित मुस्लिम उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ लंबे समय तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखा. जम्मू-कश्मीर के भारत में शामिल होने के फ़ैसले के ठीक बाद लद्दाख के बौद्ध राज्य में शेख अब्दुल्ला और कश्मीर के प्रभुत्व का विरोध करने लगे. 1947 के बाद कश्मीर के पहले बजट में लद्दाख के लिए कोई फंड निर्धारित नहीं किया गया. और तो और, 1961 तक इस क्षेत्र के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई थी. मई 1949 में एलबीए के अध्यक्ष चेवांग रिग्जिन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक प्रस्ताव भेजकर अपील की कि कश्मीर में मतदान संग्रह में यदि बहुमत का फ़ैसला पाकिस्तान के साथ विलय के पक्ष में जाता है तो यह फ़ैसला लद्दाख पर नहीं थोपा जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि लद्दाख का प्रशासन सीधे भारत सरकार के हाथों में हो या फिर जम्मू के हिंदू बहुल इलाक़ों के साथ मिलाकर इसे अलग राज्य बना दिया जाना चाहिए अथवा इसे पूर्वी पंजाब के साथ मिला दिया जाना चाहिए. उन्होंने दबी ज़ुबान में यह चेतावनी भी दे डाली कि ऐसा न होने पर लद्दाख तिब्बत के साथ अपने विलय पर विचार करने को मजबूर हो सकता है. नेहरू ने एलबीए की चिंताओं से सहमति जताई, लेकिन यह अपील भी की कि वह अपनी मांगों पर अड़ियल रवैया न अपनाए. नेहरू का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में कोई भी वैधानिक या प्रशासनिक क़दम कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष को कमज़ोर कर सकता है. इसके बाद एलबीए लद्दाख के लिए ज़्यादा आंतरिक स्वायत्तता की मांग करने लगा. उसने लद्दाख मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन की मांग की, जिसका प्रभार जनता द्वारा सीधे चुने गए विधानसभा के किसी सदस्य के हाथों में हो, विधायिका और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में लद्दाख का उचित प्रतिनिधित्व हो, इलाक़े में सड़कों और नहरों के निर्माण के लिए ज़्यादा फंड हो, कृषि एवं हॉर्टीकल्चर के विकास के लिए प्रयास किए जाएं और पुलिस बल में कश्मीरियों की जगह स्थानीय लोगों की भर्ती हो. एलबीए की इच्छा थी कि स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू की जगह तिब्बती या बोधि लिपि में लद्दाखी भाषा को जगह दी जाए एवं चिकित्सा विज्ञान, क़ानून, इंजीनियरिंग, कृषि और वानिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए. एलबीए का तर्क यह था कि लद्दाख का जम्मू-कश्मीर राज्य के साथ वही रिश्ता होना चाहिए, जो कश्मीर और भारत के बीच है. साथ ही यह भी कि लद्दाख के लिए क़ानून बनाने का अधिकार केवल स्थानीय विधायिका के पास हो.

बाद के सालों में राज्य के बजट में लद्दाख के लिए दिए जाने वाले फंड की राशि में इज़ाफ़ा किया गया और राज्य सरकार ने दस-सदस्यीय लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल का गठन भी किया, लेकिन लेह का बौद्ध समुदाय इससे संतुष्ट नहीं था और वह लद्दाख के लिए स्वायत्तता की मांग करता रहा. इन्हीं मांगों ने स्थानीय मुस्लिम और बौद्ध समुदायों के बीच राजनीतिक दूरी पैदा कर दी. 1969 में बौद्धों के झंडे का किसी मुसलमान द्वारा अनादर किए जाने की घटना, बौद्धों के जुलूस द्वारा जामिया मस्जिद एवं इमामबाड़े पर पथराव एवं कारगिल में इसके ख़िलाफ़ तीखी प्रतिक्रिया से सांप्रदायिक विभाजन और गहरा हो गया. बुद्धिस्ट एक्शन कमेटी ने एक साथ कई मांगों के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, जिनमें लद्दाखी जनता को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, तिब्बती शरणार्थियों को लद्दाख में समायोजित करना, कारगिल में एक रेस्ट हाउस का निर्माण, शिक्षा में माध्यमिक स्तर तक बोधि भाषा को आवश्यक विषय के रूप में मान्यता और राज्य सरकार में लद्दाख मामलों के लिए अलग से कैबिनेट मंत्री की व्यवस्था आदि प्रमुख थीं. राज्य सरकार ने इनमें से कुछ मांगों को मान लिया, लेकिन कारगिल मुस्लिम एक्शन कमेटी के तीखे विरोध के चलते अन्य मांगों को मानने से इंकार कर दिया. मुस्लिम एक्शन कमेटी के विरोध की वजह यह थी कि उसे डर था कि इन मांगों को माने जाने से क्षेत्र में बौद्धों का प्रभुत्व और बढ़ जाएगा.

कारगिल क्षेत्र का शिया मुस्लिम समुदाय अब ख़ुद को कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़कर देखने लगा. हालांकि कश्मीर क्षेत्र के अधिकांश मुस्लिम सुन्नी हैं और कारगिल के बहुसंख्यक शिया मुस्लिमों के साथ सांस्कृतिक स्तर पर वे काफी अलग हैं. 1980 में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करते बौद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के बाद ऑल पार्टी लद्दाख एक्शन कमेटी का गठन किया गया, ताकि इस मांग को और प्रभावशाली तरीक़े से उठाया जा सके. इसके ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कारगिल एक्शन कमेटी के रूप में एक समानांतर संगठन का गठन किया. कारगिल एक्शन कमेटी ने मांग की कि जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर लेह और लद्दाख के दो ज़िलों को भी अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए. एक स्वायत्तशासी लद्दाख में लेह की बौद्ध जनता के साथ मिलाए जाने से कारगिल का मुस्लिम समुदाय स्वाभाविक रूप से डर महसूस कर रहा था. लद्दाखी जनता के बीच इन मतभेदों के आधार पर राज्य सरकार ने कारगिल एक्शन कमेटी की मांगों का हवाला देते हुए लद्दाख के लिए प्रांतीय स्वायत्तता की मांग को नामंजूर कर दिया.

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं के लिए नैब्यूला रेंज की घड़ियां क्लासिक लैदर स्ट्रैप के अलावा स्टाइलिश कड़ा और ट्रेंडी ब्रेसलेट के पैटर्न में भी उपलब्ध हैं.

फन बाइकिंग का मजा

जापानी कंपनी होंडा ने टू व्हीलर की दुनिया में धमाका करते हुए भारतीय बाज़ार में एक नई बाइक उतारी है. बाइक राइडर्स के स्टाइल और पैशन राइडिंग एक्सपीरिएंस को बढ़ावा देते हुए कंपनी ने होंडा सीबी यूनिकॉन डैजलर नामक बाइक लांच की है, जो आधुनिक उपकरणों से लैस है. परफार्मेंस और माइलेज के हिसाब से भी यह बेहतर है. 150 सीसी इंजन के साथ यह बाइक 14 बीएचपी का पावर देती है. पावरफुल इंजन की वजह से यह लंबे वक्त तक कामयाब रहेगी और ख़राब नहीं होगी. इसमें लगे 110/80 वाइड रीयर ट्यूबलेस टायर्स एवं व्हील्स बेहतरीन पिकअप और माइलेज देते हैं. इस बाइक के अन्य फीचर्स में हाफ चेन केस, टू-टोन सीट, नई डिज़ाइन का आईना, चमचमाता थ्री डायमेंशनल लेबल और डिजिटल मीटर आदि हैं. इसके फ्रंट और रीयर डिस्क ब्रेक अचानक सामने आने वाली चीज पर संतुलित तरीक़े से ब्रेक लेने में कारगर हैं. यह बाइक साठ किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इस ख़ास बाइक में मेंटेनेंस फ्री बैट्री और विसकस एयर फिल्टर लगे हैं, जिससे राइडर को बाइक की मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. होंडा सीबी यूनिकॉन डैजलर बाइक इस प्रकार तैयार की गई है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुक़सान पहुंचे. यह स्टाइलिश बाइक मेटालिक गोल्डन, पर्ल ब्लैक, मेटालिक सिल्वर और पर्ल रेड कलर्स में उपलब्ध होगी. भारत में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स के प्रेसिडेंट शिंजी ओयामा ने कहा कि भारतीय ग्राहकों से मिले अच्छे रेस्पॉन्स की वजह से ही जापानी कंपनी होंडा भारत में अपने क़दम जमा सकी. होंडा सीबी यूनिकॉन डैजलर भारतीय ग्राहकों को फन बाइकिंग कल्चर से अवगत कराएगी, जिससे बाइक राइडिंग में भारतीय युवाओं की रुचि और बढ़ जाएगी. भारतीय बाज़ार में इस बाइक की क़ीमत 62,900 रुपये है.

फैशन में हैं स्टाइलिश घड़ियां

आभूषण और शृंगार अब केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आजकल पुरुष भी इनमें खासी रुचि लेने लगे हैं. पुरुषों के आभूषणों में घड़ी, ब्रोच, अंगूठी, चेन एवं कफलिंक्स आदि हैं. वैसे घड़ी तो किसी भी उम्र-वर्ग की महिलाओं और पुरुषों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण एक्सेसरी है. इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध कंपनी टाइटन ने इस एक्सेसरी को स्टाइलिश बनाने के लिए एक ख़ास प्रयोग किया है. टाइटन ने टाइटन नैब्यूला रेंज के अंतर्गत 18 कैरेट सोने से निर्मित आभूषण रूपी घड़ियों को बाज़ार में उतारा है. नैब्यूला रेंज की घड़ियां भारत की पहली सॉलिड गोल्ड वॉच हैं. इस रेंज में कंपनी ने दस घड़ियों की एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन नैब्यूला कैलीग्राफी घड़ियां भी पेश की हैं. कैलीग्राफी कला से प्रेरित इन घड़ियों को 18 कैरेट सोने में ढाला गया है. उक्त घड़ियां उम्दा कारीगरी का अद्भुत नमूना हैं. नैब्यूला कलेक्शन में 18 कैरेट प्लेन गोल्ड के अलावा मोतियों और हीरों की झिलमिलाहट से सजी घड़ियां भी हैं. हर घड़ी पर सैफायर क्रिस्टल ग्लास लगा है, जिसकी आभा हीरे से कम नहीं है. महिलाओं के लिए नैब्यूला रेंज की घड़ियां क्लासिक लैदर स्ट्रैप के अलावा स्टाइलिश कड़ा और ट्रेंडी ब्रेसलेट के पैटर्न में भी उपलब्ध हैं. इसी तरह पुरुषों के लिए लैदर स्ट्रैप के अलावा शुद्ध सोने से निर्मित स्ट्रैप का विकल्प भी है. नैब्यूला कलेक्शन बहुत बारीकी और ख़ूबसूरती के साथ तैयार किया गया है. ऐसी घड़ियां वैवाहिक या साधारण परिधान के साथ एकदम उपयुक्त एक्सेसरी साबित होंगी. विवाह हो या छोटी-मोटी बैचलर या किटी पार्टी, हर अवसर पर पहनी जाने वाली पोशाकों पर इस रेंज की घड़ियां फबती हैं. नैब्यूला ज्वेलरी घड़ियों की क़ीमत 10,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये तक है. इन्हें देश के सभी वर्ल्ड ऑफ टाइटन शोरूमों से ख़रीदा जा सकता है. हर घड़ी के साथ ग्राहक को लाइफटाइम वारंटी भी मिलती है.

महिलाओं के लिए नैब्यूला रेंज की घड़ियां क्लासिक लैदर स्ट्रैप के अलावा स्टाइलिश कड़ा और ट्रेंडी ब्रेसलेट के पैटर्न में भी उपलब्ध हैं. इसी तरह पुरुषों के लिए लैदर स्ट्रैप के अलावा शुद्ध सोने से निर्मित स्ट्रैप का विकल्प भी है.

feedback@chauthiduniya.com

टाइटन आई प्लस के चश्मों की नई रेंज

इटली के सैल्विनो दमेट ने 1284 में चश्मे का आविष्कार किया था. उसके बाद विश्व के हर देश-हर प्रांत में चश्मे का इस्तेमाल होने लगा. तब से आज तक चश्मे को नित नया रूप दिया जाता रहा है. कमजोर नज़र के लिए पावर वाले चश्मे, गर्मियों में हर उम्र के लोगों द्वारा पहने जाने वाले स्टाइलिश गॉगल्स, पर्सनालिटी को बेहतर लुक देने के लिए ट्रांसपेरेंट अलग-अलग शेप के ग्लासेस बाज़ार में उपलब्ध हैं. बाज़ार में पुरुषों के लिए अलग डिज़ाइन मिलते हैं तो महिलाओं के लिए अलग. टाटा की सह कंपनी टाइटन आई प्लस ने महिलाओं के लिए ख़ास चश्मों की नई रेंज बाज़ार में उतारी है. कंपनी ने स्टाइलिश और कंटेंपरेरी डिज़ाइन के चश्मों के फ्रेम की नई रेंज लांच की है. इसमें रिमलेस फ्रेम हर आकार में उपलब्ध है. मसलन गोलाकार, चौकोर एवं डायमंड शेप आदि. यानी हर तरह के चेहरे के लिए अलग-अलग आकार के फ्रेम इस रेंज में मिल जाएंगे. फ्रेम को ख़ूबसूरत लुक देने के लिए इसमें छोटे-छोटे रंगीन नग जड़े गए हैं. ये फ्रेम गोल्डन और रोज पिंक रंगों में उपलब्ध हैं. फ्रेम हर उम्र की महिला के चेहरे पर फबेगा और पर्सनालिटी में चार चांद लगा देगा. इसलिए इस रेंज के फ्रेम को हर अवसर पर हर रिश्ते की ख़ूबसूरती बरकरार रखने के लिए तोहफ़े के तौर पर भी भेंट किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि इस रेंज को ख़ास इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इन फ्रेमों की क़ीमत 2800 रुपये से शुरू होती है. इन्हें आप देश के किसी भी टाइटन आई प्लस स्टोर से ख़रीद सकते हैं. देश के छोटे-बड़े शहरों में कंपनी के 76 स्टोर्स हैं.

युवाओं को लुभाएगा लिवाइस

कपड़ों की ब्रांडेड कंपनी लिवाइस ने भारत में सफलता के 15 वर्ष पूरे किए हैं. युवाओं को ख़ासतौर पर आकर्षित करने वाले इस ब्रांड ने अपनी सफलता पर ग्राहकों को ख़ास उपहार देने का फैसला किया है. कंपनी ने चेंज योर वर्ल्ड नाम का कैंपेन शुरू किया है. इसके अंतर्गत लिवाइस ने एक म्यूजिक वीडियो, फेलोशिप म्यूजिक काईस और ढेर सारा उपहार सामग्री लांच किया है. म्यूजिक वीडियो लिवाइस की ब्रांड एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा पर फ़िल्माया गया है. प्रियंका इस म्यूजिक एलबम के गीतों पर तीन शहरों में टूर के दौरान लाइव परफॉर्म करेंगी. प्रियंका ने कहा कि लिवाइस जैसे ब्रांड और चेंज योर वर्ल्ड कैंपेन से जुड़कर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है. चेंज योर वर्ल्ड कैंपेन के तहत कंपनी एक रचनात्मक पहल करेगी, जिसमें एक ऐसे प्रतिभाशाली बैंड को चिन्हित करने की योजना बनाई जा रही है, जो प्रसिद्धि एवं गौरव की ऊंचाइयां स्पर्श कर सके. कंपनी की वेबसाइट पर नए दौर के संगीतज्ञों को प्रोत्साहन मिलेगा. वहां सर्फिंग करने वाले लोग ध्वनि के एक नवीन ब्रांड में शिरकत कर सकते हैं. भारतीय लोगों द्वारा चयनित बैंड का नाम चार्ट टॉपिंग बैंड होगा और इसके लिए म्यूजिक काईस के आधार पर बैंड को चुना जाएगा. यह म्यूजिक काईस उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा दिया जा रहा एक नि:शुल्क सेलिब्रेशन उपहार जैसा है, जिसे वे इस मौसम में लिवाइस के स्टोर्स से प्राप्त कर सकेंगे. कंपनी ने कैंपेन के अंत में जीतने वाले 15 युवाओं को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की बात कही है. इसके साथ ही लिवाइस स्टोर्स में ग्राहकों के लिए ढ़ेर सारे उपहार भी उपलब्ध हैं. लिवाइस ब्रांड इंडिया के मार्केटिंग डायरेक्टर श्याम सुखरमानी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों के दौरान कंपनी का विकास अद्भुत रहा है. लिवाइस युवाओं की पसंदीदा कॉलेज ड्रेस, रॉक स्टार्स गारमेंट और फेस्टिव पहनावा हो बन चुका है. ग्राहक प्रति 1000 रुपये की ख़रीद पर एक बोनस कार्ड पाएंगे और उसमें अंकित कोड को 54646 पर एसएमएस कर उपहार जीत सकेंगे. उपहारों में 7 कस्टमाइज्ड शेवी बीट्स, 50 कस्टमाइज्ड एपल मैकबुक्स, 150 कस्टमाइज्ड एपल आइफोंस 3 जीएस, 1500 कस्टमाइज्ड एपल आइपॉड शफल्स आदि प्रमुख हैं. समूचे देश में लिवाइस स्टोर्स में स्लैब बेस्ड गिफ्ट्स मौजूद होंगे. इनमें म्यूजिक काईस, रिस्टबैंड्स, मोबाइल पाउचेज, ड्रास्ट्रिंग बैग्स एवं कूल क्लॉक्स शामिल हैं.

प्रियंका ने कहा कि लिवाइस जैसे ब्रांड और चेंज योर वर्ल्ड कैंपेन से जुड़कर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कब तक कोशिश करता रहेगा, कब तक टीम के कप्तान और खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिशें होती रहेंगी.

ज़िम्मेदारियों से कब तक भागता रहेगा बीसीसीआई

आदित्य पूजन

हमारे देश में क्रिकेट के रहनुमाओं के तो क्या कहने! टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद प्रशंसकों का पारा चढ़ा तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को निशाने पर लेने की कोशिश की. धोनी को कप्तानी से हटाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो इसका और भी विरोध होने लगा. यह सही भी था, क्योंकि पूरी टीम के ख़राब प्रदर्शन के लिए अकेले कप्तान को ज़िम्मेदार ठहराना कहां तक उचित हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई को तो अपना मुंह छिपाने के लिए बलि के बकरों की तलाश थी. धोनी को सूली पर चढ़ाने में क़ामयाबी नहीं मिली तो बोर्ड ने टीम के छह खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया. युवराज सिंह, रोहित शर्मा, आशीष नेहरा, ज़हीर ख़ान, रवींद्र जडेजा और पीयूष चावला से सात दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया. यह नोटिस एक ऐसी घटना को लेकर जारी किया गया, जो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद घटित हुई और जिसके बारे में केवल खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम के मैनेजर रंजीव बिस्वाल भी पहले से इंकार कर चुके थे.

लेकिन बीसीसीआई की नादानी का आलम यह है कि बिस्वाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. सवाल यह है कि हार के बाद मचे बवंडर के बीच बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कब तक कोशिश करता रहेगा, कब तक टीम के कप्तान और खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिशें होती रहेंगी. बीसीसीआई द्वारा जारी की गई कारण बताओ नोटिस का आधार एक ऐसी घटना को बनाया गया है, जिसकी सत्यता पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं. 11 मई को हुई इस घटना के दिन भारत श्रीलंका के ख़िलाफ़ सुपर-8 का लगातार तीसरा मुक़ाबला हार कर टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था.

बीसीसीआई के मुताबिक़, इसके बाद टीम इंडिया के कई खिलाड़ी मौजमस्ती के लिए सेंट लूसिया के एक पब में गए और वहां पहले से मौजूद भारतीय मूल के कुछ लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो गई. मामला हाथापाई तक पहुंच गया और बाद में सुरक्षाकर्मियों की मदद से उसे क़ाबू में किया जा सका. उधर मीडिया में आ रही ख़बरों के आधार पर कहा यह भी जा रहा है कि पब में खिलाड़ियों के साथ कुछ घटना हुई ज़रूर थी, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी. खिलाड़ी एक समूह में पब में पहुंचे थे और वहां कुछ भारतीय मूल के लोगों ने उनके घटिया प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्हें गालियां देनी शुरू कर दीं. इस दौरान वहां कुछ अन्य देशों की टीमों के खिलाड़ी भी मौजूद थे. भारतीय टीम के कुछ जूनियर खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया. मामला ज़्यादा तूल पकड़ता, इससे पहले ही टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीचबचाव करते हुए सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया और सब कुछ सामान्य हो गया. बीसीसीआई इसी मामले को तूल देते हुए खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश करने लगा.

टीम के मैनेजर रंजीव बिस्वाल ने शुरुआत में खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे दी, लेकिन जैसे ही बीसीसीआई के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई तो मामला पूरी तरह बदल गया. बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रत्नाकर शेट्टी ने बिस्वाल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अब सवाल यह है कि जिस घटना के लिए खिलाड़ी पूरी तरह ज़िम्मेदार न हों, उसके आधार पर उनके ख़िलाफ़ नोटिस कैसे जारी किया जा सकता है. हार और जीत तो हर खेल का एक हिस्सा है. कोई यदि यह सोचता है कि हारने के बाद खिलाड़ियों को दुःख नहीं होता तो यह एक बड़ी भूल है. जितनी निराशा आम लोगों को होती है, उससे कहीं ज़्यादा निराश खिलाड़ी ख़ुद होते हैं. ख़ुद को क्रिकेट का बड़ा विशेषज्ञ मानने वाले लोगों को भला क्या मालूम कि मैदान के अंदर खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का कितना ज़्यादा दबाव होता है और जी-जान लगाने के बाद भी जब जीत उनसे दूर रह जाती है तो निराशा और गम का होना लाज़िमी है. फिर यदि बीसीसीआई केवल पब में जाकर मौजमस्ती करने के लिए खिलाड़ियों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है तो यह काम उसने आईपीएल के दौरान क्यों नहीं किया, जिसकी लेट नाइट पार्टियां मैदान पर होने वाले खेल के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा रंगीन हुआ करती थीं? कहीं इसकी वजह यह तो नहीं कि उक्त पार्टियां प्रायोजकों द्वारा आयोजित की जाती थीं और ख़ुद बोर्ड के अधिकारी भी उनमें शरीक होते थे. सवाल यह भी है कि यदि रंजीव बिस्वाल ने पहली बार में खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे दी थी तो बीसीसीआई को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद माज़रा बदल कैसे गया?

दरअसल, यह मामला उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है, जितना नज़र आता है. वर्ल्ड कप में टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद प्रशंसकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा तो सबसे ज़्यादा भद्द बीसीसीआई और उसकी चयन समिति की ही पिटी. टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसके लिए आईपीएल की पार्टियों को ज़िम्मेदार बताया तो कोच गैरी कर्स्टन ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवाल उठाए. अनफिट और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को टीम में चुने जाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है, खासकर तब, जबकि उनके विकल्प मौजूद हों. इसके लिए बोर्ड की चयन समिति ही अकेली ज़िम्मेदार हो सकती है. लेकिन सच्चाई यही है कि न तो बीसीसीआई और न ही के श्रीकांत की अध्यक्षता वाली चयन समिति इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है और अपनी गर्दन बचाने के लिए बोर्ड खिलाड़ियों को बेवजह परेशान कर रहा है. जिन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ यह नोटिस जारी किया गया है, उनमें से कई ऐसे भी हैं, जो जिम्बाब्वे गई भारतीय टीम में शामिल हैं. इस अनावश्यक दबाव के बीच उनसे किसी ख़ास प्रदर्शन की उम्मीद करना भी बेमानी है.

लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा. कब तक बीसीसीआई अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता रहेगा और कब तक टीम के कप्तान और खिलाड़ियों को इस तरह बलि का बकरा बनाने के प्रयास होते रहेंगे? विश्व की सबसे धनी और अधिकार संपन्न क्रिकेट संस्था चलाने वाले लोग आखिर कब जवाबदेह बनेंगे और उनकी यह जवाबदेही किसके प्रति है, सरकार, देश की जनता या फिर क्रिकेट? दरअसल, बीसीसीआई की ज़िम्मेदारी इन तीनों के प्रति है. उसकी पहली ज़िम्मेदारी सरकार के प्रति बनती है, क्योंकि सरकार ही मैचों के आयोजन के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है. उसकी ज़िम्मेदारी जनता के प्रति भी है, क्योंकि आज यदि बीसीसीआई विश्व की सबसे धनी संस्था बना हुआ है तो वह पैसा जनता की जेब से ही आता है. लेकिन बोर्ड की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्रिकेट के खेल के प्रति है, जिसके नाम पर वह सरकार और जनता को बार-बार मूर्ख बनाने की कोशिश करता है. डर इस बात का है कि आज यदि भारत सरकार और जनता नहीं चेती तो देश में क्रिकेट का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा. खेल मंत्री एम एस गिल ने दूसरे खेल संघों के अधिकारियों पर नकेल कसने का अभियान शुरू किया तो उनके ख़िलाफ़ तलवारें खिंच गईं. अब ऐसा ही अभियान बीसीसीआई के आकाओं के ख़िलाफ़ भी शुरू करना होगा. टीम जीतती है तो बीसीसीआई के अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने से नहीं चूकते, लेकिन जब टीम हारती है तो वे अपने बिल से बाहर नहीं निकलते. बीसीसीआई को अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी लेनी ही होगी, वरना देश की जनता और उसकी भावनाओं के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्रिकेट के विश्व कप में इंग्लैंड की पहली ख़िताबी जीत

क्रिकेट के जन्मदाता माने जाने वाले इंग्लैंड ने तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर क्रिकेट के किसी भी विश्व कप में ख़िताबों का अपना अकाल दूर कर लिया. 16 मई को वेस्टइंडीज के बारबाडोस में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से शिकस्त देकर यह जीत हासिल की. इंग्लैंड टीम की यह जीत इसलिए ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक तो यह क्रिकेट के किसी भी विश्व कप में उसकी पहली ख़िताबी जीत है और दूसरा यह कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तक कोई इंग्लैंड को दावेदार मानने के लिए भी राजी नहीं था, लेकिन पॉल कोलिंगवुड की कप्तानी में इंग्लैंड ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए सबको हैरान कर दिया. टीम ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया तो फाइनल मुक़ाबले में अपने एशेज प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाते हुए इंग्लिश क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत करने में क़ामयाबी हासिल की. इंग्लैंड की इस जीत में हालांकि पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए केविन पीटरसन की इसमें अहम भूमिका रही. पीटरसन ने तक़रीबन हर मैच में बेहतरीन बल्लेबाज़ी करते हुए टीम की जीत का रास्ता प्रशस्त किया. उनके अलावा टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज़ क्रेग कीजवेटर, सलामी बल्लेबाज़ माइकल लंब, स्पिनर ग्रीम स्वान, तेज गेंदबाज रियान साइडबाटम और कप्तान कोलिंगवुड ने भी अपनी ज़िम्मेदारियों का बख़ूबी निर्वाह करते हुए टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. टीम के खिलाड़ियों ने गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी के अलावा क्षेत्ररक्षण में भी अपना जलवा बिखेरते हुए किसी भी प्रतिद्वंद्वी टीम को हावी होने का मौक़ा नहीं दिया. इस ख़िताबी जीत से पहले तक इंग्लैंड टीम पर अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे थे कि विश्वस्तरीय टूर्नामेंटों में उसका प्रदर्शन उम्मीदों पर ख़रा नहीं उतरता, क्योंकि वह दबाव में बिखर जाती है. क्रिकेट की जन्मभूमि होने के बावजूद विश्व कप न जीत पाने का गम हर क्रिकेटप्रेमी को साल रहा था, लेकिन तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम ने इस कलंक को भी धो डाला. इंग्लैंड की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टी-20 वर्ल्ड कप के पहले दो संस्करणों में एशियाई उपमहाद्वीप की टीमें (भारत और पाकिस्तान) विजयी रही थीं और यह कहा जाने लगा था कि क्रिकेट के इस फटाफट अवतार में जीत का फ़ार्मूला केवल उपमहाद्वीप की टीमों के पास है, लेकिन इंग्लैंड की जीत ने इस मिथक को भी दूर कर दिया.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 31 मई–6 जून 2010

द लास्ट लीयर के बाद दिव्या को एक और हॉलीवुड प्रोजेक्ट मिल गया है. वह जल्द ही सात समंदर पार के दर्शकों का मनोरंजन हॉलीवुड फ़िल्म हिस्स में करेंगी.

दीपिका की नई सहेली

दीपिका पादुकोण उन ख़ास बॉलीवुड अभिनेत्रीयों में शुमार हो गई हैं जिन्हें प्रतिष्ठित फ़िल्म पुरस्कार समारोह के लिए कान जाने का मौक़ा मिला. ऐसे समारोहों में अक्सर अभिनेत्रियों के परिधान को लेकर कोई ना कोई टिप्पणी ज़रूर होती है. लेकिन इस बार किसी के भी पहनावे पर कोई टिका-टिप्पणी नहीं हुई. इससे बचने के लिए दीपिका अपनी पूरी तैयारी के साथ कान फ़िल्म समारोह में शामिल होने गई थीं. पारंपरिक साड़ी में वो जहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही थी वहीं स्टाइलिश अंदाज़ में बॉलीवुड की स्टाइल आइकन के रूप में भी नज़र आई. वह कहती हैं कि जितना हो-हंगामा हर बार अभिनेत्रियों के पहनावे को लेकर होता है, उस तरह का फैशन वहां देखने को नहीं मिला. वहां किसी का भी पहनावा उनकी आंखों को आकर्षित नहीं कर सका. उनका मानना है कि जब कान जैसे अंतराष्ट्रीय समारोह में कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने जाए तो उसे सिर्फ़ विचारों से ही नहीं पोशाक और आचरण से भी भारतीय ही दिखना चाहिए. वह कहती हैं कि गाउन ना पहनकर रोहित बल की डिज़ाइन की गई साड़ी पहनकर इस समारोह में आना उनके लिए प्रतिष्ठा की बात है. बहरहाल दीपिका के लिए कान समारोह में शिरकत करने के साथ उनकी निजी ज़िंदगी में भी कुछ ख़ास हुआ है. दरअसल आजकल वह सलमान ख़ान की बहन अर्पिता ख़ान से दोस्ती में मशगुल हैं. लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें सलमान के साथ कोई फ़िल्म करनी है बल्कि इसलिए कि अर्पिता का स्वभाव दीपिका से काफ़ी मिलता हैं.

मनीषा कोइराला की मुश्किल

फ़िल्म सौदागर से इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फ़िल्में दीं. बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम एवं खामोशी आदि ऐसी फ़िल्में हैं, जिनमें इस नेपाली बाला के काम को बहुत सराहा गया, लेकिन पिछले कुछ समय से वह रुपहले पर्दे से लगभग ग़ायब हो गई थीं. अब उनके प्रशंसकों के लिए ख़ुशख़बरी यह है कि वह शीघ्र ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. कुछ टूटे-पुराने रिश्तों को भुलाकर आखिरकार चालीस वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बसाने का फ़ैसला कर लिया है. उनके भावी पति सम्राट दहल नेपाल में चमड़े का व्यापार करते हैं. उनका व्यवसाय काठमांडू के अलावा भारत में कोलकाता, चेन्नई, आगरा, दिल्ली और कानपुर में भी फैला हुआ है. वह और मनीषा दोस्तों के जरिए मिले थे और फिर उन्होंने जीवन भर एक-दूसरे का साथ देने के लिए शादी करने का फ़ैसला कर लिया. उन्होंने अपने मन की बात अपने-अपने माता-पिता को बताई और शादी तय हो गई. आम पत्नियों की तरह ही मनीषा अपने होने वाले पति की शिक़ायत करती हैं कि वह हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वह एक अच्छे, सच्चे और बुद्धिमान इंसान हैं. मनीषा कहती हैं कि सम्राट को फ़िल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने शायद ही उनकी फ़िल्म 1942-ए लव स्टोरी देखी हो, लेकिन वह उन्हें एहसास दिलाना चाहती हैं कि बॉलीवुड केवल मस्ती और ग्लैमर का जहां नहीं है, बल्कि यहां कायम रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए मनीषा सम्राट को कई बार सेट पर शूटिंग देखने के लिए बुला लेती हैं. जब सम्राट मनीषा को ऐक्टिंग करते हुए देखते हैं, तो वह भी महसूस करते हैं कि फ़िल्मों में काम करना कितना मुश्किल होता है. अपने घर-परिवार से दूर भारत में अकेले रहने को लेकर सम्राट के मन में मनीषा के लिए कई सवाल उमड़ रहे थे. 2001 में नेपाल में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत क्रिस्पिन कॉन रॉय और पिछले साल अमेरिकी लेखक क्रिस्टॉफर डोरिस के साथ संबंधों की चर्चा की वजह से मनीषा ने सम्राट को मुंबई में अपने दोस्तों से मिलवाया. अच्छी बात यह है कि सम्राट को मनीषा के दोस्त बहुत पसंद आए. शादी के बाद मनीषा अपने पति के साथ नेपाल में रहेंगी या भारत में, यह उन्होंने अभी सोचा नहीं है, पर उन्होंने यह तय कर लिया है कि बॉलीवुड में काम करना नहीं छोड़ेंगी. वह रुपहले पर्दे पर एक नई पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. उनके पास एक नहीं, कई फ़िल्में हैं. उनकी आने वाली एक फ़िल्म मायावती पर आधारित है. इसके अलावा इस साल रिलीज होने वाली फ़िल्मों में दो पैसे की धूप-चार आने की बारिश, चेहरे और एक सेकंड-जो ज़िंदगी बदल दे आदि शामिल है.

दिव्या दत्ता का नया रूप

सह अभिनेत्री ही सही, लेकिन दिव्या दत्ता की पहचान बॉलीवुड में एक अच्छी कलाकार के रूप में है. उन्होंने अपनी हर फ़िल्म में अभिनय की एक नई छाप छोड़ी है. उनके काम को तारीफ़ और पहचान मिली फ़िल्म वीर-ज़ारा में शब्बो के किरदार से. उसके बाद दिल्ली-6 में जलेबी के किरदार में उन्होंने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया. इस बार भी उन्हें अलग तरह का किरदार बखूबी निभाने के लिए सराहा गया. दिव्या का करियर इन दिनों आसमान छू रहा है. अब उनकी तैयारी है प्रशंसकों को अपने अलग लुक के जरिए प्रभावित करने की. द लास्ट लीयर के बाद उन्हें एक और हॉलीवुड प्रोजेक्ट मिल गया है. वह जल्द ही सात समंदर पार के दर्शकों का मनोरंजन हॉलीवुड फ़िल्म हिस्स में करेंगी. इसमें उन्होंने इरफ़ान ख़ान के अपोजिट हॉट एंड सेंसुअल भूमिका निभाई है. इस फ़िल्म का निर्माण अमेरिका और भारत द्वारा संयुक्त रूप से हो रहा है. इसके निर्देशक जेनिफर चेंबर्स लिंक हैं. इसमें उनकी सहअभिनेत्री के तौर पर मल्लिका शहरावत ने काम किया है. और बतौर एक्टर जेफ डोकेट काम कर रहे हैं. यह फ़िल्म एक नागकथा पर आधारित है. इसमें एक नागिन के बदले की कहानी है, जिसके नाग को एक अमेरिकी शिकारी पकड़ लेता है. फ़िल्म इसी साल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी. दूसरी फ़िल्म मोनिका में दिव्या का रोल लीक से हटकर है. इसमें वह लेस्बियन की भूमिका में हैं. वह किट्टू गिडवानी की सेक्स लाइफ पार्टनर बनी हैं. दोनों ही रोल उनके पिछले किरदारों से अलग है और चैलेंजिंग भी. दिव्या कहती हैं कि यह रोल करने में उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई. वैसे भी दिव्या, विविधता तो अच्छे काम की पहचान होती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फ़िल्म रिव्यू प्रिव्यू

नए अंदाज में दर्शील व प्रियदर्शन

आतंकवाद या उग्रवाद केवल राजनीतिक समस्या ही नहीं, बल्कि यह क्षेत्र विशेष में रहने वाले आम आदमी के लिए मुसीबतों का सबब भी है. इस समस्या से प्रभावित इलाक़ों में रहना कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा हमें आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों के ख़बरों के माध्यम से मिलता रहता है. यहां के सिविलियन कभी फौजियों के शक का, तो कभी आतंकियों के हमलों का निशाना बनते रहते हैं. तेरह अप्रैल को कश्मीर में एक सत्तर साल के वृद्ध को आतंकवादी मानकर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. जबकि तीन दिनों बाद परिवारीजनों द्वारा शिनाख़्त करने पर पता चला कि वह आतंकवादी नहीं, एक मामूली भिखारी है. पुलिस को ग़लत ख़बर मिली थी, लेकिन बिना किसी छानबीन के पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, इसका ख़ामियाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके परिवारवालों को उठाना पड़ा. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में किसी भी सिविलियन के आतंकवादियों से संपर्क का पता चलते ही उस व्यक्ति और उसके परिवारवालों पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है. बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार के उस व्यक्ति का जीना हराम हो जाता है. वह समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है. जबकि पुलिस उन तत्वों का पता लगाने में विफ़ल रहती है, जो वास्तव में आतंकियों के संपर्क में रहते हैं.

ईरानी निर्देशक माज़िद मज़ीदी की बहुचर्चित फ़िल्म चिल्ड्रेन ऑफ हेवन पर आधारित फ़िल्म बमबम बोले भी एक ऐसे ही परिवार की कहानी है. असम के एक गांव में उग्रवादियों का साथी कहकर समाज द्वारा निष्कासित किया गया दयाराम (अतुल कुलकर्णी), उसकी पत्नी (रितुपर्णा सेनगुप्ता) और उसका परिवार मुश्किल भरे हालात का सामना करता है. जीवनयापन के सारे रास्ते बंद हो जाने से उसका परिवार ग़रीबी की आग में झुलसता रहता है. इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है. बेटे पिनू (दर्शील सफ़ारी) और नन्हीं बेटी रिमझिम (जिया) को एक जोड़ी जूतों में शेयर करके स्कूल जाना पड़ता है. ऐसे में पिनू की ख्वाहिश यही होती है कि वह अपनी बहन को किसी तरह नए जूते लाकर दे दे. तारे जमीं पर के किरदार से उलट दर्शील ने इस फ़िल्म में गंभीर किरदार बख़ूबी अदा किया है. रिमझिम के किरदार में बेबी जिया ने छोटी सी उम्र में अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया है. कॉमेडी फ़िल्मों में माहिर प्रियदर्शन ने इस बार अपनी फ़िल्म से समाज के एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है. ख़ूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और कसी हुई स्क्रिप्ट पर प्रियदर्शन ने सभी कलाकारों की अभिनय क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया है.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

आधुनिक युग का नायक है रावण

एक दौर था, जब विशुद्ध धार्मिक फ़िल्में बनती थीं. समय बदला, बॉलीवुड में फ़िल्म निर्माण से जुड़े लोगों के काम करने का तरीक़ा बदला और धार्मिक पृष्ठभूमि की आधुनिक कहानियों पर फ़िल्में बनने लगीं. मल्टीप्लेक्स के इस दौर में हमारे प्राचीन ग्रंथों, मुख्य रूप से रामायण एवं महाभारत के किरदारों को आधार बनाकर पटकथाएं लिखी जा रही हैं. प्रकाश झा की फ़िल्म राजनीति में जहां महाभारत के चरित्रों को उठाया गया है, वहीं मणिरत्नम की फ़िल्म रावण रामायण की आधुनिक संस्करण मानी जा रही है.

मणिरत्नम द्वारा लिखित-निर्देशित इस फ़िल्म के मुख्य कलाकार हैं अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु, गोविंदा, विक्रम, रविकिशन, निखिल द्विवेदी एवं सुहासिनी. अभिषेक बच्चन एक सताई हुई बहन के भाई बने हैं और वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या राय का अपहरण कर लेते हैं. बिपाशा अभिषेक बच्चन की पत्नी का रोल अदा कर रही हैं. अभिषेक रावण, विक्रम राम और ऐश्वर्या सीता के किरदारों में हैं. अपहरण के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच ख़ास तरह के दया भावना वाले एहसास भरे रिश्ते बनने लगते हैं, जिसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहा जाता है. फ़िल्म की कहानी का सार यह है कि हर शख्स के अंदर एक राम और रावण छिपा है, जो समय आने पर सामने दिखने लगता है. फ़िल्म के कुछ सीन कोलकाता के एक हाउसिंग कॉम्पलेक्स को वैदिक गांव का रूप देकर शूट किया गया हैं. यह फ़िल्म तीन भाषाओं यानी हिंदी, तेलुगु और तमिल में एक साथ दो जून को रिलीज होगी. रावण के तमिल और तेलगु संस्करण में अभिषेक बच्चन नहीं हैं, जबकि ऐश्वर्या राय तीनों संस्करणों में हैं. संगीत ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित रहमान ने दिया है, जबकि गीतकार गुलजार हैं. म्यूजिक ऑडियो के वितरण का अधिकार टी-सीरीज के पास है. फ़िल्म वितरण का जिम्मा संभाला है मद्रास टॉकीज और बिग पिक्चर्स ने.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 31 मई-6 जून 2010

www.chauthiduniya.com

किसका विश्वास कैसी यात्रा

जनता का भरोसा जीतने विश्वास यात्रा पर निकले नीतीश कुमार उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन्होंने साढ़े चार साल पहले उन्हें सत्ता सौंपी थी. इसलिए उनके कानों तक जिंदाबाद के नारे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मुर्दाबाद की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचने से पहले ही कहीं गुम हो जाती है.

सरोज सिंह

यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वास यात्रा के पहले चरण का आख़िरी दिन था. मुज़फ़्फ़रपुर के पानापुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जनता को विश्वास दिलाने निकला हूं कि हमारी सरकार ने वे सारे काम किए हैं, जिसकी अपेक्षा जनता ने हमसे की थी, लेकिन इस दौरान उनकी नज़रों ने इस बैनर को नहीं देखा, जो स्थानीय जनता की ओर से लगाया गया था और जिस पर लिखा था. मुख्यमंत्री जी, आप माननीय हैं, लेकिन हमारे साथ मानवीय व्यवहार नहीं करते. हम बड़ी आशा के साथ आपको भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं, लेकिन वह रद्दी की टोकरी में चला जाता है. मीनापुर और मोतीपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार की सैकड़ों घटनाएं उजागर हो चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी या कर्मचारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है.

पानापुर की सभा एक घंटे तक चली. लोग इंतजार करते रहे कि जनता का विश्वास देखने निकले मुख्यमंत्री उनकी फरियाद पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सभा समाप्त होते ही नीतीश के हेलीकॉप्टर की पंखियां घुमीं और उससे निकली तेज़ हवा में जनता की फरियाद भी उड़कर कहीं गुम हो गई. बड़े ही तामझाम के साथ निकली नीतीश की विश्वास यात्रा बिहार के गांवों और शहरों में कुछ ऐसे ही दौड़ रही है. पानापुर की इस सभा के पहले वह इसी गांव में नरेगा का जायज़ा लेने पहुंचे थे. प्रशासन को मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम की पहले से ही ख़बर थी, लिहाज़ा तैयारी मुक्कमल कर ली गई थी. मज़दूरों से चंद सवालात और उसके माकूल जवाब से मुग्ध नीतीश अधिकारियों की ओर घूमकर बोले केंद्र सरकार कहती है हमारे यहां नरेगा में काम नहीं हो रहा है, बोलने वालों को इसी गांव में ले आना चाहिए, लेकिन नीतीश की आत्ममुग्धता को भीड़ में मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत समाप्त कर दिया. भीड़ में शामिल पानापुर का ही रामाशंकर प्रसाद अचानक चिल्ला उठा सर यहां क्या देख रहे हैं, सब पहले से सेटिंग है, विकास की सच्चाई देखनी है तो बगल में चलकर देखिए. नीतीश और उनके अधिकारी रामाशंकर की आवाज़ को पहले तो नकारने में लगे रहे, लेकिन उसका चिल्लाना जारी रहा तो नीतीश ख़ुद बोल उठे. आपके कहने पर हम वहां जाएंगे, अपना काम करिए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए. मुख्यमंत्री के इस जवाब के बाद वहां मौजूद वर्दीधारियों ने रामाशंकर को फिर से ज़ुबान खोलने तक का मौक़ा नहीं दिया. जनता देखती रह गई और नीतीश का काफ़िला वहां से आगे निकल गया.

पानापुर की ये दो घटनाएं नीतीश कुमार की बहुप्रचारित विश्वास यात्रा की हक़ीक़त उजागर करने के लिए काफी है. विश्वास यात्रा पर निकलने से पहले नीतीश ने घोषणा की थी कि अपनी यात्रा के ज़रिए वह जनता का विश्वास परखेंगे. अगर जनता ने सही शासन का भरोसा दिलाया तो ठीक नहीं तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन यात्रा के दौरान वह विश्वास की हिल रही बुनियाद को नहीं परख पाएं. नीतीश कुमार की घोषणा थी कि वह अचानक गांवों में पहुंचकर वहां का हाल लेंगे, लेकिन प्रशासन को एक सप्ताह पहले ही उनके दौरे की ख़बर मिल चुकी थी. मुख्यमंत्री किस गांव में राशन की दुकान में जाएंगे और किस गांव में स्कूल का जायज़ा लेंगे प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी पहले से थी. लिहाज़ा राशन की जिस दुकान में महीनों से ताला नहीं खुला था, उसमें नीतीश के पहुंचने से पहले आनाज की कई बोरियां लाकर रख दी गईं. विश्वास यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण के बड़हरवा लखनसेन गांव में राशन दुकान के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा घेरे के बाहर खड़ी जनता चीख-चीख कर महीनों से राशन नहीं मिलने की शिकायत करती रही, लेकिन इस चीख पुकार का नीतीश पर कोई असर नहीं पड़ा. वैसे यात्रा के दौरान इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात भी उजागर हुई. यात्रा के पहले दिन नीतीश पश्चिम चंपारण के बगही गांव में ग़रीबों की एक बस्ती में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें इंदिरा आवास के एक भी मकान पर छत नज़र नहीं आई. नीतीश इसके लिए भले ही महंगाई को दोषी बताकर चल दिए, लेकिन लोग कुछ अलग ही कहानी कह रहे थे. बगही हो या बड़हरवा लखनसेन या फिर सीतामढ़ी का अरुरिया, लोगों ने इंदिरा आवास में जमकर हो रही लूटपाट की पोल खोल दी. आम लोगों का आरोप था कि इंदिरा आवास के लिए पांच से लेकर दस हज़ार रुपये तक घूस सरेआम लिए जा रहे हैं. हाल तो यह है कि वृद्धावस्था पेंशन में भी पचास फ़ीसदी राशि घूस में ली जा रही है.

लोग इंतजार करते रहे कि जनता का विश्वास देखने निकले मुख्यमंत्री उनकी फरियाद पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सभा समाप्त होते ही नीतीश के हेलीकॉप्टर की पंखियां घुमीं और उससे निकली तेज़ हवा में जनता की फरियाद भी उड़कर कहीं गुम हो गई.

विश्वास यात्रा के पहले चरण के पहले तीन दिनों तक तो मुख्यमंत्री इन शिकायतों की अनदेखी करते रहे, लेकिन मुज़फ़्फ़रपुर में लोगों के गुस्से को परखने के बाद उनकी ज़ुबान खुली. मुज़फ़्फ़रपुर की जनसभा में मंच से ही पुलिस को इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिए, वहीं सूबे के आलाधिकारियों को महिलाओं का सेल्प हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें ही इंदिरा आवास की राशि सौंपने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने एक महीने बाद अपने निर्देशों पर हुए अमल की समीक्षा करने का भी ऐलान किया, लेकिन अधिकारियों की मनमानी को झेल रहे लोगों को भ्रष्टाचार पर रोक की आस कम ही है. यह लोगों की निराशा ही थी कि विशवास यात्रा के दौरान नीतीश ने जहां कहीं भी जनसभा की वहां उन्हें कुछ न कुछ विरोध झेलना पड़ा. आलम यह था कि मधुबनी की जनसभा में जदयू कार्यकर्ताओं ने ही नीतीश की सभा में जमकर शोर-शराबा किया. इससे पहले सीतामढ़ी में सभा की ओर जा रहे नीतीश के काफिले पर अग्निकांड के पीड़ितों ने पथराव भी किया, जिससे काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई लोगों को चोटें भी आईं. महादलित तबके से आने वाले चोटाही गांव के पांच सौ से ज़्यादा परिवारों के घर और उनकी सारी जमा पूंजी अगलगी की भेंट चढ़ गई. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर के गृह ज़िले के लोगों को राहत का चंद दाना भी नहीं मिला था. पीड़ितों ने प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई थी, लेकिन पूरा अमला नीतीश के स्वागत की तैयारियों में जुटा रहा. लिहाज़ा उन्हें कुछ भी नहीं मिला. बबार्द हो चुके लोगों ने सीएम के दौरे के दिन सड़क जाम कर सूबे के मुखिया तक अपना दर्द पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात सुनकर राहत देने के बजाय लाठियां बरसा कर उन्हें सड़क से हटा दिया. उसके बाद ही पत्थरबाज़ी की घटना हुई. दरभंगा की सभा में एक युवक ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल फेंक कर अपना विरोध जताया. हिरासत में पांच दिन रहने के बाद ज़िले के सिमरी थाना के बनौली निवासी रामबाबू को जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस युवक का कहना है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. उसने मुख्यमंत्री की जनता दरबार, राष्ट्रपति और मानवाधिकार आयोग से भी गुहार लगाई फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिला. यात्रा के दो चरणों की समाप्ति के बाद नीतीश ने जनता का भरोसा जीतने का दावा किया. बकौल नीतीश, विकास यात्रा के बाद विश्वास यात्रा ने उन्हें गुड गवर्नेंस में मदद की है. विश्वास यात्रा ने उन्हें जनता का सरकार पर भरोसा मापने का भी मौक़ा दिया और वह समझते हैं कि जनता का उनकी सरकार पर पूरा भरोसा है.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी भी विश्वास यात्रा की ऐतिहासिक सफलता के दावे कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इससे सहमत नहीं हैं. मुख्य विपक्षी दल राजद यात्रा को वनवास यात्रा करार दे रहा है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के मुताबिक़ नीतीश जनता की समस्याओं की अनदेखी कर यात्रा के ज़रिए अपना गुणगान करने में लगे हैं. विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता के आक्रोश का अहसास हो जाएगा. लालू प्रसाद विश्वास यात्रा की पोल खोलने के लिए भंडाफोड़ यात्रा शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं. वहीं लोजपा अध्यक्ष रामविलास पसवान भी नीतीश पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं. वैसे कुल मिलाकर नीतीश विश्वास यात्रा के ज़रिए विधानसभा चुनाव की अग्निपरीक्षा को पास करने की जुगत में हैं. इससे पहले चंपारण से ही उन्होंने न्याय यात्रा और विकास यात्रा निकाली थी. न्याय यात्रा के बाद वे मुख्यमंत्री बन गए तो विकास यात्रा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में भारी सफलता दिला दी. इस बार फिर चंपारण से ही विश्वास यात्रा शुरू की गई है, लेकिन इन यात्राओं में एक बड़ा अंतर भी है. न्याय और विकास यात्रा में नीतीश सड़कों पर चल कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे, पर इस बार हालात उलटा है. क्योंकि आम लोगों की पहुंच से वह दूर हैं. इसलिए इनको लेकर दिल में कड़वाहट बढ़ रही है.

feedback@chauthiduniya.com

सुनील खवाड़े की शहर में एक विशेष पहचान है. विरासत में मिली जनसेवा इनकी दिनचर्या है. खेलकूद में इनकी गहरी रुचि है, जिससे युवाओं में इनकी अच्छी पैठ है.

विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र सीपीएम की झोली में चली गई और पिछले तीन दशक से सीपीएम नेता रामदेव वर्मा वामपंथी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते रहे हैं.

नेत्रहीन इज़हारुल का हौसला

हर तरफ फैलानी है शिक्षा की रोशनी

हौसला अगर बुलंद हो और इरादे नेक़, तो कुछ भी असंभव नहीं है. यही साबित किया है नेत्रहीन मुहम्मद इज़हारुल हक़ ने. आंखों में रोशनी न सही, लेकिन शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए वह कृतसंकल्प हैं.

ए एन शिबली

यदि किसी व्यक्ति में शारीरिक कमी होती है, तो वह इसका बहाना बना कर काम करना छोड़ देता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है. विश्व में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं है, कई ऐसे हैं जिन के पांव नहीं है और कई ऐसे हैं, जो किसी न किसी शारीरिक कमी से ग्रस्त हैं और इसका बहाना बना कर ऐसे लोगों ने ख़ुद को दूसरों पर निर्भर कर लिया है. मगर, इन में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कई प्रकार की शारीरिक कमी के बावजूद न सिर्फ अपने को दूसरों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि वह दूसरों की सहायता भी कर रहे हैं. ऐसे ही लोगों में से एक हैं मुहम्मद इज़हारूल हक़. बिहार के मधुबनी ज़िले के खैरी बांका गांव के रहने वाले इज़हार साहब पूरी तरह से दोनों आंखों से अंधा होने के बावजूद ख़ुद को किसी से कम नहीं समझते. वह किसी पर निर्भर नहीं हैं. आज वह गांव में एक शानदार स्कूल चला रहे हैं और आंखों की रोशनी न होने के बावजूद दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं.

इज़हारुल हक़

इज़हार साहब के जीवन की कहानी भी काफी दिलचस्प है. मात्र छह वर्ष की आयु में दोनों आंखों से अंधा होने के बावजूद उन्होंने हिफ़्ज़ (कुरआन शरीफ को पूरा याद किया) किया और फिर जीवन में कुछ करने की ललक के चलते कोलकाता से भाग कर मुंबई चले गए.

उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं दूसरों के लिए मुसीबत नहीं बनूंगा. इसलिए उन्होंने अंधों के लिए बने इंस्टीट्यूट में तीन साल की टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल की. ट्रेनिंग के दौरान उनकी गिनती अच्छे विद्यार्थियों में होती थी. ट्रेनिंग में जब भी कोई प्रोग्राम होता तो मेहमानों का इस्तकबाल करने की जिम्मेदारी इज़हार साहब की ही होती थी. तीन साल का कोर्स पूरा करने के बाद इज़हार साहब को महिंद्र एंड महिंद्र कंपनी में नौकरी मिल गई. वह नौकरी तो करते रहे. मगर, उन के दिल में हमेशा एक चीज खटकती रही कि वह अपने गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. छुट्टियों में वह जब भी अपने गांव आते तो उन्हें यह जान कर काफ़ी अफसोस होता कि हमारे गांव के जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वह दिन भर इधर-उधर घूम रहे हैं. कोई दिन भर खेल कर अपना समय बर्बाद कर रह है, तो कोई चौक पर रह कर ही अपना जीवन खराब कर रहा है. छुट्टियां बिता कर वह मुंबई तो चले जाते मगर वहां जाकर भी इनका ध्यान सिर्फ गांव और गांव के बच्चों पर लगा रहता. उन्हें हमेशा यही चिंता सताती रहती कि बच्चों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कैसे किया जाए. ताकि वह शिक्षित हो सकें. यही सोचकर 1991 में 10 साल पहले ही रिटायरमेंट ले कर वह गांव चले आएं. यहां आकर उन्होंने अपने दरवाज़े पर ही अपने ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. इज़हार साहब की मेहनत लगन और उनकी ईमानदारी का ही नतीज़ा है कि मात्र दो टीचर और कुछ बच्चों से शुरू हुआ यह स्कूल आज इलाक़े के बेहतरीन स्कूलों में शुमार है. यह इज़हार साहब का ही कमाल है कि जिस गांव में कभी एक दो लड़की ही मैट्रिक पास करती थी, वहीं अब इस स्कूल के खुल जाने के बाद लगभग सौ लड़कियों ने मैट्रिक पास की है. कई लड़कियां इंटरमीडिएट कर रही हैं. कमाल की बात यह है कि जिन घरों में पढ़ाई का कोई रिवाज़ नहीं था और जहां के लड़के भी मैट्रिक पास नहीं थे. गांव के लोग इज़हार साहब की इस कोशिश से बहुत खुश हैं. ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि इज़हार साहब ने स्कूल खोल कर पूरे गांव पर अहसान किया है. इज़हार साहब को प्रचार नहीं चाहिए. उनके शानदार कामों की वज़ह से उन्हें ख़ुद ही प्रचार मिल रहा है. एक बार इज़हार साहब को पटना जाना था. बस वाला यात्रियों से मनमानी किराया वसूल रहा था. यह बात इज़हार साहब को उचित नहीं लगी. बस वाले की मनमानी की शिकायत करने के लिए वह पटना में दैनिक हिंदुस्तान के कार्यालय पहुंचे. वहां संपादक यह जान कर काफ़ी प्रभावित हुआ कि जो व्यक्ति दोनों आंखों से अंधा है. वह इतना जागरूक है और गांव में स्कूल भी चला रहा है. उनमें एक बड़ी ख़ूबी यह है कि वह बच्चों से सिर्फ़ उनकी शिक्षा नहीं बल्कि उनके घर के मसले भी सुनते हैं और इसका हल निकालने में मदद करते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

जहां पानी बिन रुक जाती हैं शादियां

कैमूर पहाड़ी पर रहने वाले दो बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं

दुनिया चांद पर चली गई और यहां आज भी कुछ लोग सदियों पीछे की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं. यहां तक कि जीने के लिए अति आवश्यक पानी भी लोगों को गला तर करने के लिए नसीब नहीं हो रहा है. जीहां, यह हक़ीक़त रोहतास ज़िले के दक्षिणी छोर पर स्थित कैमूर पहाड़ी पर बसे औरइया एवं भुडकुड़ा गांवों की है. जहां गर्मी शुरू होते ही लोग पहाड़ी के नीचे पलायन करने लगते हैं. नौबत यहां तक आ पहुंची है कि पहाड़ी पर बसे पूरा गांव गर्मी के दिनों में खाली हो जाता है. शादियों के मौसम में यहां की युवतियों के हाथ पीले नहीं हो पाते और ना ही युवकों के माथे पर सेहरा बंध पाता है. इसके पीछे मुख्य वजह है पानी का न मिलना. पिछले पांच वर्षों में चेनारी प्रखंड के इन दोनों गांवों में गर्मी के दिनों में होने वाली लगभग पांच दर्जन शादियां टल गईं और आधा दर्जन शादियां नहीं हो पाईं. इन परिस्थितियों में इस पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के सामने व्यवस्था को लेकर कई प्रश्न खड़े हैं. रामचंद्र चेरो की मानें तो पिछले कई वर्षों से इन दोनों गांवों के लोग मात्र एक कुएं से अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो यह कुआं भी सूख जाता है. उसके बाद ये गांव से पांच किमी दूर पश्चिमी कोने पर बहने वाली दुर्गावती नदी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं. और इसी पानी से रोजमर्रा का काम निपटाते हैं. पिछले वर्ष पेयजल की ऐसी किल्लत थी कि इस वर्ष के दर्जन से ज्यादा शादियां पानी के अभाव में टल गईं.

एक बार तो लड़के की मंगनी में आए वधु पक्ष के लोग हाथ में मिठाई का प्लेट लिए पानी का घंटों इंतज़ार करते रहे. तीन घंटे बाद मेहमानों को पानी मिला, उसके बाद मंगनी करके वापस गया वधु पक्ष आज तक शादी की रस्म अदा करने के लिए नहीं पहुंचा. पिछले दस वर्षों में इन दोनों गांवों की लगभग डेढ़ हज़ार की आबादी पेयजल की समस्या से गुज़र रही है. नन्हकू खरवार की मानें तो स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है. उन्हें व्यवस्था के नाम पर प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के तरफ से सिर्फ आश्वासनों के सिवाए कुछ भी नहीं मिलता. गांव की जागरूक महिला रामरती बताती हैं कि बगल से गुज़रने वाली दुर्गावती नदी भी सूखी हुई होती है तो हमारे यहां के सैकड़ों मवेशी पानी बिना मर जाएंगे. अब तो हमलोगों ने यह तय कर लिया है कि शादियां गांव से बाहर जाकर ही करेंगे. क्योंकि गर्मी के दिनों में गांवों में रहकर शादी करना कठिन कार्य है. कैमूर पहाड़ी पर बसे इन गांवों में 90 फ़ीसदी परिवार आदिवासी मूल के हैं और उनके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित हो रही हैं. फिर भी आज तक इन गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई. पिछले दिनों सरकार की तरफ से चापाकल लगाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन वहां पहुंचे अभियंताओं के दल ने भी हाथ खड़े कर दिए. बताया जाता है कि इन गांवों के नीचे ज़मीन में पानी ही नहीं है, केवल एक कुआं है, जो बरसाती पानी इकट्ठा होने पर लोगों के काम आता है. वरना, जब यह सूख जाता है तो समझो स्थिति और गंभीर हो जाएगी. इन दोनों गांवों के तर्ज़ पर सासाराम प्रखंड के गोरेया एवं भोरकछुआ गांव की भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां पानी के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ता है. मुसीबत यह है कि औरइया, भुडकुड़ा गांव के समीप से तो दुर्गावती नदी भी गुज़रती है, लेकिन गोरेया एवं भोरकछुआ के समीप से कोई नदी भी नहीं गुज़रती. ऐसी स्थिति में गर्मी के दिनों में यहां के लोग पलायन कर निकटवर्ती दरिगांव, करसेरुआ आदि गांव में आकर शरण लेते हैं.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

कसौटी पर वामपंथियों की ताक़त

विकास कुमार

समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास यात्रा पर आने के बाद से ज़िले की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है. मुख्यमंत्री की विश्वास यात्रा का सबसे ज़्यादा असर ज़िले के लेनिनग्राद कहे जाने वाले विभूतिपुर विधानसभा में पड़ा है. यहीं से मौजूदा सीपीएम के विधायक रामदेव वर्मा छह बार विधानसभा चुनाव जीते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के तहत होना है और पिछले 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 एवं पुन: 2005 के विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने वाले विधायक रामदेव वर्मा अभी से ही चुनावी बाधाओं को दूर करने में जुटे दिखते हैं. नए परिसीमन के अंतर्गत विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप बदल गया है, जिसमें उजियारपुर संसदीय क्षेत्र की बल्कि कोलकाता और दिल्ली की राजनीति में विशेष रूप से रहता है.

इस बार मौजूदा विधायक के साथ-साथ पुराने प्रतिद्वंद्वी पूर्व कांग्रेसी विधायक चंद्रबली ठाकुर भी पूरे दमखम से चुनौती देने हेतु कमर कस ली है और वह पूरे क्षेत्र में घूम-घूमकर राहुल गांधी का पाठ लोगों को पढ़ा रहे हैं. 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर ने सीपीएम नेता रामदेव वर्मा को शिकस्त दी थी. इसके बाद पूर्व विधायक चंद्रबली ठाकुर वर्ष 2005 में दल बदलकर भाजपा के टिकट पर विभूतिपुर विधानसभा से किस्मत आजमाया लेकिन ज़िले में वामपंथियों का गढ़ कहे जानेवाले विभूतिपुर में वे फिर से मात खा गए. इस बार पूर्व विधायक श्री ठाकुर कांग्रेस की अकेले चलने की नीति से प्रभावित होकर फिर से पुराने घर कांग्रेस में लौट आए हैं. इन्हें चुनाव लड़ने हेतु बिहार कांग्रेस के प्रभारी जगदीश टाईटलर से लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा की हरी झंडी मिल चुकी है.

ज़िले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही वामपंथियों के

रामबालक सिंह | रामदेव वर्मा | सुशील कुमार सिंह

विधानसभा क्षेत्र विभूतिपुर

जदयू सांसद अश्वमेध देवी की प्रभावकारी भूमिका विशेष रूप से चर्चा में है. नए परिसीमन के तहत उजियारपुर ज़िले में नए संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ है, जिसमें नए उजियारपुर के साथ ही विभूतिपुर विधानसभा का नए सिरे से गठन किया गया है. नए परिसीमन में पूर्व दलसिंह सराय विधानसभा को समाप्त कर दलसिंहसराय प्रखंड के बुलाकीपुर, कमरांव, मालपुर पुरवारी पट्टी, रामपुर जलालपुर, बंबैया हरलाल और अजनौल ग्राम पंचायत को विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है. इसके अलावा विभूतिपुर प्रखंड के सभी 29 पंचायतों भरपुरा पटपारा, बाजितपुर बंबैया, मेहिशी, केराय, चकहबीब, मुस्तफापुर, कल्याणपुर उत्तर, मुहम्मदपुर सकड़ा, टभका, खास टभका उत्तर, खास टभका दक्षिण, चोरा टभका, सुरौली, गंगौली मंदा, साखमोहन, देसरी करंख, पतैलिया, भुसवर, विभूतिपुर उत्तर, विभूतिपुर दक्षिण, नरहन, बोरिया, महथी दक्षिण, महथी उत्तर, सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण, सिंघिया बुजुर्ग उत्तर, बेलसंडी तारा, आलमपुर कोदरिया, कल्याणपुर दक्षिण को मिलाकर विभूतिपुर विधानसभा का गठन किया गया है.

नए परिसीमन के तहत होने वाले चुनाव में मौजूदा सीपीएम विधायक रामदेव वर्मा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी रहे लोजपा के रामबालक सिंह कुशवाहा इस बार लोजपा को अलविदा कह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहती विकास धारा में शामिल हो गए हैं और विभूतिपुर क्षेत्र से इनकी चर्चा सत्ताधारी राजग गठबंधन के प्रबल टिकटार्थियों में हो रही है. पिछले सभी चुनावी जंग को फतह करने वाले मौजूदा विधायक रामदेव वर्मा बिहार की राजनीति में सीपीएम के इकलौते विधायक हैं. उनके समर्थन में पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं एवं प्रकोष्ठों के नेताओं का विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में दौरा और आमसभा आयोजित होती रहती है. क्योंकि वामपंथी मोर्चा ने ज़िले के विभूतिपूर क्षेत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रतिष्ठा की सीट मान रखी है. वामपंथी राजनीति में विभूतिपुर विधानसभा का महत्व न केवल पटना गढ़ के रूप में जाना जाता है जहां से कभी राज्य के प्रसिद्ध शिक्षाविद् प्रो. परमानंद सिंह मदन विधायक हुआ करते थे. लेकिन बाद में वामपंथी एकता के नाम पर विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र सीपीएम की झोली में चली गई और पिछले तीन दशक से सीपीएम नेता रामदेव वर्मा वामपंथी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते रहे और उन्हें छह बार जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. जब कभी ज़िले में वामपंथी मोर्चा उम्मीदवार संसदीय चुनाव लड़े हैं तो सीपीएम विधायक रामदेव वर्मा को ही वामपंथी मोर्चा ने मैदान में उतारा है. पिछले संसदीय चुनाव में भी नवगठित उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से वाममोर्चा की ओर से रामदेव वर्मा ने किस्मत को आजमाया था लेकिन जदयू सांसद अश्वमेघ देवी ने नवगठित सीट जीतकर ज़िले की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त किया. जदयू सांसद ने सीपीएम विधायक रामदेव वर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी प्रो.शील कुमार राय सहित राजद के निकटतम प्रतिद्वंद्वी पूर्व सांसद एवं युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मेहता को पराजित कर ज़िले की राजनीति में महिला सशक्तिकरण अभियान में तेजी ला दी.

पिछले चुनाव में मौजूदा विधायक रामदेव वर्मा के निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे जदयू नेता रामबालक सिंह कुशवाहा के इर्द-गिर्द विभूतिपुर की राजनीति घूम रही है. रामबालक सिंह ने लगातार दो चुनावों से सीपीएम विधायक रामदेव वर्मा को कड़ी चुनौती दिया है पर मामूली वोटों के अंतर से चूक जाते हैं. राजद-लोजपा का वामदलों से हो रही निकटता को देखते हुए रामबालक सिंह पिछले 27 अप्रैल को पटना में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी एवं विधि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रामनाथ ठाकुर की उपस्थिति में जदयू की सदस्यता ग्रहण की. इनके जदयू में आने से विभूतिपुर की राजनीति में भारी उलटफेर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. जदयू प्रत्याशी बनकर रामबालक सिंह वामपंथियों के मजबूत किले को ध्वस्त करने की कवायद में जुट गए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

ऑरकुट पर बाहुबली

दिव्या कुमारी

अपराध की दुनिया में कभी अपना जौहर दिखाने वाले कालांतर में राजनीति में भी अपनी चमक दिखाने लगे हैं. बाहुबल और राजनीति के इन चर्चित चेहरों ने अब इंटरनेट की दुनिया में भी अपनी चमक दिखानी शुरू कर दी है. हैरानी की बात तो यह है कि इनके समर्थक इन्हें न सिर्फ़ रॉबिनहुड के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, बल्कि एक अलग व्यक्तित्व भी बताते हैं. इंटरनेट की दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट ऑरकुट पर भी बाहुबली नेताओं का जलवा है. इन बाहुबलियों के समर्थक सदस्य बिहार की सीमा से बाहर के तो हैं ही. ये विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए भी नायक बने हुए हैं. अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, शाहाबुद्दीन, प्रभुनाथ सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडेय सरीखे बाहुबली नेताओं के नाम से ऑरकुट में कम्युनिटी बनी है. इन बाहुबली नेताओं के समर्थकों द्वारा बनाई गई कम्युनिटी में सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. बाहुबल के धनी ये चेहरे भले ही ऑरकुट से अंजान हैं, लेकिन उनके समर्थकों ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है. लालगंज के जदयू विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बलिया के पूर्व लोजपा सांसद सूरजभान सिंह और महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के नाम से दो-दो कम्युनिटियां बनी हुई हैं. मगर, बात यदि समर्थक सदस्यों की करें तो मोकामा विधायक अनंत सिंह सब पर भारी हैं. उनकी कम्युनिटी में समर्थक सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है. अनंत सिंह के बाद दूसरे स्थान पर सीवान जेल में वर्षों से कैद पूर्व सांसद शाहाबुद्दीन का नाम आता है. डेहरी-ऑन-सोन के संतोष द्वारा बनाई गई कम्युनिटी में अनंत सिंह की तुलना महर्षि वाल्मीकि से की गई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि उनके अतीत से इनके समर्थकों का कोई लेना-देना नहीं है. अनंत सिंह के नाम पर बनी कम्युनिटी में सदस्यों की संख्या 160 है. अनंत सिंह के नाम पर बनी कम्युनिटी में तीन लड़कियां भी सदस्य हैं और यूपी, राजस्थान, दिल्ली के लोगों सहित एक अप्रवासी भारतीय भी उनकी कम्युनिटी सदस्यों की सूची में शामिल है. शाहाबुद्दीन को सीवान का शेर बताने वाली कम्युनिटी में कुल 156 सदस्य हैं. उनके समर्थक सदस्यों की संख्या भले ही अनंत सिंह से कम है, लेकिल उनके समर्थक सदस्य भारत से बाहर के भी हैं जैसे दोहा, कतर, अल-सोबर, सऊदी अरब, अमेरिका में रहने वाले आदि. शाहाबुद्दीन के बारे में बताया गया है कि वह सीवान के लिए जीते हैं तथा उन्हें सीवान का गौरव बताया गया है. शाहाबुद्दीन के समर्थकों ने एक बहस भी छेड़ रखी है कि अन्य बाहुबली पर शिकंजा उतना ज़्यादा नहीं कसा जा रहा है, जितना शाहाबुद्दीन पर. उन्हें जान बूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है. महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह तो एक नए अंदाज़ में ही ऑरकुट पर नज़र आते हैं. छपरा के सुधीर सिंह द्वारा बनाई गई कम्युनिटी में प्रभुनाथ को सारण का मुख्यमंत्री बताया गया है. इस कम्युनिटी में कुल 27 सदस्य हैं तथा उनकी राय है कि प्रभुनाथ ने सारण का मान-सम्मान बढ़ाया है. प्रभुनाथ के नाम पर एक अन्य कम्युनिटी मशरक के सोनू कुमार ने बना रखी है. 56 सदस्यों की संख्या वाली इस कम्युनिटी में प्रभुनाथ के उस क़दम की प्रशंसा की गई है, जिसमें उन्होंने ग़रीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने की वकालत की थी. पीरो के बाहुबली विधायक सुनील पांडेय के नाम पर बनी ऑरकुट

कम्युनिटी में कुल 49 सदस्य हैं. सुनील पांडेय को शहाबाद का गौरव बताया गया है. मोकामा निवासी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के नाम पर ऑरकुट में दो कम्युनिटी बनी है. छप्पन सदस्यों वाली कम्युनिटी में सूरजभान को महान व्यक्तित्व और दादा तुस्सी ग्रेट हो जैसे जुमलों से भी नवाजा गया है. लालगंज विधायक मुन्ना शुक्ला के नाम पर बनी दो कम्युनिटियों में उन्हें किंग ऑफ वैशाली भी कहा गया है. मुन्ना शुक्ला के समर्थकों की राय है कि उनके कारण वैशाली की प्रतिष्ठा बढ़ी है. मुन्ना शुक्ला भी इस कम्युनिटी के सदस्य हैं. इन बाहुबली नेताओं के इतर एक नई कम्युनिटी में मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है. सर्च इंजन गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट ऑरकुट पर बाहुबली नेताओं का जलवा बदस्तूर जारी है. ऑरकुट के इन नायकों को ऑरकुट पर हीरो मान कर बतौर रॉबिनहुड प्रस्तुत किया जा रहा है. यह विस्मित करने वाली बात है कि इनके अतीत की चर्चा करने की बात तो दूर साथ ही साथ साफ तौर पर यह कह दिया गया कि उनके अतीत से उनलोगों को कोई मतलब नहीं. यह स्थिति तब है जब विचारों की अभिव्यक्ति के इस माध्यम पर पढ़े-लिखे तबकों की पहुंच है.

feedback@chauthiduniya.com

मेयर एवं डिप्टी मेयर के लिए होगा घमासान

नवगठित देवघर नगर निगम के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज़ हो गई हैं. ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न कोषांगों का गठन एवं सभी तैयारी कर ली गई. राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ऐ के मंडल भी ज़िले के अधिकारियों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. नगर निगम के तहत कुल 35 वार्ड हैं. जहां 159 बूथों पर कुल एक लाख 27 हज़ार 582 मतदाता मत देकर पहली बार मेयर, डिप्टी मेयर एवं वार्ड आयुक्त को चुनेंगे. मेयर एवं डिप्टी मेयर पद को अनारक्षित रखा गया है. वार्ड आयुक्तों में एससी को 4, ओबीसी को 13 एवं महिलाओं के लिए 13 सीट आरक्षित किया गया है. उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा मतगणना में 23 जून को खुलेगा. ग़ौरतलब है कि इससे पहले 17 वर्ष पूर्व नगरपालिका का चुनाव हुआ था.
नगर निगम की गठन प्रक्रिया प्रारंभ से ही विवादों में रहा है. शहर के चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया है, विभिन्न तरह के टैक्स के चलते ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है. ज़िले के सदर प्रखंड अंतर्गत रोहिणी गांव के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में नगर निगम के विरोध में याचिका दायर की है, जिसे न्यायालय में स्वीकार भी किया जा चुका है. न्यायालय की ओर से नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी को नोटिस भी दिया गया है, जिसका जवाब न्यायालय को दिया गया है.

देवघर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसके कारण यहां चुनावी तापमान कम ही चढ़ता है. लेकिन नगर निगम चुनाव के लिए मेयर एवं डिप्टी मेयर पद को अनारक्षित रखा गया है. जिसके चलते दोनों पदों हेतु चुनाव अतिसंवेदनशील एवं तनावपूर्ण माहौल में होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. सर्वाधिक रोचक मुक़ाबला मेयर पद हेतु होता दिख रहा है, जिसमें शहर के कई चर्चित व दबंग चेहरे मैदान ए जंग में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. अपने अपने क्षेत्रों में शीर्षस्थ रहे सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध शिक्षाविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, चिकित्सक, राजनिति से जुड़े चेहरे के साथ-साथ शहर की दबंग हस्तियां भी अपना भाग्य आजमाने में पसीना बहा रहे हैं. जिसके कारण मेयर पद हेतु मुक़ाबला बहुकोणीय होता दिख रहा है. शहर में विकास की गंगा बहाने, कायाकल्प करने, लगभग सभी समस्याओं का निदान करने तथा हमेशा ही जनता की सेवा में तत्पर रहने जैसे बयान उम्मीदवारों की ओर से आम जनता को देने का क्रम जारी है. वैसे धार्मिक नगरी बाबाधाम हमेशा से ही शांत शहर रहा है. यहां सभी जाति व धर्म के लोग आपस में मिलजुलकर सालोंभर लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं. अधिकांश मतदाताओं के अनुसार नगर निगम चुनाव में स्वच्छ छवि, शिक्षित, ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार ही सभी पर भारी पड़ेंगे. अप्रत्यक्ष रूप से राजनितिक प्रभावों की भूमिका भी दिख रही है. मेयर पद के लिए उम्मीदवारों में शिक्षाविद् एवं खेलकूद के जानेमाने हस्ती युद्धिष्ठिर प्रसाद राय सरल स्वभाव एवं स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं. प्रशासनिक विभागों में इनकी अच्छी पहचान है. शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सिंह झाविमो बुद्धिजीवी मंच के ज़िलाध्यक्ष हैं तथा इनकी पहचान गणमान्य नागरिकों में होती है. उनके पास नगरपालिका आयुक्त का लंबा अनुभव भी है. समाजसेवी सुनील खवाड़े की पहचान हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित रही है. ग़रीबों की बेटी की शादी हो या जटिल रोग से पीड़ित असमर्थ का इलाज, पढ़ने वाले ग़रीब विद्यार्थी को हर तरह की सहायता आदि में इनकी भूमिका देखी गई है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े हाल में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में 40 हज़ार वोट लाकर सबको चौंका दिया था. शहर में उनके समर्थकों की भी लंबी फौज है. जाने माने चिकित्सक व झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता डॉ. संजय, अधिवक्ता संघ के सचिव एवं पूर्व नगरपालिका चेयरमैन प्रणय कुमार सिन्हा सहित दर्जनों उम्मीदवार मैदान में डटे हैं. देखना है शहर की जनता नगर निगम का पहला मेयर का ताज किसे पहनाती है.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

जूते भी पॉलिश किए सुनील खवाड़े ने

मेयर पद के उम्मीदवार सुनील खवाड़े की शहर में एक विशेष पहचान है. विरासत में मिली जनसेवा इनकी दिनचर्या है. युवा एवं चुस्त-दुरुस्त खवाड़े को खेलकूद में गहरी रुचि है, जिससे युवाओं में इनकी अच्छी पैठ है. किसी प्रकार के खेलकूद का आयोजन हो खवाड़े की सहभागिता अवश्य ही देखी जा सकती है. हाल के दिनों में क्षेत्र के ग़रीब एवं असहायों की बेटी की शादी में उनकी ओर से हरसंभव सहायता को सभी ने देखा. कुछ महीने पूर्व शहर के एक युवक जिसका किडनी खराब हो चुका था और उसके समुचित इलाज में परिजन असमर्थ थे. उस युवक ने अखबार के माध्यम से जीने की इच्छा जताई, तभी खवाड़े ने उक्त युवक की जान बचाने की हर संभव कोशिश की ठानी और शहर के मुख्य स्थल टावर चौक पर इलाज हेतु धन संग्रह में लोंगो के जूते पॉलिश किए, साथ ही लोंगो से सहायता का आग्रह भी किया. परिणामस्वरुप आवश्यक धन संग्रह करके उक्त रोगी को इलाज हेतु चंडीगढ़ भेजा गया, जहां उसका सफल ऑपरेशन संपन्न हुआ.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 31 मई–6 जून 2010

ख़ूबसूरत बाला शीला बहुत जल्द ही मार्केटिंग के सारे गुर भी सीख गई हैं. तभी तो वह मुख्य भूमिकाओं के अलावा आइटम नंबर के भी ऑफर स्वीकार कर रही हैं.

हाथी अब साथी नहीं, आफत बने

नवल किशोर सिंह

जंगलों की बेतहाशा कटाई के कारण वन्यजीवों के लिए भोज्य सामग्री और पेयजल का अभाव हो गया है. नतीजतन भूख और प्यास से बेहाल पशु जंगल से निकलकर बस्तियों में चले आते हैं. और अपने स्वभाव के अनुरूप जान-माल का नुक़सान पहुंचाते हैं. लोग वन्यपशुओं को भगाने के लिए ढोल-नगाड़े से लेकर पटाखों तक का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते ख़ौफ़ से ये पशु इधर-उधर भागते हैं. इसी क्रम में वे लोगों को नुक़सान भी पहुंचाते हैं, जिससे उनके अंदर लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण और हिंसक प्रवृति में इज़ाफ़ा होता है. झारखंड के वनबहुल इलाक़ों से लगी बस्तियों में रहने वाले लोग ख़ासतौर पर हाथियों, भेड़ियों, लकड़बघ्घों जैसे वन्यजीवों से ज़्यादा परेशान रहते हैं. सिर्फ़ हाथियों ने ही पिछले दस वर्षों के अंदर 745 लोगों को मौत की नींद सुला दिया.

आए दिन मानव बस्तियों में उनके झुंड के झुंड पहुंचने, खेतों में लगी फसलों को कुचल डालने, घरों को ध्वस्त करने और मनुष्यों को कुचल कर मार डालने की ख़बरें प्रकाश में आती रहती है.

हाथियों के हमले से होने वाले नुक़सान के एवज़ में सरकार द्वारा मुआवज़ा देने का प्रावधान है. संयुक्त बिहार के जमाने से मार्च 2010 तक हाथियों के हमले से मारे गए लोगों, घायलों, बर्बाद हुई फसलों, मवेशियों, घरों और अनाजों की क्षति पर सरकार ने मुआवज़ा के तौर पर 1546.86 लाख रुपये की अदायगी की थी, जबकि 10.58 लाख मुआवज़ा की राशि बकाया थी. राज्य निर्माण के बाद से मार्च 2010 तक 708.83 लाख मुआवज़ा दिया गया, जबकि 4.75 लाख मुआवज़ा की राशि बकाया है. ग़ौरतलब है कि जंगली जानवरों के हमले से मौत होने पर सरकार द्वारा मुआवज़ा के तौर पर वयस्कों को एक लाख रुपये, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत पर 50 हज़ार रुपये दिए जाते हैं. यही राशि घायलों पर है, जबकि गंभीर रूप से घायल वयस्कों के लिए 33 हज़ार 333 रुपये और नाबालिगों के लिए 16 हज़ार 666 रुपये मुआवज़ा देने का प्रावधान है.

हाथियों के हमले के प्रति संवेदनशील इलाक़ों में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, देवघर, जामताड़ा, सरायकेला, खरसांवा, धालभूमगढ़, पलामू प्रमंडल के सभी ज़िले, बोकारो का कसमार प्रखंड, हजारीबाग, रामगढ़ सहित कोल्हान प्रमंडल के कई क्षेत्र शामिल हैं.

पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 में हाथियों से झारखंड में लगभग 56 लोगों की मौत हो गई. रांची पूर्व में 15, खूंटी में सात, रांची पश्चिम में एक, गुमला में छह, सिमडेगा में तीन, भू-संरक्षण प्रमंडल देवघर में चार, जामताड़ा में एक, पोडैयाहाट में एक, सरायकेला-खरसांवा में चार, धालभूम में एक, गढ़वा दक्षिणी में एक, डाल्टेनगंज उत्तरी में एक, बोकारो में एक, रामगढ में दो, व्याघ्र योजना पलामू में चार, वन प्राणी प्रमंडल रांची में दो मौतें शामिल है. इसी प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष में हाथियों ने क़रीब 164 लोगों को घायल कर दिया. रांची पूर्वी में 52, खूंटी में नौ, रांची पश्चिम में पांच, गुमला में 13, सिमडेगा में 12, अजय भू-संरक्षण प्रमंडल देवघर में सात, सारंडा में एक, सरायकेला-खरसांवा में तीन, चाईबासा दक्षिणी में 13, धालभूम में एक, लातेहार एवं गढ़वा दक्षिणी में एक-एक, डाल्टेनगंज उत्तरी में तीन, हजारीबाग पश्चिम में तीन, कोडरमा एवं बोकारो में 10-10, रामगढ में तीन, व्याघ्र योजना पलामू में 10, वन प्राणी प्रमंडल में सात लोग घायलों में शामिल हैं. घायलों को मुआवज़ा के तौर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्माण के बाद से मार्च 2010 तक 200.45 लाख रुपये दिए गए, जबकि 4.76 लाख रुपये बकाया है. इसी प्रकार मार्च 2010 तक हाथियों के कारण फसल, पशु, मकान एवं अनाज क्षति के 64242 मामले आए, जिसके एवज़ में मुआवज़ा के तौर पर 637.58 लाख रुपये का भुगतान किया गया. केंद्र सरकार मनुष्य और वन्यपशुओं के संबंधों को बेहतर बनाने और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन झारखंड के नौकरशाह इस दिशा में उदासीन है. हाल ही में केंद्र सरकार ने वन्य जीवन के संरक्षण के लिए करोड़ों की राशि आवंटित की, लेकिन उस राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका है, जो राशि ख़र्च की गई उसका उपयोग प्रमाणपत्र विभाग को नहीं भेजा गया. प्रमाणपत्र के अभाव में अगले आवंटन की प्रक्रिया भी बाधित हुई. केंद्र ने दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के लिए 25.33 लाख की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 18 लाख रुपये उपलब्ध भी करा दिए गए थे. इससे आश्रयणी के चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर लगना था और आश्रयणी के अंदर ही हाथियों के लिए भोजन मुहैया कराने की व्यवस्था करनी थी, ताकि हाथी बस्तियों में प्रवेश न करें और उन्हें उत्पात मचाने से रोका जा सके, लेकिन इस योजना की सिर्फ़ खानापूर्ति ही की गई. इसी तरह हजारीबाग वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 17 लाख, महुआडांड़ भेड़िया आश्रयणी के लिए 13 लाख, तोपचांची वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 7.60 लाख, कोडरमा वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 11.19 लाख, उधवा झील पक्षी अभयारण्य के लिए 5.64 लाख, पारसनाथ वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 4.60 लाख. लावालौंग वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 8.36 लाख, गौतम बुद्ध वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 7.29 लाख और पालकोट वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए 13.71 लाख की राशि आवंटित की गई थी. मगर, आवंटित राशियों का सदुपयोग नहीं हो पाया. जिसके चलते समस्या जस की तस बनी हुई है. रांची के सांसद सुबोधकांत सहाय, मांडर के विधायक बंधु तिर्की सहित कई जनप्रतिनिधियों ने वन्य पशुओं से पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने और हर तरह से सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते रहे. मुआवज़ा अदायगी की पेचीदी प्रक्रिया के कारण कई बार उन्हें जनांदोलन का भी सहारा लेना पड़ा.

feedback@chauthiduniya.com

शीला का मेकओवर

शीला अपने किरदारों को लेकर कई प्रयोग कर रही हैं.

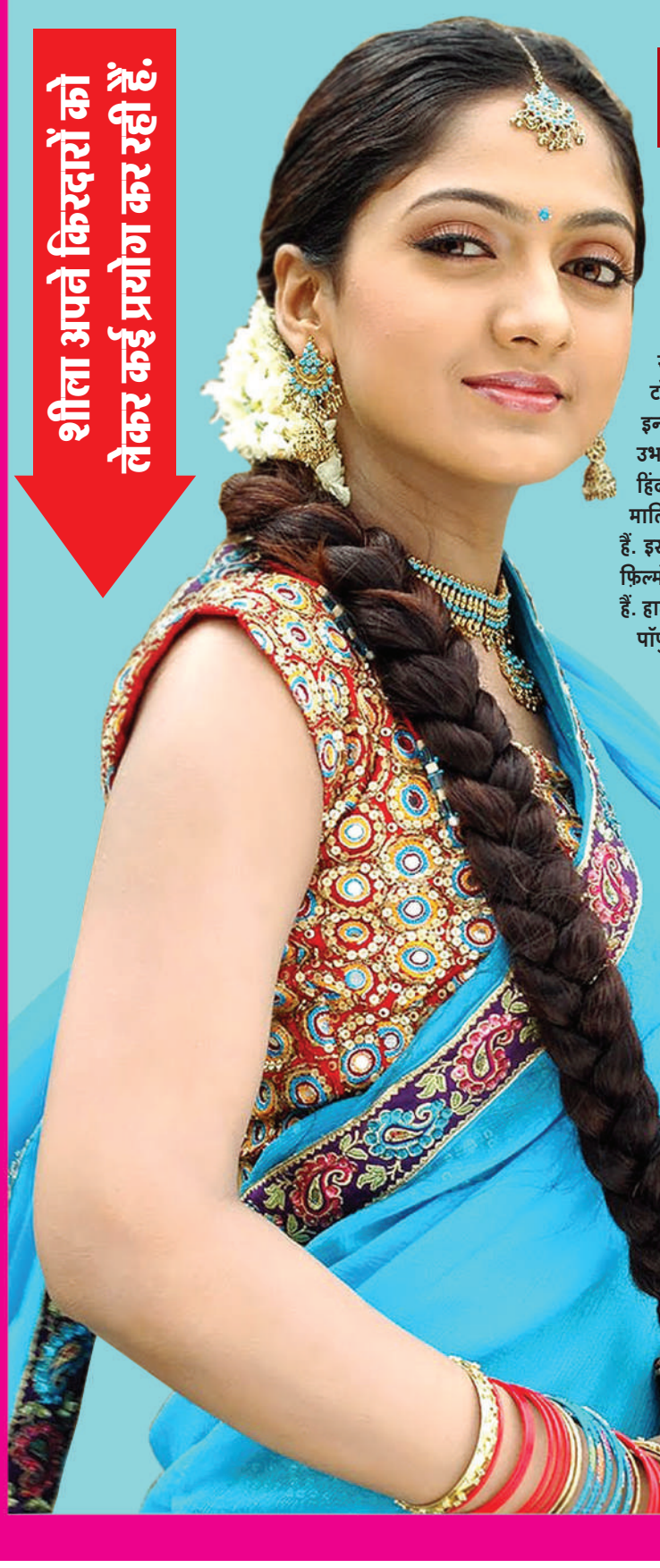

एक दौर था जब साउथ समेत लगभग सभी क्षेत्रीय फ़िल्मों के कलाकारों को हिंदी फ़िल्मों में काम करने का क्रेज था. नतीजतन, अधिकतर कलाकार हिंदी फ़िल्मों में वक्त-बेवक्त अपनी क़िस्मत आजमाते रहते थे. कुछ को इसमें सफलता भी मिलती थी, लेकिन ज़्यादातार का रिकॉर्ड निगेटिव ही रहा. रिकॉर्ड भले ही कुछ भी रहा हो पर इस तरह के चलन से एक बात तय हो जाती है कि अधिकतर कलाकार हिंदी फ़िल्मों को ही स्टारडम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझते हैं. समय बदला और बॉलीवुड के साथ-साथ टॉलीवुड और लॉलीवुड जैसी कई इंडस्ट्री पनपने लगीं. इन्हीं नई इंडस्ट्रीज में भोजपुरी सिनेमा बहुत तेज़ी से उभरा. आज आलम यह है कि भोजपुरिया फ़िल्मों में हिंदी फ़िल्मों के सुपरस्टार बिग बी, मिथुन और हेमा मालिनी से लेकर साउथ सुंदरी नगमा तक काम कर रही हैं. इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है. भोजपुरी फ़िल्मों में अपने हुस्न और अभिनय का जादू बिखेर रही हैं. हाल ही में उनका भोजपुरी सेक्सी आइटम नंबर काफ़ी पॉपुलर हुआ है. उनकी फ़िल्में भी ठीक-ठाक बिज़नेस कर रही हैं. और तो और भोजपुरी फ़िल्मों के अलावा उनकी तमिल फ़िल्म परूगु भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. ख़ूबसूरत बाला शीला बहुत जल्द ही मार्केटिंग के सारे गुर भी सीख गई हैं. तभी तो वह मुख्य भूमिकाओं के अलावा आइटम नंबर के भी ऑफर स्वीकार कर रही हैं. साथ-साथ साइनिंग अमाउंट भी बढ़ाती जा रही हैं. यह तो थी मार्केटिंग की बात. मार्केटिंग के अलावा शीला अपने किरदारों को लेकर भी कई प्रयोग कर रही हैं. अभी तक अपनी गर्लनेक्स्ट डोर की छवि में क़ैद शीला बोल्ड किरदार निभाने के लिए भी तैयार हैं. हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में शीला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपने स्टारडम के मुताबिक़ ही फीस ले रही हैं. और रही बात बोल्ड किरदार की, तो यह समय की मांग है. आजकल की कहानियों में बोल्ड किरदारों की मांग होती है, हम कैसे मना कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ISO 9001:2000 Certified

World Standard Quality Now Available in India

Italian International Paints

Long Life for Paints & Walls

ITALIAN Wall Putty

* Made from DPMC
* Marvelous White
* Super Smoothness
* 100% Damp proof
* 100% Crack proof
* World Class Packing

World Standard ITALIAN Decorative Premium WHITE CEMENT

welcome

ITALIAN International Paints.
Plot No.8, 2nd Floor, Nitin Palace,
CHANDKHEDA, Near-O.N.G.C.IRS,
Ahmedabad,Pin-382424(Gujarat)

Slight Costly but Superior

Fax No.079-23972402 / 033-25224090